वैश्विक संवाद

14.2

अनेक भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

समाजशास्त्र पर बातचीत साड़ी हनाफी के साथ

थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग
हेले हैग्लुंड

दक्षिण–दक्षिण सहयोग और नस्लीकरण

कैरोलिना वेस्टेना
एरिक सेजने
मैरी स्टिलर
रूस विसर
क्रिस्टीन हेट्जकी
सारा वॉन बिलरबेक
केसेनिया ओक्सामित्ना

वैश्विक न्याय के रूप में डीग्रोथ और उत्तर–निष्कर्षणवाद

मिरियम लैंग
बेंगी अकबुलुत
तातियाना रोआ एवेन्डानो
पाब्लो बर्टिनाट
जो रैंड्रियामारो

ओपन मूवमेंट्स

एना सिल्विया मोनजोन
कारमेन गेमिटा ओयारजो विडाल
जूलियन रेबन
कार्लोस डी जेसुस गोमेज–अबार्का

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

नादिया बौ अली
रे ब्रासियर

खुला अनुभाग

> विनियोजन या उपयोग? श्रम संघर्षों का पारिस्थितिक आयाम
> मध्य पूर्व का डिजिटल दोहरा बंधन
> गाजा शिक्षाविदों द्वारा खुला पत्र

पत्रिका

International Sociological Association

GD
अंक 14 / क्रमांक 2 / अगस्त 2024
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

> सम्पादकीय

जिस समय हम वैश्विक संवाद के इस अंक को पूरा कर रहे थे, गाजा खंडहर बन गया था । हम अपनी नजरें नहीं फेर सकते हैं। यही कारण है कि यह अंक गाजा में युद्ध के साथ शुरू और खत्म होता है। हमारे नियमित साक्षात्कार में, नॉर्वे के समाजशास्त्री थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग और हेले हैग्लंड ने पूर्व आईएसए अध्यक्ष सारी हनाफी का साक्षात्कार किया। एक सीरियाई–फिलिस्तीनी के रूप में, हनाफी दूसरे इंतिफादा, अल–अक्सा इंतिफादा के दौरान फिलिस्तीन में रहते थे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जिसे वे 'स्पेसियो–साइडल' इजरायली परियोजना कहते हैं, उसके तहत रहना कैसा होता है, को अनुभव किया। इस बातचीत में, वे गाजा में चल रहे युद्ध पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इजरायली संस्थानों के संस्थागत बहिष्कार का आह्वान करते हैं, और युद्ध की कुछ सामान्य व्याख्याओं पर चर्चा करते हैं जिन्हें वे अपर्याप्त या गलत मानते हैं।

इस अंक में, दो विषयगत खंडों का केंद्र दक्षिण–दक्षिण और उत्तर–दक्षिण संबंध हैं। कैरोलिना वेस्टेना, एरिक सेजने और मैरी स्टिलर द्वारा आयोजित पहले खंड में, दक्षिण–दक्षिण सहयोग को पदानुक्रम और नस्लीयकरण की गतिशीलता के माध्यम से जांचा जाता है। उनका तर्क है कि वैश्विक सहयोग चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के अंतर्गत वर्चस्व के व्यापक रूपों को देखना महत्वपूर्ण है। इस खंड के लेख सममित सहयोग और पारस्परिक सहायता के विचारों से परे जाकर ऐसा करने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से, वे चर्चा करते हैं कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग का वास्तविक जीवन का अनुभव नस्लीयकरण के पारस्परिक और संस्थागत रूपों द्वारा कैसे चिह्नित किया जाता है।

आगामी खंड वैश्विक उत्तर में डीग्रोथ और वैश्विक दक्षिण से पोस्ट–एक्स्ट्रेक्टिविस्ट विकल्पों के बीच तालमेल की संभावनाओं का पता लगाता है। एक साथ लिया जाए तो इस खंड के विभिन्न लेख वैश्विक विषमता और उत्तर–दक्षिण संबंध, हरित विकास के खिलाफ गैर–औपनिवेशिक वैश्विक गठबंधन, 'न्यायसंगत पारिस्थितिक–सामाजिक संक्रमण' के ढांचे को चुनौती देने की आवश्यकता या जमीनी स्तर पर ऊर्जा संक्रमण के निर्माण के विभिन्न रास्ते, और एक गैर–औपनिवेशिक जलवायु न्याय आंदोलन जैसे मुद्दों का पता लगाते हैं, जिसमें पूंजीवाद के विकल्प और जीवन की रक्षा इसके केंद्र में है। यह खंड दक्षिण के पारिस्थितिक सामाजिक समझौते और वैश्विक दक्षिण और उत्तर में इसके सहयोगियों द्वारा किए गए व्यापक संवादों से प्रेरित है, जैसा कि पुस्तक *द जियोपॉलिटिक्स ऑफ ग्रीन कोलोनियलिज्मः ग्लोबल जस्टिस एंड इकोसोशल ट्रांजिशन* में दर्शाया गया है।

''खुले आंदोलन'' खंड चार लैटिन अमेरिकी देशों में समकालीन राजनीतिक प्रक्रियाओं में विरोध और सामाजिक आंदोलनों की भूमिका का अवलोकन प्रस्तुत करता है। ग्वाटेमाला में, एना सिल्विया मोनजोन ने परीक्षण किया कि कैसे स्वदेशी और लोकप्रिय नायकत्व वर्तमान प्रगतिशील राष्ट्रपति, समाजशास्त्री बर्नार्डो एरेवलो के चुनाव के लिए एक प्रमुख विशेषता रही है। चिली के मामले में, कारमेन गेमिटा ओयार्जो घटक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न परिवर्तन की अपेक्षाओं, इसकी हार के कारणों और आंदोलनों के बाद के पुनर्गठन पर चर्चा करती है। इसके अलावा, जूलियन रेबोन अपने कार्यकाल के पहले सौ दिनों के दौरान माइली के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत का विश्लेषण करते हैं, जबकि जेसुस गोमेज–अबार्का अयोत्जिनापा में गायब हुए 43 छात्रों के मामले के माध्यम से मेक्सिको में दस साल की दंडमुक्ति का जायजा लेते हैं।

सैद्धांतिक खंड में, नादिया बौ अली और रे ब्रासियर बेरोजगार लोगों की विशेषता के रूप में '' अधिशेष आबादी'' की धारणा पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह मूल लेख यहाँ अल्मेडा संस्थान के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जा रहा है।

अंत में, हमारे ''ओपन सेक्शन'' में, साइमन शॉप चर्चा करते हैं कि श्रम संघर्ष हमें पूंजीवादी श्रम प्रक्रिया और पारिस्थितिक संकट के बीच संबंधों के बारे में क्या सिखा सकते हैं, जबकि कतर के समाजशास्त्री मोहम्मद जायनी और जो एफ. खलील मध्य पूर्व में डिजिटल परिवर्तनों के कुछ मुख्य रुझान और परिणाम प्रस्तुत करते हैं। नवीनतम लेख एक आह्वान है – शायद उससे भी अधिक, एक जयघोष – जिस पर 158 फिलिस्तीनी शिक्षाविदों और गाजा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। वे दुनिया भर के शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों से इजरायल के 'विद्वानों की हत्या' के अभियान का विरोध करने और अपने विश्वविद्यालयों का पुनर्निर्माण करने में मदद करने का आह्वान करते हैं। जैसा कि सारी हनाफी ने इस अंक के शुरुआती साक्षात्कार में कहा, विद्वानों और शैक्षणिक संस्थानों की एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम पदानुक्रम और औपनिवेशिक और सत्तावादी शक्तियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कोई वैश्विक संवाद वास्तव में संभव नहीं है।■

ब्रेनो ब्रिंगल, *ग्लोबल डायलॉग* के संपादक

> वैश्विक संवाद **जी.डी. वेबसाइट** पर अनेक भाषाओं में देखा जा सकता है।

> प्रस्तुतियाँ <**globaldialogue@isa-sociology.org**> पर भेजी जा सकती हैं।

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रेनो ब्रिंगेल

सह–सम्पादक : विटोरिया गोंजालेज, कैरोलिना वेस्टेना

सहयोगी सम्पादक : क्रिस्टोफर इवांस

प्रबंधन संपादक : लोलाबुसुतिल, अगस्त बागा

सलाहकार : माइकल बुरावे, ब्रगिट औलेनबैकर, क्लाउस डोरे

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : *(लेबनान)* साड़ी हनाफी, *(ट्यूनिशिया)* फातिमा रधौनी, सफौने ट्रैबेल्सी।

अर्जेन्टीना : मैगडालेना लेमस, जुआन परसिआ, दांते मार्चिसिओ।

बांग्लादेश: हबीबुल खोंड़कर, खैरुल चौधरी, बिजॉय कृष्णा बनिक, शेख मोहम्मद कैस, मुमिता तंजीला, अब्दुर रशीद, मोहम्मद जहीरुल इस्लाम, रसेल हुसैन, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, हेलाल उद्दीन, मसुदूर रहमान, यास्मीन सुल्ताना, एसएम अनवारुल कायेस शिमुल, रूमा परवीन हशू, राशेद हुसैन, एकरामुल कबीर राणा, फरहीन एक्टर भुइयां, खदीजा खातून, आरिफुर रहमान, मो. शाहीन अख्तर, सुरैया अख्तर, आलमगीर कबीर, तस्लीमा नसरीन, नूर ए हबीबा मुक्ता।

ब्राजील : फेबरिसियो मासिएल, एंड्रेजा गली, जोसे गुइराडो नेटो, जेसिका मज़िजनी मेंडिस, रिकार्डो नोब्रेगा।

फ्राँस/स्पेन : लोला बुसुतिल

भारत : रश्मि जैन, मनीष यादव।

ईरान : रेयहाने जावदी, नियाश डॉलाती, एलहम शुशत्राजिदे, अली राघेब।

पोलैंड: अलेक्सांद्रा बिएरनका, अन्ना टर्नर, जोआना बेडनारेक, उर्स्जुला जारेका।

रोमानिया : रालुका पोपेस्कु, राइसा–गैब्रिएला जम्फिरेस्कु, बियांका ऐलेना मिहिला।

रूस : ऐलेना ज्द्रावोम्यस्लोवा, डारिया खोलोडोवा।

ताईवान : वान–जू ली, ताओ–युंग लु, चिएन–यिंग–चिएन, जी हाओ केर्क, मार्क यी–वेई लाई, यूं–जो लिन, यू–वेन लियाओ, यूं–हुआन चाउ।

तुर्की : गुल कोरबासियोग्लू, इरमक एवरेन।

*''समाजशास्त्र पर बातचीत'' अनुभाग में, नॉर्वेजियन समाजशास्त्री थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग और हेले हैग्लुंड ने **गाजा में चल रहे युद्ध** के बारे में पूर्व आईएस, अध्यक्ष सारी हनाफी का साक्षात्कार किया।*

*विषयगत खंड **''दक्षिण–दक्षिण सहयोग और नस्लीकरण''** दक्षिण–दक्षिण सहयोग के अंतर्गत प्रभुत्व के व्यापक रूपों को उजागर करने का प्रयास करता है ताकि कुछ मुख्य वैश्विक सहयोग चुनौतियों का विश्लेषण किया जा सके।*

*विषयगत खंड ''खुले आंदोलन'' चार लैटिन अमेरिकी देशों में समकालीन राजनीतिक प्रक्रियाओं में **विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक आंदोलनों की भूमिका** का अवलोकन प्रस्तुत करता है ।*

कवर चित्र : प्लानाल्टो पैलेस, ब्रासीलिया। श्रेय : लुकास लेफा @lleffa, 2024.

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

संपादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

गाजा में युद्ध और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी : सारी हनाफी के साथ एक साक्षात्कार
थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग और हेले हैग्लुंड, नॉर्वे द्वारा 5

> दक्षिण–दक्षिण सहयोग और नस्लीकरण

दक्षिण–दक्षिण सहयोग में पदानुक्रम और नस्लीकरण
कैरोलिना वेस्टेना, जर्मनी, एरिक सेजने, नीदरलैंड्स और मैरी स्टिलर द्वारा 9

"ग्लोबल साउथ" अवधारणा और इसके अधूरे नस्लवाद विरोधी आदर्श
मैरी स्टिलर द्वारा 11

अफ्रीका–चीन मुठभेड़ में नस्ल की प्रमुखता
एरिक सेजने और रूस विसर, नीदरलैंड द्वारा 13

अंगोला और क्यूबा का अग्रणी दक्षिण–दक्षिण सहयोग (1975–1991)
क्रिस्टीन हेट्जकी, जर्मनी द्वारा 15

क्या संयुक्त राष्ट्र आंति स्थापना में नस्लीय पदानुक्रम को समाप्त किया जा सकता है?
सारा वॉन बिलरबेक, और केसेनिया ओक्सामित्ना, यूके द्वारा 17

> वैश्विक न्याय के रूप में डीग्रोथ और उत्तर–निष्कर्षणवाद

डीग्रोथ, वैश्विक विषमताएं और पारिस्थितिक–सामाजिक न्याय
मिरियम लैंग, इक्वाडोर द्वारा 19

नारीवादी डीग्रोथ और पारिस्थितिक–सामाजिक संक्रमण
बेंगी अकबुलुत, कनाडा द्वारा 22

एक न्यायोचित एवं लोकप्रिय ऊर्जा परिवर्तन को कैसे निर्मित किया जाए?
तातियाना रोआ एवेन्डानो, कोलंबिया और पाब्लो बर्टिनाट, अर्जेंटीना द्वारा 25

(अखिल) अफ्रीकी पर्यावरण–नारीवादी आंदोलन
जो रैंड्रियामारो, मेडागास्कर द्वारा 28

> ओपन मूवमेंट्स

ग्वाटेमाला में लोकतंत्र के लिए 106 महत्वपूर्ण दिनों का वृतांत
एना सिल्विया मोनजोन, ग्वाटेमाला द्वारा 31

चिली में संवैधानिक प्रक्रिया की विफलता के बाद सामाजिक आंदोलन
कारमेन गेमिटा ओयारजो विडाल, चिली द्वारा 34

माइली की सरकार के प्रतिरोध की आुरुआत
जूलियन रेबन, अर्जेंटीना द्वारा 37

अयोतजिनापा: दस साल की दण्डहीनता
कार्लोस डी जेसुस गोमेज–अबार्का, मेक्सिको, द्वारा 39

> सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

अधिशेष और विस्थापन, शरणार्थी और प्रवासी
नादिया बौ अली और रे ब्रासियर, लेबनान द्वारा 41

> खुला अनुभाग

विनियोजन या उपयोग? श्रम संघर्षों का पारिस्थितिक आयाम
साइमन शॉप, स्विटजरलैंड द्वारा 45

मध्य पूर्व का डिजिटल दोहरा बंधन
मोहम्मद जायनी, कतर द्वारा 47

गाजा शिक्षाविदों द्वारा खुला पत्र
गाजा से शिक्षाविदों द्वारा 49

"व्यक्तियों के खिलाफ बहिष्कार अक्सर निरस्त करने की संस्कृति के हस्तक्षेप का क्षेत्र होता है। दूसरी ओर, संस्थागत बहिष्कार सक्रिय दमनकारी शक्ति वाले संस्थानों की मिलीभगत को लक्षित करता है।"

सारी हनाफी

> गाजा में युद्ध
और विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी
सारी हनाफी के साथ एक साक्षात्कार

ओस्लो विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी शिविरों में सारी हनाफी। श्रेय : पर्सनल आकाईव

सारी हनाफी वर्तमान में समाजशास्त्र के प्रोफेसर, अरब और मध्य पूर्वी अध्ययन केंद्र के निदेशक और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में इस्लामिक अध्ययन कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। वे ब्रिटिश अकादमी के कोरेस्पोंडिंग फेलो और अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ के पूर्व अध्यक्ष (2018–23) हैं। वे धर्म के समाजशास्त्र, फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर लागू (मजबूर) प्रवास के समाजशास्त्र और वैज्ञानिक अनुसंधान की राजनीति पर कई लेखों और पुस्तकों के लेखक हैं। एक सीरियाई–फिलिस्तीनी के रूप में, हनाफी फिलिस्तीन में रह रहे थे जब दूसरा इंतिफादा, अल–अक्सा इंतिफादा हुआ था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जिसे, वे स्पेसिओ–साइडल इजराइली प्रोजेक्ट कहते हैं, के तहत रहना क्या होता है का अनुभव किया। इस बातचीत में, वे गाजा में चल रहे युद्ध पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इजराइली संस्थानों के संस्थागत बहिष्कार का आह्वान करते हैं, और युद्ध के बारे में आज प्रचलित कुछ सामान्य व्याख्याओं पर चर्चा करते हैं, जिन्हें वे अपर्याप्त या गलत मानते हैं। यह साक्षात्कार मई 2024 में sosiologen.no के सदस्य, **थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग** और **हेले हैग्लुंड** द्वारा लिया गया था। sosiologen.no ओस्लो स्थित एक संपादकीय परियोजना है, जो नॉर्वेजियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का हिस्सा है, और ओस्लोमेट, बर्गन विश्वविद्यालय, एनटीएनयू, ओस्लो विश्वविद्यालय और ट्रोम्सो विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित है।

थोरा ब्योर्के सैंडबर्ग (टीबीएस) और हेले हैग्लंड (एचएच): प्रोफेसर हनाफी, 7 अक्टूबर के हमले के बाद आपके तात्कालिक विचार क्या थे? क्या इससे गाजा में चल रहे युद्ध के प्रति आपके दृष्टिकोण पर कोई असर पड़ा?

सारी हनाफी (एसएच): युद्ध 1947 में शुरू हुआ और विभिन्न प्रकरणों में जारी है। मैं 7 अक्टूबर के फिलिस्तीनी हमले को उपनिवेशीकरण की इस लंबी प्रक्रिया और इस उपनिवेशीकरण के प्रतिरोध के हिस्से के रूप में देखता हूं। मुख्य रूप से 2000 के बाद, जब इजरायल ने, चाहे सरकारी या जनमत के कारण, दूसरे इंतिफादा को हिंसक रूप

> >

से कुचलने में संलग्न हो ओस्लो शांति प्रक्रिया को लागू न करने का फैसला किया, पश्चिमी तट पर कब्जा और गाजा यहूदी बस्ती की घेराबंदी इतनी भयानक रही है (संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, इजरायली सेना और उपनिवेशियों द्वारा मारे गए फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या इजरायलियों की तुलना में 21 गुना अधिक है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, अवैध बस्तियों का तेजी से बढ़ना और विस्तार आदि को सम्मिलित करना चाहिए) कि हम फिलिस्तीनी प्रतिरोध के सुंदर होने की अपेक्षा क्यों करें ? समाजशास्त्रीय रूप से यह एक महत्वाकांक्षी सोच है। तथापि, अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के बारे में सोचने वाले एक समाजशास्त्री के रूप में मुझे एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने हमास को दोषमुक्त करने के लिए क्षेत्र में इजरायली हिंसा के इतिहास का उपयोग किया है।

इसके विपरीत, अन्य लोग तर्क देते हैं कि फिलिस्तीनियों – जिनकी जान ही दांव पर लगी है – से नैतिक संतुलन की मांग करना अन्यायपूर्ण है। लेकिन शायद हम में से कुछ लोगों में हमास की कार्रवाइयों पर नैतिक निर्णय पारित करने की अनिच्छा इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर हम बंदी शिविर की उन भयावह परिस्थितियों में रह रहे होते तो हम कैसे कार्य करते या प्रतिक्रिया करते। अंततः मेरा विचार है कि कोई भी हमला जो नागरिकों और लड़ाकों के बीच भेदभाव नहीं करता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं उपनिवेशियों का औपनिवेशवादियों का हिंसक तरीके से प्रतिरोध करने के अधिकार की निंदा नहीं करता हूँ।

टीबीएस और एचएचः हाल ही में ओस्लो विश्वविद्यालय ने इजरायल के अकादमिक बहिष्कार को नकार दिया है, जबकि साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी उल्लंघनों की निंदा की है और तत्काल युद्ध विराम की तथा गाजा पट्टी और इजरायल में नागरिकों के खिलाफ हमलों को रोकने की मांग की है। इस तरह के रुख पर आपके क्या विचार हैं?

एसएचः मैं विद्वानों और शैक्षणिक संस्थानों से उनकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए कहूंगा। मैं किसी भी संस्थान के खिलाफ संस्थागत बहिष्कार करने के नैतिक दायित्व में विश्वास करता हूं, जिसका औपनिवेशिक या सत्तावादी शक्तियों के साथ संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। मैं न केवल इजरायली संस्थानों बल्कि सीरियाई विश्वविद्यालयों का भी बहिष्कार करने का आह्वान करूंगा। संस्थागत बहिष्कार का विचार अक्सर उदार लोकतांत्रिक देशों में इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी जब इजरायली मामले की बात आती है, तो ये देश अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर अनिच्छुक होते हैं। यूरोपीय संस्थान हमेशा से ऐसा करते रहे हैं; यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी संस्थानों के खिलाफ और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के खिलाफ बहिष्कार का स्मरण करें। मुझे फिलिस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के एक फिलिस्तीनी सहयोगी की याद है, जिन्हें 2008 में फ्लोरेंस में यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान में एक अकादमिक कार्यशाला में भाग लेना था। कार्यशाला की तारीख से दो दिन पहले अचानक निमंत्रण रद्द कर दिया गया, क्योंकि उस समय हमास ने चुनाव जीता था, और कार्यशाला को यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मेरे अपने विश्वविद्यालय, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत (AUB) में, हम स्टेट डिपार्टमेंट डेटाबेस का उपयोग किए बिना किसी बाहरी वक्ता या पंजीकृत सहभागी को AUB में जूम टॉक में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। USAID से कुछ फंडिंग प्राप्त करने के लिए अनुपालन आवश्यक है। इस डेटाबेस के अनुसार, हम ईरानी सार्वजनिक विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं।

आज मैं सोचता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और गाजा पर युद्ध को नरसंहार के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्ध–योग्यता दिए जाने के अनुरूप, इजरायली संस्थानों का बहिष्कार करना एक नैतिक अनिवार्यता है। 2021 और 2022 में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच, साथ ही इजरायली मानवाधिकार समूह बी'सेलम और येश दीन ने भी इजरायल को एक रंगभेदी राज्य माना है।

मैंने अभी–अभी एक इजराइली विद्वान, माया विंड, द्वारा लिखी शानदार पुस्तक, *टावर्स ऑफ आइवरी एंड स्टीलः हाउ इजराइली यूनिवर्सिटीज डिनाई फिलिस्तीनी फ्रीडम* को पढ़ना समाप्त किया है। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से न केवल इजराइली राज्य के संरचनात्मक नस्लवाद को दिखाती है क्योंकि नस्लीय असमानता कानून में लिखी गई है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इजराइली विश्वविद्यालय इजराइली उत्पीड़न प्रणालियों में उलझे हुए हैं। तेल अवीव विश्वविद्यालय की इजराइली सेना के साथ कई साझेदारियां हैंः सैनिकों को प्रशिक्षण देना, सैन्य अधिकारियों को वहां पढ़ाने की अनुमति देना, तकनीक प्रदान करना, न्यायेतर हत्या के लिए नैतिकता आदि। विंड लड़ाकू सैन्य इकाइयों में अधिकारियों के लिए ''प्रतिष्ठित 'एरेज' बीए कार्यक्रम का उदाहरण देती हैं। इस दोहरी–प्रमुख डिग्री में सैन्य 'रुचि के क्षेत्रों' पर केंद्रित एक अकादमिक कार्यक्रम शामिल है, जो मानविकी, सामाजिक विज्ञान, व्यापार या अभियांत्रिकी के अन्य प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। सेना बताती है कि इरेज कार्यक्रम में, 'सैन्य और शैक्षणिक प्रशिक्षण आपस में जुड़े हुए हैं,' जिसमें कैडेटों को 'नागरिकों से सर्वोत्कृष्ट लड़ाकों' में बदल दिया जाता है।'' इजरायली क्षेत्रीय, जनसांख्यिकीय और सैन्य परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए इजरायली विश्वविद्यालयों में और उनके माध्यम से विकसित विशेषज्ञता, बुनियादी ढाँचा और तकनीकें प्रदान करते हुए, अन्य आठ इजरायली विश्वविद्यालय भी यही करते हैं (उनमें से दो कब्जे वाले पश्चिमी तट पर हैं)। मानविकी और सामाजिक विज्ञान में इजरायली औपनिवेशिक पुरातत्व (फिलिस्तीनी क्षेत्रों से कलाकृतियों की चोरी), कानूनी अध्ययन, मध्य पूर्व अध्ययन और सुरक्षा राज्य के लिए प्रशिक्षण में सहयोग करते हैं।

साथ ही, हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इजरायली शिक्षाविदों ने कुछ महान, साहसी विद्वानों को जन्म देने में सफलता प्राप्त की है जो सत्ता के सामने सच बोलते हैं। अन्य लोगों के साथ, मैं लेव ग्रिनबर्ग, ओरेन यिफ्ताचेल और ईवा इलौज के बारे में सोच रहा हूँ, । दो इजरायली दार्शनिक और मित्र, आदि ओफिर और मिशल गिवोनी के साथ सह–संपादित मेरी पुस्तक, *द पावर ऑफ इनक्लूसिव एक्सक्लूजन : एनेटोमी ऑफ इजरायल रूल इन द ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी टेरिटरीज* को देखते हुए, यह जानना दिलचस्प है कि अधिकांश इजरायली योगदानकर्ता अब इजरायल के बाहर पदों पर हैं। मुझे पता है कि उन्हें इस हद तक परेशान किया गया कि उन्होंने इजरायली शिक्षा जगत को छोड़ दिया । हिब्रू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नादेरा शाल्होब–केवोर्कियन, जिनके अनुबंध को रोक दिया गया और जिन्हें इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की, द्वारा झेले गए उत्पीड़न, 7 अक्टूबर से ही नहीं बल्कि उससे भी पहले सुनी गई कई कहानियों में से एक है।

टीबीएस एवं एचएचः यह बहिष्कार के बारे में है, लेकिन बीडीएस (बहिष्कार, विनिवेश और प्रतिबंध) में शामिल अन्य दो मदों के बारे में क्या?

एसएचः मैं यह देखकर हैरान हूँ कि विश्वविद्यालयों के अधिकांश अनुदान अब करोड़पतियों के हेज फंड का हिस्सा हैं। ये करोड़पति अधिकतम लाभ कमाने में रुचि रखते हैं, और अक्सर अमेरिका और

>>

कई अन्य देशों में हथियार और तंबाकू उद्योगों में आकर्षक निवेश की तलाश करते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास हैः इस हथियार/तंबाकू–सैन्य–सत्तावादी–औपनिवेशिक परिसर को वित्तपोषित करते हुए हम अपने छात्रों को तथाकथित ''लिबरल आर्ट'' पढ़ाते हैं? हमें इजरायली उद्योग से विनिवेश करते समय भी यही तर्क देना चाहिए, जिसके बारे में हम इतने सारे अध्ययनों से जानते हैं कि यह किस हद तक इजरायली उपनिवेशवादी और रंगभेदी सैन्य परियोजनाओं में शामिल है और उन्हें मंजूरी दे रहा है।

टीबीएस एवं एचएचः कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि बीडीएस यहूदी विरोध का एक रूप है...

एसएचः फिलिस्तीनी–इजरायल संघर्ष एक औपनिवेशिक संघर्ष है, भले ही कुछ लोग इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दुखद संदर्भ में प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद के रूप में देखें। इस प्रारूप में भी, एक राष्ट्रीय समूह दूसरे राष्ट्रीय समूह को बेदखल करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, पश्चिमी तट (पूर्वी यरुशलम सहित) और गाजा में फिलिस्तीनी क्षेत्र कब्जे वाली भूमि हैं। एक कब्जाधारी है जिसकी प्रतिदिन औपनिवेशिक और नस्लभेदी प्रथाएं हैं और उनके विरूद्ध प्रतिरोध है। मेरे लिए, यहूदियों के लिए नफरत या यहूदी–विरोध के बारे में बात करना बेतुका है। आज, नरसंहार की भौतिकता और ग्राफिक छवियां मानवता में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रोधित करती हैं। एक विषय के रूप में यहूदी–विरोध आज, बहस और चर्चा को बंद कर देता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान अकादमिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के समय मैंने दक्षिण अफ्रीका– विरोधी या अफ्रिकन–विरोधी विचारों के बारे में कभी भी नहीं सुना। मुझे यकीन है कि अधिकांश यूरोपीय शिक्षाविद रूसी संस्थानों का बहिष्कार करते हैं। मैंने कभी लोगों को यह कहते नहीं सुना कि यह रूस विरोधी है। यह कहने के साथ, दुनिया के कुछ हिस्सों में यहूदी विरोध स्पष्ट है, लेकिन इसे यहूदीवाद–विरोध या इजरायली औपनिवेशिक प्रथाओं की आलोचना के साथ जोड़ना भ्रामक है।

टीबीएस और एचएचः कुछ लोग यह भी तर्क दे सकते हैं कि "फ्रॉम द रिवर टू द सी, फिलिस्तीन विल बी फ्री" का नारा यहूदी विरोधी है।

एसएचः अधिकांश कार्यकर्ता इसका उपयोग कैसे करते हैं के बारे में यह निश्चित रूप से एक गलत व्याख्या है। यूरो–अमेरिकी क्षेत्र में प्रदर्शनों में, मैंने प्रदर्शनकारियों के साथ कई बैनर और साक्षात्कार देखे हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अपने सभी निवासियों के लिए एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य का आह्वान था। इसका मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहा जाना चाहिएः फिलिस्तीन/इजराइल या कोई तीसरा नाम। यहां तक कि हमास के नेतृत्व में नंबर 3 मूसा अबू मरजूक ने हाल ही में एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया कि एक–राज्य समाधान एक व्यक्ति, एक वोट है, चाहे व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो। इस नारे का चयन ''फ्रॉम द रिवर टू द सी'' की राजनीति के तहत रोजमर्रा के इजराइली उपनिवेशी प्रथाओं की प्रतिक्रिया है। हम यह न भूलें कि नेतन्याहू की अपनी पार्टी, लिकुड के चार्ट पर भी यह नारा है। इससे भी बदतर, यह नदी जॉर्डन नदी नहीं बल्कि यूफ्रेट्स है।

यूरोप में नरसंहार की यादें अभी भी जीवंत हैं, और मैं समझता हूं कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किया गया हमला, जो नागरिकों और लड़ाकों के बीच भेदभाव नहीं करता है, ने कुछ यादें वापस ला दी हैं। लेकिन इस पुरानी पीढ़ी को यह भी समझना चाहिए कि क्यों युवा अपने कट्टरपंथी नारे के साथ, मानवीय रूप से अपने अनुभव को दर्शाते हैं कि कैसे इजरायली सेना महिलाओं और बच्चों को मार रही है और भूख से मार रही है, गाजा में उनके स्कूलों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर रही है – जिसे कुछ विद्वान 'विद्वान हत्या' कहते हैं। हालांकि, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि युवा लोग अक्सर एक ही सामग्री नहीं देखते हैंः डीडब्ल्यू न्यूज और फ्रांस 24 की तुलना अल जजीरा से करें। यही कारण है कि हमें विभिन्न समूहों को अलग–अलग तर्कों से अवगत कराने के लिए परिसर के अंदर एक संवाद स्थान बनाना चाहिए।

टीबीएस और एचएचः यदि कोई कहे कि संस्थागत बहिष्कार दूसरों की संस्कृति को निरस्त करने के समान है तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे?

एसएचः व्यक्तियों के खिलाफ बहिष्कार अक्सर निरस्त करने की संस्कृति के हस्तक्षेप का क्षेत्र होता है (उदाहरण के लिए, एक वक्ता का निमंत्रण निरस्त करना, किसी शख्सियत के पद को बदलना)। दूसरी ओर, संस्थागत बहिष्कार सक्रिय दमनकारी शक्ति वाले संस्थानों की मिलीभगत को लक्षित करता है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में मान्यता दी गई है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन को किया गया था। संस्थागत बहिष्कार को प्रतिरोध के अंतिम शांतिप्रिय उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए। इस अर्थ में, यह इजरायली संस्कृति को निरस्त करना नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय–सैन्य परिसर को कमजोर करता है। इस तरह के बहिष्कार का आह्वान करने से मुझे दो इजरायली दार्शनिकों के साथ एक पुस्तक का सह–संपादन करने से नहीं रोका जा सका। ऐसा करके, मैं फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों विद्वानों को एक–दूसरे को पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ : किसी भी आवाज को निरस्त नहीं करना चाहिए।

टीबीएस एवं एचएचः ऐसी परिस्थितियों में क्या विश्वविद्यालयों के लिए तटस्थ रहना संभव है?

एसएचः चुप्पी का मतलब है मिलीभगत। दशकों से, विश्वविद्यालय विरोध, खुली चर्चा और वर्चस्वशाली प्राधिकारियों की राजनीति के बारे में असहमति का स्थान रहे हैं, जैसा कि वियतनाम युद्ध से लेकर रंगभेद दक्षिण अफ्रीका तक हुआ। वे वाक् स्वतंत्रता के स्थान तब तक ही हैं जब तक वहां जोरदार जवाबी भाषण हो। इसलिए, मैं दूसरों की संस्कृति को खत्म करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ हूं, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक या नस्ल और लिंग के मुद्दों से संबंधित हो।

टीबीएस और एचएचः आपने 'स्पेसियो–साइड' की अवधारणा गढ़ी। इसका क्या मतलब है? और 7 अक्टूबर के हमलों से पहले फिलिस्तीन की स्थिति के बारे में ध्यान और जागरूकता (या इसकी कमी) के बारे में आप क्या सोचते हैं?

एसएचः 1999 से 2004 के बीच, मैं दूसरे इंतिफादा के चरम पर कब्जे वाले फिलिस्तीन में रहा। उस समय, मैंने 'स्पेसियो–साइड' की अवधारणा को गढ़ा, क्योंकि मैं फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मुद्दों और संघर्ष के राजनीतिक समाजशास्त्र दोनों में रुचि रखता था। इजरायली बसने वाले औपनिवेशिक परियोजना लंबे समय से ''स्पेसियो–साइडल'' (नरसंहार के विपरीत) रही है, चूँकि यह फिलिस्तीनियों के निष्कासन के लिए भूमि को लक्षित करती है।

>>

जिस स्थान पर फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, उसे लक्षित करके, यह नीति फिलिस्तीनी आबादी के स्थानांतरण पर बल डालती है और उसे अपरिहार्य बनाती है।

स्पेसियो–साइड एक सोची–समझी विचारधारा है, जिसका एक ही तर्क है कि यहूदियों के लिए ज्यादा जमीन और फिलिस्तीनियों के लिए कम जमीन होनी चाहिए। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध की कार्रवाइयों सहित बदलते संदर्भ के साथ अंतर्क्रिया करती है। यह अलग–अलग ''–साइड्स'' की परिणिति है, जिसमें फिलिस्तीनियों की गतिशीलता पर प्रतिबंध लगाकर फिलिस्तीनी भूमि को रहने लायक नहीं बनाया जाता, फिलिस्तीनी नेताओं की हत्या की जाती है (राजनीति–साइड), फिलिस्तीनी कृषि के लिए आवश्यक भूजल की चोरी की जाती है और फिलिस्तीनियों की संभावित आर्थिक व्यवहार्यता को कम किया जाता है (अर्थ–साइड)। इजराइली सैन्य–न्यायिक–नागरिक तंत्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन और उन पर प्रश्न उठाकर, मैं दिखाता हूँ कि स्पेसियो–साइडल परियोजना एक ऐसे शासन के जरिए संभव हुई जो तीन सिद्धांतों को लागू करता है: उपनिवेशीकरण (ज्यादा जमीन जब्त करना), पृथक्करण (इजराइली जमीन और फिलिस्तीनी जमीन के मध्य), और अपवाद की स्थिति जो इन दो विरोधाभासी सिद्धांतों के बीच मध्यस्थता करती है। अब, इजराइली औपनिवेशिक परियोजना स्पेसियो–साइडल से नरसंहारक बन गई है।

टीबीएस और एचएच: भविष्य को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न। फिलिस्तीन / इजराइल के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं (मुझे पता है यह बड़ा प्रश्न है)? क्या आप सकारात्मक और आशावादी हैं? क्या आपके पास कोई "सपना परिदृश्य" है?

एसएच: एक समाजशास्त्री जिसने देखा है कि फिलिस्तीनी–इजराइली संघर्ष कितना खूनी है, के रूप में एक–राज्य समाधान की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, फिर भी दो–राज्य समाधान फिलिस्तीन–इजराइल के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय उदार लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में पहला कदम होना चाहिए। इसका मतलब है दो कक्षों की स्थापना: एक सभी नागरिकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए ''एक व्यक्ति, एक वोट'' सिद्धांत को दर्शाता है; दूसरे में, दो राष्ट्रीय समूह (यहूदी, अरब) स्वायत्तता के अपने रोजमर्रा के मुद्दों पर बहस करते हैं। मेरे इजराइली सहयोगी, समाजशास्त्री जूली कूपर ने इस दिशा में कुछ दिलचस्प विचार विकसित किए हैं। फिर भी, यह 2007 के हाइफा घोषणा की भावना को दर्शाता है, जिसे नादिम रूहाना, नादेरा शालहौब–केवोर्कियन और अन्य लोगों ने मिलकर लिखा था और कई फिलिस्तीनी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन बिना किसी अविलम्ब के, गाजा में वर्तमान इजराइली नरसंहार को रोका जाना चाहिए। हमें दुनिया भर में नई पीढ़ियों, हमारे छात्रों को इस युद्ध में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों और कई विश्वविद्यालय प्रशासनों की मिलीभगत पर अपना आक्रोश व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए। राणा सुकरीह की भाषा में, उनका संघर्ष उपनिवेशवाद–विरोधी तीसरी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीयतावादी कल्पना को दर्शाता है। ऐसी लामबंदी के लिए जयकार! ■

सभी पत्राचार सारी हनाफी को <sh41@aub.edu.lb>
ट्विटर: @hanafi1962 पर प्रेषित करें।

> दक्षिण–दक्षिण सहयोग में पदानुक्रम और नस्लीकरण

कैरोलिना वेस्टेना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसल, जर्मनी, **एरिक सेजने**, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड्स, और **मैरी स्टिलर*** द्वारा

20 अप्रैल, 1955 को बांडुंग के मर्डेका भवन में एशियाई–अफ्रीकी सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने आर्थिक अनुभाग की पूर्ण बैठक आयोजित की। श्रेय : सार्वजनिक डोमेन।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण गत्यात्मकता है। ऐतिहासिक उदाहरणों में बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पैन–अफ्रीकनिज्म शामिल हैं, जो 1950 और 1960 के दशक के दौरान अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की पृष्ठभूमि में उभरे थे। हाल के उदाहरण, विशेष रूप से 2000 के बाद की अवधि में, कमोडिटी बूम के चरम पर और उत्तरी नेतृत्व वाले वैश्वीकरण के साथ बढ़ते मोहभंग के बीच ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती ताकतें– और ब्रिक्स जैसे उनके संबंधित समूह रणनीतिक वाणिज्यिक साझेदारी और राजनीतिक प्रभाव की खोज में पाए जा सकते हैं। यद्यपि यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में एसएससी और संभावित प्रति–आधिपत्य संबंधों के बारे में बयानबाजी तेजी से बढ़ी है ।

हालांकि, दक्षिण–दक्षिण सहयोग में ब्रिक्स के मामले में राजनीतिक या आर्थिक शक्ति बढ़ाने के प्रयासों से कहीं अधिक शामिल हैं, जैसा ब्रिक्स के मामले में। अधिक व्यापक रूप से, इसे संसाधनों, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और आदान–प्रदान से जोड़ा जा सकता है। इसमें पारंपरिक रूप से ''ग्लोबल साउथ'' के रूप में संदर्भित देशों और निजी कर्त्ताओं के मध्य व्यापार, शिक्षा या श्रम प्रवास के क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग के माध्यम से मध्यस्थता वाले पारस्परिक संपर्क के विविध रूप शामिल हैं। दक्षिण–दक्षिण ''एकजुटता'', ''दोस्ती'' और ''पारस्परिक मदद'' जैसे शब्द अक्सर एसएससी रणनीतियों और प्रथाओं को चिह्नित करने और वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, जिन्हें दक्षिणी देशों के अपने हितों और विकास संदर्भों के लिए अधिक क्षैतिज और बेहतर रूप से अनुकूल बताया जाता है ।

> >

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों की एजेंसी, स्वतंत्रता और संसाधनशीलता पर जोर देना है। यह वैश्विक दक्षिण स्वयं की बहुमुखी अवधारणा को भी रेखांकित करता है, जिसका खुलासा इस अवधारणा के ऐतिहासिक विश्लेषण से से होता है (उदाहरण के लिए, इस अंक में स्टिलर का आलेख देखें)। सामाजिक आंदोलनों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी वैकल्पिक वैश्वीकरण या जलवायु संकट से निपटने के नए तरीकों की वकालत करते समय दक्षिण–दक्षिण एकजुटता की सकारात्मक धारणा का आह्वान करते हैं। सभी कोणों से एसएससी की सकारात्मक छवियों का आह्वान किया जाता है: ''नीचे'' से और साथ ही ''ऊपर'' से भी।

लेकिन यदि एक राजनीतिक परियोजना के रूप में, दक्षिण–दक्षिण सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर एक विशिष्ट अभ्यास, तथा दक्षिणी कर्त्ताओं की एजेंसी को उजागर करने के लिए एक वैचारिक अनुमान – का आंतरिक रूप से इतना सकारात्मक चरित्र है, तो हम सहयोग की ऐसी परियोजनाओं के भीतर असमानताओं और पदानुक्रमों के बने रहने की व्याख्या कैसे कर सकते हैं?

दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर आलोचनात्मक साहित्य पहले ही दिखा चुका है कि तटस्थ सहयोग जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान और सहयोग भी वर्चस्व के (घरेलू) सामाजिक संबंधों को दर्शाते हैं। अधिकांश साहित्य ने पूंजीवाद के तर्क पर निर्मित वैश्विक पदानुक्रमों की आलोचना की है। उदाहरण के लिए, डु बोइस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर निबंधों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक शक्ति वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों के देशों में नस्लीय पदानुक्रमों और श्रम विभाजन के रखरखाव में भी प्रकट होती है। यह व्याख्या, जो पूंजीवादी संरचनाओं और नस्लीय पदानुक्रमों को मिलाना चाहती है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व के संबंधों की जटिलता पर चिंतन के लिए मौलिक है।

हालाँकि, अधिकांश दक्षिण–दक्षिण सहयोग अध्ययन अभी भी नस्लीयकरण के घटक को छोड़कर, केवल आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नस्लीयकरण के घटक, यानि के ये सम्बन्ध किस प्रकार और कैसे नसलीकृत होते हैं, को छोड़ देते हैं। इससे वैश्विक सहयोग की चुनौतियों और इसके आंतरिक संघर्षों की एक–आयामी समझ विकसित हो सकती है। इसके अलावा, यह इस बात की कोई समझ नहीं प्रदान करेगा कि एसएससी की ये परियोजनाएँ दक्षिण से मित्रता और आपसी सहयोग के आख्यानों के प्रसार के माध्यम से विवादास्पद वैधता के लिए क्यों प्रयास करती हैं।

हमारा तर्क है कि वैश्विक सहयोग के लिए चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए दक्षिण–दक्षिण सहयोग के अंतर्गत वर्चस्व के व्यापक रूपों को देखना महत्वपूर्ण है। हम आगे दावा करते हैं कि एसएससी के बहुआयामी विश्लेषण के लिए विभिन्न स्तरों पर संघर्षों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, चाहे वह राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या जमीनी कर्त्ताओं के मध्य संबंधों के भीतर हो। जहाँ मित्रता और आपसी मदद के आख्यान शक्ति और पदानुक्रमिक पदों के विषम संबंधों, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इन प्रयासों को रेखांकित करते हैं, को छिपाने में मदद करते हैं, हम एसएससी पर शोध के उभरते हुए क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं जिसकी ऐसी जटिलताओं को ध्यान में रखने की संभावना है।

इसके बाद आने वाले लेखों की श्रृंखला से पता चलता है कि सममित सहयोग और पारस्परिक सहायता के आधिकारिक रूप से घोषित विचारों के पीछे, एसएससी का वास्तविक जीवन का अनुभव नस्लीयकरण के पारस्परिक और संस्थागत रूपों द्वारा चिह्नित है, जो भेदभाव की पदानुक्रम और गतिशीलता का उत्पादन करता है। नस्लीयकरण प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही संस्थानों और कर्त्ताओं द्वारा ''अन्य'' (अर्थात जातीय रूप से अलग, आमतौर परध्अधिकतर अश्वेत नागरिक माने जाने वाली आबादी) के दृष्टिकोण को भी फ्रेम करती हैं।

चूंकि साहित्य में मुख्य रूप से आर्थिक और राजनीतिक पदानुक्रमों पर जोर दिया गया है, हम नस्लवाद की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे हम यह मानते हैं कि वर्ग, लिंग और नागरिकता की स्थिति सहित विभिन्न आयाम वैश्विक पदानुक्रम में योगदान करते हैं। दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर हमारी चर्चा विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक स्वानुभविक श्रेणी के रूप में नस्लवाद की समस्याग्रस्त सामाजिक घटनाओं से जुड़ती है। सबसे पहले, हम विचार करते हैं कि एसएससी के भीतर पदानुक्रम के एक रूप और ''सहकारी–विभाजित'' के निर्माण के रूप में नस्लवाद कैसे सामने आता है। हम विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न कर्त्ताओं के पुंज में नस्लवाद की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं; उदाहरण के लिए, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय आंदोलन को सम्मिलित करने वाली एसएससी। अंत में, दक्षिण–दक्षिण निवेश, शैक्षिक परियोजनाओं, या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बारे में कर्त्ताओं की धारणाओं में स्थानिक रूप से स्थित विकास और परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, आलेख एसएससी कैसे स्थानीय स्तर पर नस्लीयकरण को आकारित करती है के बारे में जमीनी परिपेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

दक्षिण–दक्षिण वैश्विक सहयोग में नस्लीयकरण पर बहस के ये तीन आयाम, एक तरफ, वैश्विक सहयोग के भीतर शक्ति गतिशीलता पर अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, तब भी जब इसका उद्देश्य ''वैश्विक उत्तर और दक्षिण'' के बीच शक्ति असंतुलन को बदलना हो। दूसरी ओर, यह चर्चा तब भी उपयोगी हो सकती है जब समाज में नस्लीय–आधारित पदानुक्रमों की संरचनात्मक भूमिका और वर्चस्व के अन्य रूपों, जैसे लिंग, वर्ग या जातीय–आधारित पदानुक्रमों के साथ अंतर्संबंधों और वैश्विक व्यवस्था के भीतर विभिन्न स्तरों पर उन्हें कैसे कायम रखा गया है, के बारे में सोचने की बात आती है। ■

* लेखक ने छद्म नाम का उपयोग करने का विकल्प चुना।

सभी पत्राचार कैरोलिना वेस्टेना को <carolina.vestena@uni-kassel.de>
ट्विटरः @carolinavestena
एरिक सेजने को <e.m.cezne@uu.nl> ट्विटरः @eric_cezne पर प्रेषित करें।

> "ग्लोबल साउथ" अवधारणा और इसके अधूरे नस्लवाद विरोधी आदर्श

मैरी स्टिलर द्वारा*

ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। श्रेय : ग्लोबल मैजोरिटी विकिमीडिया टेक्नोलॉजी प्रायोरिटीज।

अप्रैल 18, 1955 को बांडुंग सम्मलेन में अपने उद्घाटन भाषण में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो ने "ग्लोबल साउथ" देशों और नस्लवाद के प्रश्न को निम्नलिखित तरीके से जोड़ाः

''हम कई अलग–अलग राष्ट्रों से हैं, हम कई अलग–अलग सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पैटर्न से हैं। [...] हमारा प्रजातीय वंशास्त्रोत भिन्न है, और यहाँ तक कि हमारी त्वचा का रंग भी अलग है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मानवजाति इनके अलावा अन्य विचारों से एकजुट या विभाजित होती है। संघर्ष न तो त्वचा की विविधता से, न ही धर्म की विविधता से, बल्कि विभिन्न इच्छाओं की वजह से आता है। मुझे यकीन है कि हम सभी उन चीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से एकजुट हैं जो हमें सतही रूप से विभाजित करती हैं। उदाहरण के लिए, हम उपनिवेशवाद, चाहे वह किसी भी रूप में प्रकट हो, के प्रति एक समान घृणा से एकजुट हैं। हम नस्लवाद के प्रति एक समान घृणा से एकजुट हैं। और हम विश्व में शांति को बनाए रखने और स्थिर करने के लिए एक समान दृढ़ संकल्प से एकजुट हैं।''

ग्लोबल साउथ को यहां उपनिवेशवाद विरोधी, नस्लवाद विरोधी और शांति समर्थक परियोजना के रूप में पेश किया गया। हालांकि, यह मंच दिखाता है कि दक्षिण–दक्षिण सहयोग प्रक्रियाएं कैसे विभिन्न प्रकार की नस्लीयकरण प्रक्रियाओं द्वारा चिह्नित की गई हैं। यदि वास्तव में ग्लोबल साउथ से कोई नस्लवाद विरोधी परियोजना है, तो उसका वादा अभी भी अधूरा है।

> नस्लभेदीकरण और वैश्विक दक्षिण

यहाँ नस्लीयकरण को एक ऐसी प्रथा के रूप में समझा जाता है जिसके द्वारा लोगों के एक समूह को एक विशिष्ट नस्लीय अर्थ या रूढ़िबद्धता दी जाती है। नस्लीयकरण ''नस्ल'' की श्रेणी के आधार पर पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखता है। नस्लीयकरण की अवधारणा हमें उन प्रथाओं का अध्ययन करने में मदद करती है जो नस्लीय असमानता या नस्लवाद का परिणाम हैं। इसके अलावा, इस शब्द का उपयोग ''नस्ल'' की तथाकथित जैविक श्रेणी, जिसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, से बचने का एक तरीका हो सकता है (इस विषयगत अंक का परिचय देखें)।

जबकि नस्लवाद विरोधी आदर्श साकार नहीं हुए हैं, फिर भी सामाजिक कल्पना के रूप में वैश्विक दक्षिण का पूर्व उपनिवेशित राज्यों, संस्थाओं और लोगों के बीच एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए लगातार आह्वान किया जाता रहा है। विशेष रूप से, सरकारों ने अक्सर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को वैध बनाने या "विकास पहल" के लिए रणनीतिक बयानबाजी के उपकरण के रूप में वैश्विक दक्षिण एकजुटता की भाषा का इस्तेमाल किया है।

ग्लोबल साउथ एक समरूप इकाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना है जिसे घोषित नस्लवाद विरोधी भावना, जो अभी भी अनुपस्थित है, द्वारा आंशिक रूप से वैध बनाया गया है। इस संक्षिप्त लेख का उद्देश्य ग्लोबल साउथ अवधारणा को इस आधार के साथ समस्याग्रस्त बनाना है।

> अवधारणाओं की त्रिमूर्ति

आम तौर पर, ग्लोबल साउथ की अवधारणा बहुत अस्पष्ट और अवधारणात्मक रूप से कमजोर है। सामाजिक कल्पना के रूप में यह नस्लीय अन्याय सहित कई अन्यायों को हराने के बजाय उन्हें बनाए रख सकती है।

श्नायडर (2017) ''ग्लोबल साउथ'' की तीन मुख्य अवधारणाओं में भेद करता हैः भौगोलिक ग्लोबल साउथ, अधीनस्थ ग्लोबल साउथ और एक लचीले रूपक के रूप में ग्लोबल साउथ। सबसे आम प्रयोग >>

भौगोलिक का है और यह ग्लोबल साउथ को उन पूर्व उपनिवेशित विश्व क्षेत्रों में स्थित करता है जिन्हें संरचनात्मक रूप से अविकसित और गरीबी से ग्रस्त (पूर्व में ''तीसरी दुनिया'') माना जाता है: लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। भौगोलिक अवधारणा समकालीन प्रवचनों में प्रमुख है। इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र जैसे शक्तिशाली सुपरानेशनल संस्थानों द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्र–राज्य और अंतर–राज्य परिप्रेक्ष्य पर आधारित है।

ग्लोबल साउथ का दूसरा मॉडल, जो पहली बार अल्फ्रेड लोपेज (2007) द्वारा सुझाया गया था, दुनिया भर के ''अधीनस्थों'' से संबंधित है: नवउदारवादी नीतियों से वंचित मानव जो सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से अशक्त हैं। वे ''वैश्विक'' हैं क्योंकि उन्हें अब एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यद्यपि लोपेज ''दक्षिणी'' को भौगोलिक स्थान से अलग करते हैं (दक्षिणी हर जगह है), वह अंततः ''दक्षिण'' को ''वर्ग'' में संकुचित कर देते हैं।

अंत में, तीसरी व्याख्या वैश्विक दक्षिण को एक लचीले रूपक के रूप में मानती है जिसे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र (जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया) या सामाजिक रूप से निश्चित तत्व (जैसे वर्ग) तक सीमित नहीं किया जा सकता है। बल्कि, यह संबंधपरक है। यह तीसरी अवधारणा तथाकथित शक्तिशाली उत्तर और वंचित दक्षिण के बीच एक रूपकात्मक सीमा खींचती है। उदाहरण के रूप में, यह उत्तरी और दक्षिणी इटली के बीच की सीमा से, या समृद्ध जर्मनों और वंचित जर्मन आबादी के बीच संबंधित हो सकता है। यह अमूर्त है क्योंकि यह ''लचीला'' है। यह भौगोलिक और सामाजिक भेदभाव और किसी भी प्रकार की असमानता दोनों से संबंधित हो सकता है ।

निकट से निरीक्षण करने पर, तीनों अवधारणाओं के अपने लाभ और नुकसान हैं। साथ ही, वे एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण या विकास से संबंधित हैं। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब हम पूछते हैं: ग्लोबल साउथ पहली बार कब उभरा और इसने तीसरी दुनिया की अवधारणा को कब प्रतिस्थापित किया?

ऐतिहासिक रूप से, इस शब्द का उदय उपनिवेशवाद के उन्मूलन की अवधि और पूर्व उपनिवेशित लोगों के बीच राष्ट्रीय पहचान के उदय से संबंधित है। ''ग्लोबल साउथ'' शब्द का इस्तेमाल 1960 और 1970 के दशक में बांडुंग (1955) की ऐतिहासिक घटना और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) और 1964 में 77 के समूह की स्थापना के बाद आम इस्तेमाल में आना शुरू हुआ। इसने धीरे–धीरे ''पश्चिम'' और ''पूर्व'' शब्दों के साथ–साथ ''तीसरी दुनिया'', जो एक अपमानजनक अवधारणा में बदल गई थी, की जगह ले ली। ''ग्लोबल साउथ'' शब्द एक निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था और अंतर–राज्यीय और अंतर–क्षेत्रीय समानता के संघर्ष की दृष्टि से जुड़ा था। इसमें ग्लोबल नॉर्थ की ओर से नई जिम्मेदारी का आह्वान शामिल था।

> विविधता, आंतरिक विभाजन और अतिसरलीकरण के खतरे

अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि अपनी ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक पुरातन और सबसे अधिक प्रचलित व्याख्या – भोगौलिक व्याख्या– के रूप में ग्लोबल साउथ ''वास्तविक'' दुनिया का वर्णन करने के लिए एक अत्यंत अपरिष्कृत श्रेणी है। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों में भारी (और बढ़ती हुई) विविधता है। दक्षिण अफ्रीका (दक्षिणी ब्रिक्स) के साथ चीन, ब्राजील और भारत, शायद ही सोमालिया, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक, के साथ समूहबद्ध हो सकते हैं। इसके बजाय चीन और ब्राजील कई अफ्रीकी क्षेत्रों में वैश्विक हितधारक बन गए हैं। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे "दक्षिण" के लेबल द्वारा स्पष्ट रूप से चुप करा दिया गया है। इसके अलावा, भौगोलिक व्याख्या इन दक्षिणी देशों के भीतर उल्लेखनीय विभाजनों को छोड़ देती है: इन देशों में अमीर और गरीब के मध्य विशाल अंतर। जैसा कि विजय प्रसाद ने *पॉसिबल हिस्ट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ* (2012) में पता लगाया है, दक्षिण कभी भी एक समरूप इकाई नहीं रहा है, बल्कि यह वैचारिक खाइयों (जैसे नवउदारवाद के इर्द–गिर्द घूमती) के आधार पर विभाजित रहा है।

फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भौगोलिक व्याख्या इन ''दक्षिणी'' देशों के भीतर वर्ग, नस्ल, लिंग और क्षेत्रीय रेखाओं के आधार पर उल्लेखनीय विभाजन को छोड़ देती है। लोपेज की सबाल्टर्न ग्लोबल साउथ की अवधारणा यह स्वीकार करते हुए कि निर्धनता अक्सर नस्लीय होती है, और अनिवार्य रूप से ''वर्ग'' की श्रेणी पर आधारित होती है, ''वर्ग'' विभाजन की ओर इशारा करने की कोशिश करती है ।

तो, यदि ग्लोबल साउथ की अब तक की उपलब्ध सभी अवधारणाएं वास्तविक दुनिया का सटीक वर्णन करने में विफल रही हैं, उन्होंने विशेष रूप से नस्लीयकरण की प्रक्रियाओं के इर्द–गिर्द घूमने वाली असमानताओं को कम करके आंका है। हमारे पास एक ऐसी अवधारणा का अभाव है जो यूरो–अमेरिकी संदर्भ के ढांचे पर केंद्रित अश्वेत–श्वेत युग्मक और द्वैतवाद से आगे बढ़ती है, जैसा कि यह विषयगत अंक दर्शाता है।

भले ही सुकर्णो के दक्षिण के नस्लवाद विरोधी आदर्श पूरे न हुए हों, लेकिन पूर्व उपनिवेशी लोगों के साथ–साथ उत्तर के विद्वानों के बीच एकजुटता की भावना में काल्पनिक रूप से वैश्विक दक्षिण का लगातार आह्वान किया जाता रहा है। कई विद्वान और सक्रिय बुद्धिजीवी वैकल्पिक शब्दों के अभाव में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अक्सर इसका प्रयोग एक निष्पक्ष और सामाजिक रूप से अधिक प्रगतिशील दुनिया की खोज में भी किया जाता है: नस्लवाद–विरोधी, उपनिवेश–विरोधी और शांति–समर्थक दुनिया का आह्वान जारी रखने के लिए (श्नायडर 2017)।

फिर भी, वैश्विक दक्षिण एक समरूप इकाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी रचना है जिसे आंशिक रूप से घोषित नस्लवाद–विरोधी भावना, जिसे ये पूरा करने में विफल रहते हैं, के माध्यम से वैध बनाया गया है। इस प्रकार, अवधारणा का अविवेकी उपयोग हमें नस्लीयकरण, नस्लवाद और उपनिवेशवाद के नए रूपों के प्रति अंधा बना सकता है। ■

* लेखक ने छद्म नाम का उपयोग करने का विकल्प चुना।

> अफ्रीका–चीन मुठभेड़ में नस्ल की प्रमुखता

एरिक सेजने, यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय, नीदरलैंड, और **रूस विसर**, एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय, नीदरलैंड द्वारा

थिएस, सेनेगल में चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन (CRBC) द्वारा ILA टूर्स राजमार्ग का निर्माण। श्रेय : यिफान यांग।

वर्ष 2020 में, वैश्विक महामारी और दुनिया भर में नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों के शक्तिशाली संगम के मध्य, चीनी शहर ग्वांगझोउ में हुई घटनाओं ने अफ्रीका–चीन संबंधों में नस्लवाद की चर्चाओं को फिर से हवा दे दी। कोविड–19 को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए उपायों ने अफ्रीकियों और अफ्रीकी मूल के लोगों को असंगत रूप से लक्षित किया। कई लोगों को बेदखली, बेघर होने और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिससे अफ्रीकी प्रवासियों और सरकारों के मध्य आक्रोश फैल गया।

अफ्रीका–चीन संबंधों को पारंपरिक रूप से दक्षिण–दक्षिण एकजुटता और सहानुभूति पर आधारित मित्रता के रूप में दर्शाया गया है। विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत से, इनमें उल्लेखनीय वृद्धि ने न सिर्फ अवसरों की प्रचुरता को, बल्कि चुनौतियों को भी जन्म दिया है। दोनों दिशाओं में यात्रा, प्रवास और व्यापार में वृद्धि ने गतिशील व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया है। तथापि, बढ़े हुए संपर्क ने नस्लीय भेदभाव, संदेह और अलगाव के मामलों को भी जन्म दिया है, जिसका प्रमाण ग्वांगझोउ में हाल की घटनाएँ हैं।

अफ्रीका–चीन संबंधों में नस्लवाद और नस्लीय पूर्वाग्रह जटिल ऐतिहासिक और वैश्विक गतिशीलता में निहित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मुद्दे चीनी दृष्टिकोण और अफ्रीकियों के साथ व्यवहार तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि नस्लवाद विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। नस्लीयकरण – नस्लीय अर्थों और वर्गीकरणों का सामाजिक संबंधों तक विस्तार – दोनों दिशाओं में होता है, जो चीन में अफ्रीकियों और अफ्रीका में चीनी व्यक्तियों को समान रूप से प्रभावित करता है।

> चीन में अफ्रीकी

ग्वांगझोउ के अलावा, पूरे चीन में अफ्रीकी–विरोधी (आमतौर पर अश्वेत–विरोधी) भावना के कई मामले दर्ज किए गए हैं। एक उल्लेखनीय मामला 1980 के दशक का "कैंपस–नस्लवाद" है, जिसमें अफ्रीकी छात्रों को अपने चीनी साथियों से नस्लीय रूप से प्रेरित प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। चीनी महिलाओं के साथ अपने संबंधों के माध्यम से अफ्रीकी लोगों को चीनी समाज को "प्रदूषित" करने वाले, पिछड़े और आलसी के रूप में चित्रित किया गया था, और चीन की सहायता के अयोग्य माना गया था।

इस तरह की नस्लीय सोच समय के साथ बनी रही है और अब इसे वीचौट और वीबो जैसे चीनी सोशल मीडिया चौनलों पर एक मंच मिल गया है, जहाँ अफ्रीकियों के खिलाफ नस्लीय गालियाँ मिलना असामान्य नहीं है। चीनी उपयोगकर्ता अक्सर अफ्रीका और अफ्रीकियों की अपमानजनक छवि बनाते हैं, जो चीन की हालिया सफलताओं और विकास के विपरीत है। अफ्रीकियों को आलसी, अयोग्य और यौन रूप से आक्रामक बताकर, चीनी खुद को मेहनती, योग्य और सम्मानजनक के रूप में पेश करना चाहते हैं। यह चित्रण चीन में अश्वेतता और नस्लीय पहचान के ऐतिहासिक निर्माण को

>>

दर्शाता है, जो अक्सर सांस्कृतिक और नस्लीय श्रेष्ठता की धारणाओं से जुड़े होते हैं, विशेष रूप से वर्चस्वशाली हान समूह की विदेशियों और अन्य चीनी अल्पसंख्यकों पर।

आज, लगभग 500,000 अफ्रीकी प्रवासी चीन में रहते हैं, जो स्थानीय आबादी के साथ अपने व्यवहार में नस्लवाद की विभिन्न धारणाओं का अनुभव करते हैं। जहाँ कुछ लोग स्वयं को स्वीकार किया महसूस करते हैं और भेदभावपूर्ण व्यवहार को अज्ञानता का परिणाम मानते हैं, अन्य लोग अत्यधिक पूर्वाग्रही व्यवहार का सामना करते हैं। अक्सर, चीन में नस्लीय भेदभाव को प्राथमिक रूप से संस्थागत रूप में देखा जाता है। 1980 के दशक के ''कैंपस–नस्लवाद'' के विपरीत, अक्सर (अवैध) अफ्रीकी निवासियों और शत्रुतापूर्ण अधिकारियों के बीच झड़पें होती हैं, जिन्हें अफ्रीकियों के खिलाफ प्रवास और कानून प्रवर्तन उपायों को अनुचित तरीके से लागू करते देखा जाता है। कई लोगों ने द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक सौदों को खतरे में डालने के डर से, चीन में अपने नागरिकों की शिकायतों को दूर करने में विफल रहने के लिए अफ्रीकी सरकारों को दोषी ठहराया है।

चीनी सरकार ने नस्लीय विवादों को लगातार कमतर आँका है, तथा अफ्रीकी विरोधी भावना के मामलों को अलग–थलग बताकर खारिज कर दिया है, तथा इस बात पर जोर दिया है कि नस्लवाद एक पश्चिमी समस्या है। हालांकि, ग्वांगझोउ में व्यापक रूप से प्रचारित घटनाओं और अफ्रीकी प्रवासियों और सरकारों की नाराजगी के बाद, चीनी अधिकारियों को नस्लीय पूर्वाग्रहों के अस्तित्व को सावधानीपूर्वक स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। विशेष परिस्थितियों में, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए सांकेतिक उपाय लागू किए गए हैं, जैसे कि कोविड–19 प्रतिबंधों के दौरान सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की सुविधा के लिए स्वास्थ्य ऐप प्रणाली तक विदेशियों की पहुँच में सुधार करना ।

हालांकि, ऐसे उपायों में नस्लवाद और भेदभाव को प्रणालीगत और व्यापक लक्षणों के बजाय आकस्मिक और स्थानीय मुद्दों के रूप में माना जाता है। जैसे चीन नस्लवाद विरोधी एजेंडे सहित मानवाधिकार वकालत और सक्रियता पर कड़े प्रतिबंध लगाता है, गहन रूप से जड़ चुनौतियां बनी रहती हैं। राजनीतिक और मीडिया स्थानों पर सरकार के सख्त नियंत्रण के बावजूद, इसने अभी तक चीनी समाज के भीतर (ऑनलाइन) नस्लीय प्रवचनों और व्यवहारों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए हैं।

> अफ्रीका में चीनी

अफ्रीका में चीनी उपस्थिति की जांच करते समय, नस्लीय भेदभाव और तनाव पर आम तौर पर श्रम संबंधों के संदर्भ में चर्चा की जाती है, विशेष रूप से चीनी निर्माण परियोजनाओं में। चीनी नियोक्ताओं, प्रबंधकों और श्रमिकों की अपने अफ्रीकी समकक्षों, आलोचना की गई है, जिन्हें आलसी, अविश्वसनीय और अविश्वसनीय के रूप में चित्रित किया गया है, की कार्य आदतों और प्रथाओं का उल्लेख करते समय नस्लवादी व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए आलोचना की गई है। चीनियों पर स्व–पृथक्करण में संलग्न होने का आरोप भी लगाया गया है: विविधता के प्रति नापसंदगी के कारण निवास, भाषा और समाजीकरण प्रथाओं के संदर्भ में खुद को अफ्रीकियों से अलग करने के चयन के कारण। इसके बावजूद, अफ्रीका में चीनी नस्लवाद की सामान्य व्याख्या के खिलाफ अन्य लोगों ने चेतावनी दी है। हमें स्मरण होता है कि श्रम असमानताएं और स्व–पृथक्करण के प्रतिमान लंबे समय से (और बने हुए हैं) महाद्वीप में पश्चिमी उपस्थिति की एक विशेषता है और चीनियों द्वारा भाषा–उपार्जन और सामाजिक एकीकरण के सफल मामले हैं।

इसके साथ ही, अफ्रीकी हितधारकों के मध्य शत्रुता और चीन विरोधी भावना के स्पष्ट पैटर्न उभर रहे हैं। एक विचारधारा यह सुझाव देती है कि अफ्रीकी एजेंसी को स्वीकार करते हुए, चीनी लोगों के अफ्रीकी नस्लीयकरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अफ्रीका में चीनी विरोधी दृष्टिकोण ज्यादातर आर्थिक समूहों से आते हैं जो चीनी उद्यमियों और श्रमिकों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में हैं, उदाहरण के लिए, वे जो नौकरी खो देते हैं या अनिश्चित कार्य स्थितियों का अनुभव करते हैं। अक्सर, अफ्रीका में शिकारी या नव–औपनिवेशिक गतिविधियों में संलग्न ''पीले जोखिम'' के रूप में चीन का नकारात्मक चित्रण– पश्चिमी नीति और मीडिया चित्रण में आम है।यह इन भावनाओं को बढ़ाने में योगदान देता है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि श्वेतता, अश्वेतता और चीनीपन के मध्य एक जटिल अंतर्संबंध सम्मिलित कर अफ्रीका–चीन संबंधों को भी बाहरी कर्त्ताओं द्वारा कैसे नस्लीय बनाया जाता है।

अफ्रीकी नेता कभी–कभी राजनीतिक लाभ के लिए चीनियों के प्रति नकारात्मक भावनाओं का लाभ उठाते हैं, कभी–कभी नस्लीय राष्ट्रवाद की रणनीतियों का सहारा लेते हैं। चीन की आलोचना करना सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के लिए जांच से ध्यान हटाने और भेद्यता के समय में राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण के रूप में काम कर सकता हैय जबकि विपक्षी समूह मौजूदा दलों को चुनौती देने के लिए चीन विरोधी बयानबाजी का उपयोग कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण जाम्बियन राजनेता माइकल साटा का है, जिन्होंने 2011 में चीनी विरोधी मंच पर राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार किया था। हालाँकि, पद संभालने के बाद, उन्होंने अपनी बयानबाजी को संशोधित किया और चीन के साथ आर्थिक संबंधों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया।

फिर भी, इन गतिशीलता को हमेशा संदर्भ में रखना और स्थानीय, राष्ट्रीय और सुपरानेशनल पैमानों पर अंतर करना महत्वपूर्ण है। कई अफ्रीकी राज्यों में, चीन के निवेश, व्यापार और समग्र विकास सफलताओं की सराहना करते हुए, स्थानीय आबादी आम तौर पर चीनियों का स्वागत करती है। तथापि, जबकि अफ्रीकी चीन के साथ अपने संबंधों को महत्व देते हैं, वे किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। महामारी के दौरान गुआंगजोउ में अफ्रीकियों के विरूद्ध शत्रुता की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष क्वेसी कर्तेय द्वारा घोषित किया गया था। जैसा कि अफ्रीकी संघ के उपाध्यक्ष क्वेसी क्वार्टी ने महामारी के दौरान ग्वांगझू में अफ्रीकियों के खिलाफ शत्रुता के जवाब में घोषित किया था। यह नस्ल–संबंधी मुद्दों के राजनीतिक महत्व और दोनों पक्षों के लिए उनके साथ सार्थक रूप से जुड़ने की आवश्यकता को उजागर करता है। ऐसा करना उभरती और उत्तरोत्तर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच अक्सर चीन–अफ्रीकी मित्रता के रूप में संदर्भित की जाने वाली दोस्ती को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ■

सभी पत्राचार
एरिक सेजने को <e.m.cezne@uu.nl> एवं
रूस विसर को <rv_visser@outlook.com> पर प्रेषित करें।

> अंगोला और क्यूबा का अग्रणी

दक्षिण–दक्षिण सहयोग (1975–1991)

क्रिस्टीन हेट्जकी, लीबनिज यूनिवर्सिटी हनोवर, जर्मनी द्वारा

1975 में अंगोलन कमांडर और पूर्वी मोर्चे के क्यूबा के प्रमुख जनरल, डेंजरेक्स किमेंगा और कार्लोस फर्नांडीज गोंडिन। श्रेय : अल्फोंसो नारंजो रोसाबल / विकिमीडिया कॉमन्स.

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के विशेष लक्षण क्या हैं? कुछ मामलों में, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसमें दो पूर्व उपनिवेशित देशों की सरकारों, संस्थाओं, सशस्त्र बलों और आबादी के मध्य सहयोग शामिल है। मैं अंगोला और क्यूबा के उदाहरण का उपयोग करके इसे स्पष्ट करुँगी, और उन विशिष्टताओं और ऐतिहासिक संदर्भों को रेखांकित करुँगी जिनसे यह सहयोग उभरा। यह परियोजना पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के मध्य दुनिया के विभाजन की पृष्ठभूमि में, उपनिवेशवाद के उन्मूलन के दौर में हुई। इस युग की विशेषता यह भी थी कि अभी भी यह आशा बनी हुई थी कि पूर्व उपनिवेशित देशों के मध्य मजबूत सामंजस्य पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर विजय पाने में सक्षम होगा, तथा इन दो प्रणालियों से परे विकास का अपना मार्ग बनाएगा।

क्यूबा और अंगोला का मामला दो वामपंथी परियोजनाओं के बीच सहयोग का मामला है: द पीपलस मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला (एमपीएलए) और क्यूबा सरकार। प्रथम ने अभी तक अपनी अंतिम दिशा निर्धारित नहीं की थी, परवर्ती समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन सोवियत प्रणाली की राजनीतिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीयतावादी एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित, दोनों देशों के मध्य सहयोग का उद्देश्य एक उपनिवेशवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी ट्रान्साटलांटिक गठबंधन की स्थापना करना था, जो अमेरिकी आधिपत्य का विरोध करेगा। चूँकि, अंगोला भी कच्चे माल (तेल, अयस्कों, हीरे) में समृद्ध था(और अभी भी है), इस तरह के सहयोग ने क्यूबा को सोवियत संघ से अधिक आर्थिक (और इस प्रकार अधिक राजनीतिक) स्वतंत्रता की संभावना के साथ–साथ 1960 में अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए आर्थिक नाकेबंदी को दरकिनार करने का अवसर प्रदान किया।

हालाँकि यह बराबरी के लोगों के मध्य सहयोग था, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं था और प्रत्येक पक्ष ने हमेशा अपने स्वयं के राजनीतिक और आर्थिक हितों का पीछा किया। बेशक, इन पदानुक्रमों में दोनों पक्षों की नस्लवादी धारणाएँ भी शामिल थीं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया – कम से कम आधिकारिक चर्चा में तो नहीं। उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के विमर्श में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं थी। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में मुक्ति आंदोलनों और स्वतंत्र सरकारों के मध्य सामंजस्य को मजबूत करने के उद्देश्य से, मौजूदा पदानुक्रम और नस्लीयकरण को उपनिवेशवाद–विरोधी और नस्लवाद–विरोधी एकजुटता की बयानबाजी द्वारा छुपाया गया था।

> सैन्य सहायता के साथ–साथ नागरिक सहयोग

1975 में पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध के अंत में और उसके बाद MPLA के प्रतिद्वंद्वियों – FNLA और यूनिटा – और उनके साथ संबद्ध दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद शासन के खिलाफ उपनिवेशवाद के बाद के युद्ध में, लगभग 400,000 क्यूबा के सैनिकों ने 1991 तक MPLA बलों के साथ लड़ाई लड़ी। इस सैन्य सहयोग से नागरिक सहयोग विकसित हुआ, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि एक स्वतंत्र अंगोला को केवल सैन्य सहायता से कहीं अधिक की आवश्यकता थी: सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक

>>

क्षेत्रों में पुनर्निर्माण सहायता। इसलिए, स्वतंत्र अंगोला के राष्ट्रपति, अगोस्तिन्हो नेटो ने क्यूबा सरकार से अतिरिक्त नागरिक सहायता देने के लिए कहा, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में। क्यूबा सरकार सहमत हो गई और उन्होंने सभी स्तरों पर विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों के माध्यम से अपना ज्ञान उपलब्ध कराया, और 1991 तक लगभग 50,000 क्यूबा के नागरिक अंगोला में काम कर रहे थे। इनमें मंत्रालयों के सलाहकार, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और शिक्षक शामिल थे, जिन्होंने उग्र आंतरिक युद्ध की परवाह किए बिना इन सभी क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं के विकास का समर्थन किया।

प्रारंभ में इस सहायता का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के लिए मदद था, लेकिन योग्य अंगोलावासियों की कमी के कारण, कई क्षेत्रों में क्यूबावासियों को आगे आना पड़ा। यह प्रोग्राम विशेष रूप से अंगोलन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था और इसे द्विराष्ट्रीय अंगोलन–क्यूबा टीमों द्वारा व्यवस्थित और समन्वित किया गया था। नागरिक सहयोग की शर्तों को विस्तृत अनुबंधों में परिभाषित किया गया था, जिसमें सेवा के लिए भुगतान भी शामिल था। अंगोलन सरकार ने काम के लिए क्यूबा सरकार को सीधे भुगतान किया और साथ में उन्होंने आवास, परिवहन और भोजन के साथ–साथ सहयोगियों के लिए मामूली भत्ता भी प्रदान किया। अंततः, 1988 में दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा और अंगोला के बीच न्यूयॉर्क समझौते के साथ यह सहयोग समाप्त हो गया, जिसने अंगोला से क्यूबा और दक्षिण अफ्रीकी सैनिकों और नागरिकों की वापसी को सील कर दिया और 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता की स्थापना की, जो रंगभेद शासन के पतन में एक और मील का पत्थर था।

कुल मिलाकर, यह इतिहास में दो पूर्व उपनिवेशित देशों के बीच दक्षिण–दक्षिण सहयोग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक प्रकरण था। इस सहयोग में नस्लीय पदानुक्रम का प्रश्न जटिल है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे अंगोलन या क्यूबा के दृष्टिकोण से उठाया गया है या नहीं। सहयोग के रोजमर्रा के जीवन में आत्म–धारणाएँ और आपसी धारणाएँ, जिन्हें मैंने क्यूबा और अंगोलन भागीदारों के साक्षात्कारों के आधार पर, अपने प्रकाशन में खोजी हैं, मौजूदा और कथित पदानुक्रमों के पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

> उपनिवेशवाद और गुलामी के माध्यम से जुड़े देश

इस सहयोग की पृष्ठभूमि और प्रेरणा को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। सोलहवीं शताब्दी से ही ट्रान्साटलांटिक दास व्यापार के माध्यम से दोनों देश स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेशवाद से जुड़े हुए थे। इसके परिणामस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक लगभग दस लाख अफ्रीकियों को क्यूबा के चीनी बागानों में निर्वासित किया गया था। अफ्रीकी मूल के इन लोगों में से कई ने स्पेनिश साम्राज्य (1868–1898) के खिलाफ क्यूबा के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष फिदेल कास्त्रो ने 1975 में MPLA के साथ सैन्य सहयोग को उचित ठहराते हुए इसका उल्लेख किया था। उन्होंने क्यूबावासियों को ऐतिहासिक रूप से ऋणी और पुर्तगालियों (1960–1975) के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने अफ्रीकी भाइयों का समर्थन करने के लिए बाध्य माना, और क्यूबा को एक ''लैटिन अमेरिकी–अफ्रीकी'' राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया।

इबेरियाई उपनिवेशवाद के साझा अनुभव से उत्पन्न सांस्कृतिक और भाषाई अनुकूलता ने कम से कम सहयोग को सुगम बनाया। उस समय अंगोला और क्यूबा के लोगों के बीच नस्लीय पदानुक्रम की धारणा की तुलना में साझा आधार अधिक महत्वपूर्ण था। औपनिवेशिक और उत्तर–औपनिवेशिक वर्चस्व के रूपों पर काबू पाने में कालानुक्रमिक लाभ के कारण एक पदानुक्रम निश्चित रूप से मौजूद था जो 1959 के आंदोलन से तीव्र हुआ, जिसका अंतर्राष्ट्रीयवाद एक गैर–औपनिवेशिक, समतावादी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवंत–गार्डे परियोजना से जुड़ा था।

> वैश्विक विउपनिवेशीकरण और ट्राइकॉन्ट का उदय

क्यूबा ने जिस क्रांति के साथ खुद को अमेरिका की साम्राज्यवादी पकड़ से मुक्त किया (जिसने 1898 में अमेरिका में प्रमुख शक्ति के रूप में स्पेनिश उपनिवेशवाद की जगह ली थी) वह वैश्विक विउपनिवेशीकरण के युग में हुई थी। 1955 में, 29 से अधिक संप्रभु राज्य और 30 मुक्ति आंदोलन उपनिवेशवाद के अंत पर चर्चा करने के लिए बांडुंग (इंडोनेशिया) में मिले। वहाँ ''तीसरी दुनिया'' (जिसे बाद में ''ट्रिकोंट'' कहा गया) शब्द ''पहले'' पूंजीवादी और साम्राज्यवादी दुनिया और ''दूसरे'' समाजवादी दुनिया के विपरीत, चीन के अपवाद के साथ, विकास के ''तीसरे रास्ते'' का प्रतीक था।

1950 के दशक के अंत में अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अंत के साथ, क्यूबा के क्रांतिकारियों ने वहां उपनिवेश–विरोधी आंदोलनों और सरकारों के साथ संबंध स्थापित किए। 1961 में शीत युद्ध की परिणति पर – जब क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया– बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई, जिसमें भाग लेने वाला एकमात्र लैटिन अमेरिकी राज्य क्यूबा था। 1966 में, हवाना में ''ट्राईकॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस'' हुई, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 82 उपनिवेश–विरोधी आंदोलनों और सरकारों ने भाग लिया। इस सम्मलेन का उद्देश्य ''अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता'' की भावना में क्यूबा के नेतृत्व में उपनिवेश–विरोधी विश्व क्रांति की तैयारी करना था। 1970 के दशक के प्रारम्भ में, क्यूबा ''तीसरी दुनिया'' का पहला देश था जिसे द्वीप के आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ब्ड्म। के समाजवादी आर्थिक समुदाय में स्वीकार किया गया था। पूर्वी ब्लॉक राज्यों और सोवियत संघ से प्राप्त इस आर्थिक सहायता से अंगोला और कई अन्य ट्राइकॉन्ट देशों के साथ व्यापक दक्षिण–दक्षिण सहयोग स्थापित करना संभव हो सका। ■

सभी पत्राचार क्रिस्टीन हेट्जकी को <christine.hatzky@hist.uni-hannover.de> पर प्रेषित करें।

> क्या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में नस्लीय पदानुक्रम को समाप्त किया जा सकता है?

सारा वॉन बिलरबेक, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूके, और **केसेनिया ओक्सामित्ना**, सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूके द्वारा

श्रेय : सारा वॉन बिलरबेक।

समकालीन वैश्विक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक संयुक्त राष्ट्र है। दुनिया भर के लगभग सभी राज्यों को एक साथ लाते हुए, इसमें सहयोग के कई वेक्टर शामिल हैं: उत्तर–उत्तर, उत्तर–दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण। निस्संदेह, संयुक्त राष्ट्र स्वयं का अस्तित्व इस धारणा पर आधारित है कि एक संस्थागत मंच जहाँ राज्य समान रूप से संरचित सहयोग में संलग्न हो सकते हैं, संघर्ष से बचने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा। फिर भी संयुक्त राष्ट्र के भीतर राज्यों के मध्य समानता पर लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं और हाल के शोध से पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र की संरचना न केवल निर्णय लेने की प्रक्रियाओं (विशेष रूप से वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के मध्य, उदहारण के लिए सुरक्षा परिषद् में) तक अलग–अलग पहुँच के माध्यम से राज्यों के मध्य असमानता को संस्थागत बनाती है, बल्कि यह कि संरचनाएँ अक्सर मूल रूप से नस्लीय होती हैं और इस प्रकार उनके भीतर पदानुक्रम भी नस्लीय होते हैं। जैसा कि इस विषयगत अंक के परिचय में वर्णित है, हम जाति को एक सामाजिक निर्माण के रूप में समझते हैं जिसमें अपरिवर्तनीय मानी जाने वाली विशेषताओं के आधार पर समूहों को अलग करना और रैंकिंग करना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक संसाधनों तक असमान पहुँच होती है।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच नस्लीय असमानताओं की मान्यता के बावजूद, विद्वान हाल ही तक यह जांचने में विफल रहे हैं कि इस तरह के पदानुक्रम कैसे अस्तित्व में आते हैं, दोहराए जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के भीतर कैसे स्थापित हो जाते हैं – यानी कि संगठन के कार्यबल के भीतर। ''रेस एंड इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन'' नामक हमारे हालिया लेख में, हम संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की जांच करते हैं और रे के (2019) नस्लीय संगठनों के सिद्धांत पर आधारित, चार तंत्रों के प्रमाण पाते हैं जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के भीतर नस्लीय पदानुक्रम कायम रहते हैं।

> विभेदक एजेंसी, नस्लीय वितरण, प्रमाणन, और नस्लीय वियोजन

सबसे पहले, हम विभिन्न नस्लीय समूहों के कर्मियों की कम या बढ़ी हुई एजेंसी देखते हैं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सभी नए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान गैर–श्वेत–बहुल देशों जैसे अफ्रीका, एशिया और कैरेबियन में हुए हैं, यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कर्मचारियों के मध्य अंतर में स्पष्ट है। राष्ट्रीय कर्मचारी अक्सर सहायक भूमिकाओं में काम करते हैं, उदाहरण के लिए ड्राइवर या अनुवादक के रूप में, या उन्हें स्थानीय और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए कहा जाता है। इन भूमिकाओं को अधिक ''महत्वपूर्ण'' काम से कम महत्व दिया जाता है, और इस प्रकार राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के भीतर निम्न स्थिति के साथ नस्ल–प्रकार की नौकरियों में संकेंद्रित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के मध्य महत्वपूर्ण वेतन अंतर से यह और अधिक गहरा हो जाता है। शांति स्थापना में नस्लीय समूहों की एजेंसी वरिष्ठ पदों पर गैर–श्वेत कर्मियों की प्रतीकात्मक नियुक्ति के माध्यम से भी कम हो गई है।

दूसरा, हमें संगठनात्मक संसाधनों के नस्लीय वितरण के प्रमाण मिलते हैं। शांति सैनिकों के लिए प्रमुख संसाधनों में से एक शारीरिक सुरक्षा है, जिसे श्वेत कर्मियों द्वारा जमा किया जा सकता है। नागरिक शांति सैनिकों में, राष्ट्रीय कर्मचारियों को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसे वे अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की तुलना में कम करने में कम सक्षम हैं: उदाहरण के लिए, उन्हें आमतौर पर संकट के दौरान निकाला नहीं जाता है। इसी तरह, गैर–श्वेत–बहुल देशों के सैनिकों को श्वेत–बहुल देशों के सैनिकों की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, माली में MINUSMA में, बेहतर उपकरणों और तकनीक वाले यूरोपीय सैनिकों ने टोही और खुफिया भूमिकाएँ निभाईं, जिससे गश्त का अधिक खतरनाक काम अफ्रीकी सैनिकों के पास रह गया।

तीसरा, हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि श्वेतता एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करती है। शांति स्थापना में कुछ कार्यों और कौशलों को अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, जैसे कि सैन्य योजना बनाना या मानवाधिकारों या सुरक्षा क्षेत्र सुधार के बारे में विषयगत

>>

ज्ञान प्रदान करना। श्वेत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को अक्सर ऐसी भूमिकाएँ निभाने में सक्षम माना जाता है, जबकि गैर–श्वेत राष्ट्रीय कर्मचारी स्थानीय या सांस्कृतिक ज्ञान से जुड़े होते हैं, जिसे कम ''परिष्कृत'' माना जाता है। सैन्य पक्ष में, श्वेतता और व्यावसायिकता के मध्य संबंध और भी मजबूत हैं, जिसके कारण ऐसा श्रम का विभाजन होता है जिसके तहत यूरोप या उत्तरी अमेरिका से श्वेत सैनिकों को योजना और रणनीति भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि गश्त और संचालन का कार्य एशिया और विशेष रूप से अफ्रीका से गैर–श्वेत सैनिकों को दिया जाता है ।

अंततः, नस्लीय आधार पर अलगाव के प्रमाण मिलते हैं, जहां श्वेत सैनिक संगठनात्मक नियमों को दरकिनार करते हुए विशेष बर्ताव पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, श्वेत–बहुल देशों के सैनिकों ने विशेष परिवहन व्यवस्था, बड़े राशन और सौदेबाजी के जरिए द्विपक्षीय चिकित्सा और निकासी समझौतों की मांग की है। यद्यपि तकनीकी रूप से ऐसी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इस धारणा को मजबूत करते हैं कि मानक संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाएँ कुछ लोगों के लिए – गैर–श्वेत–बहुल देशों के सैनिकों के लिए – पर्याप्त हैं, लेकिन अन्य के लिए नहीं। निस्संदेह, शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस बल का योगदान देने से देशों को प्रतिपूर्ति से लेकर तख्तापलट तक के लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, इसका अक्सर यह अर्थ होता है कि इन देशों – जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में हैं– के पास ग्लोबल नॉर्थ देशों की तुलना में अपने कर्मियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों पर सौदेबाजी करने की कम क्षमता है।

ये नस्लीय पदानुक्रम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य शक्ति और धन के असमान वितरण, विशिष्ट संगठनात्मक प्रक्रियाओं और पथ निर्भरताओं, और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का परिणाम हैं। लेकिन क्या उन्हें खत्म करना संभव है?

> अधिकारियों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास

संयुक्त राष्ट्र ने अपने कार्यबल के भीतर नस्लीय असमानता और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए कुछ उपाय अपनाए हैं। 2020 में, ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के बाद, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कई पहल शुरू कीं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में नस्लवाद को संबोधित करने और सभी के लिए सम्मान को बढ़ावा देने पर टास्क फोर्स। उसी वर्ष कर्मचारियों की धारणाओं के एक सर्वेक्षण ने खुलासा किया कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक तिहाई कर्मचारियों का मानना था कि संगठन की भर्ती प्रथाएँ नस्ल, राष्ट्रीयता या जातीयता के आधार पर भेदभावपूर्ण थीं। इसी तरह के प्रतिशत ने भेदभाव का अनुभव होने की सूचना दी, जिसमें अश्वेत या अफ्रीकी के रूप में पहचाने जाने वाले लोग विशेष रूप से प्रभावित हुए।

2022 में, संयुक्त राष्ट्र ने विविधता और सहभागिता के प्रमुख की नियुक्ति की और संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद को संबोधित करने और सभी के लिए सम्मान को बढ़ावा देने पर विशेष सलाहकार का पद स्थापित किया। सचिवालय ने विविधता, समानता और समावेशन कार्यालय की स्थापना के लिए भी धनकोष का अनुरोध किया, लेकिन प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी।

संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के वेतन में भी वृद्धि की है। उदाहरण के लिए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में, उच्चतम रैंकिंग वाली पेशेवर श्रेणी में राष्ट्रीय कर्मचारियों का वार्षिक वेतन $84,735 है, जो मध्यम रैंकिंग वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों (पी–3), जिन्हें $77,884 का भुगतान किया जाता है, के बराबर है। हालाँकि, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्ते शामिल नहीं हैं। सामान्य सेवा श्रेणी में सबसे कम वेतन पाने वाले राष्ट्रीय कर्मचारी, जिसमें अधिकांश राष्ट्रीय कर्मचारी आते हैं, को प्रति वर्ष केवल $7,690 मिलते हैं।

इसके अलावा, शांति स्थापना और विशेष राजनीतिक मिशनों का प्रबंधन करने वाले विभागों में एक अंतर–विभागीय नस्लवाद विरोधी कार्य समूह बनाया गया। विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस समूह के काम का समर्थन करने के लिए अपने जिनेवा मुख्यालय में एक अवैतनिक इंटर्नशिप का विज्ञापन दियाय अवैतनिक इंटर्नशिप केवल स्वतंत्र साधनों वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जो आमतौर पर श्वेत–बहुल देशों से आते हैं, जो ठीक उन्हीं असमानताओं को बढ़ावा देता है जिन्हें संबोधित करने का यह समूह दावा करता है।

अंत में, संयुक्त राष्ट्र ने नस्लवाद विरोधी संदेशों को दोहराने के लिए एक आंतरिक संचार मंच शुरू किया, फिर भी यह विशुद्ध रूप से एक आत्म–वैधीकरण उपकरण बना रह सकता है, खासकर अगर यह एकतरफा, ऊपर से नीचे संचार तक सीमित है। अन्य उपाय, जैसे कि अचेतन पूर्वाग्रहों पर प्रशिक्षण या भेदभाव के पिछले दावों की समीक्षा, द्वारा अल्पावधि में बदलाव लाने की संभावना नहीं है। इन सबके मद्देनजर, संरचनात्मक परिवर्तन के अभाव में नस्लवाद को संबोधित करने के लिए सचिवालय की योजनाएँ प्रभावी होंगी या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। ■

सभी पत्राचार
सारा वॉन बिलरबेक को <s.b.k.vonbillerbeck@reading.ac.uk> एवं
केसेनिया ओक्साम्यत्ना को <Kseniya.Oksamytna@city.ac.uk> पर प्रेषित करें।

> डीग्रोथ, वैश्विक विषमताएं और पारिस्थितिक–सामाजिक न्याय

मिरियम लैंग, यूनिवर्सिडाड एंडिना सिमोन बोलिवर, इक्वाडोर द्वारा

विश्व बैंक स्प्रिंग मीटिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन , वाशिंगटन डीसी, अप्रैल 2024। फोटो : मिरियम लैंग।

डीग्रोथ मुख्य रूप से भू–राजनीतिक उत्तर के देशों, विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों से और के दृष्टिकोण के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों के बारे में, कई डीग्रोथ प्रस्तावक स्पष्ट करते हैं कि डीग्रोथ एजेंडा सभी विश्व क्षेत्रों के लिए मान्य एक सार्वभौमिक परिवर्तनकारी पथ के विचार को खारिज करते हुए परिवर्तन के लिए कोई सार्वभौमिक नुस्खा नहीं है। इसके बजाय, वे कहते हैं कि उत्तरी उच्च आय वाले देशों में डीग्रोथ पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के परिधि पर स्थित देशों या अर्थव्यवस्थाओं के लिए ''पारिस्थितिक स्थान को बढ़ाने'' या ''वैचारिक स्थान को मुक्त करने'' के लिए आवश्यक है, ताकि उन्हें ''जिसे वे अच्छे जीवन के रूप में परिभाषित करते हैं, के लिए अपने स्वयं के प्रक्षेपवक्र को खोजने की अनुमति मिल सके''। एक पूरक तर्क यह है कि वैश्विक दक्षिण के गरीब देशों को लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ने की जरूरत है। यह निर्धनता, आवश्यकताओं और कल्याण की विशिष्ट मुख्यधारा की समझ के इर्द–गिर्द विकसित होता है, जो भौतिक प्रचुरता बनाम अभाव से जुड़ा है, जो वैश्विक दक्षिण में हाल की बहसों के आलोक में संदिग्ध प्रतीत होता है।

यह लेख वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण, पारिस्थितिक परिवर्तन लाने के कार्य को ध्यान में रखते हुए डीग्रोथ की कुछ ताकत और कमजोरियों को रेखांकित करने का प्रयास करता है, और इस संदर्भ में कुछ वैश्विक बहसों के साथ क्रॉस–फर्टिलाइजेशन की संभावनाओं की खोज करता है। लेख दो मुख्य तर्कों के इर्द–गिर्द संगठित है: सबसे पहले, मैं एक आंदोलन के रूप में और एक शोध एजेंडे के रूप में – डीग्रोथ और वैश्विक दक्षिण के बीच मौजूदा संवादों, प्रतिध्वनि और (गैर–) जुड़ावों का सारांश प्रस्तुत करूँगी। और दूसरा, मैं इस दावे की सीमाओं को उजागर करूँगी कि उत्तर में डीग्रोथ ''दक्षिण के लिए स्थान खोलेगा''। यह इंगित करेगा कि कुछ बहसें डीग्रोथ और इसके विपरीत के लिए कहाँ लाभदायक हो सकती हैं और वे (हरित) विकास के खिलाफ गैर–औपनिवेशिक उत्तर–दक्षिण गठबंधनों की आवश्यकता को स्थापित करती हैं।

> दक्षिण से डीग्रोथ और वैकल्पिक प्रतिमानों के बीच तालमेल

जैसा कि डीग्रोथ समर्थकों ने बताया है, डीग्रोथ की अवधारणा वैश्विक दक्षिण में बहुत अधिक गतिशील नहीं हो सकती है, जहाँ 'अविकसितता' के प्रतिमान का अभी भी लोगों की व्यक्तिपरकता पर गहरा प्रभाव है। लेकिन दक्षिण में परिवर्तन के लिए डीग्रोथ को एक मार्गदर्शक अवधारणा बनने की भी आवश्यकता नहीं है।

> >

लैटिन अमेरिकी लेखक, जैसे आर्टुरो एस्कोबार, एडुआर्डो गुडीनास, अल्बर्टो अकोस्टा और अन्य ने डीग्रोथ और उत्तर–निष्कर्षवाद, उत्तर–विकासवाद और स्वदेशी विश्वदृष्टिकोण जैसे सुमाक कावसे के बीच कुछ अभिसरण और तालमेल का प्रमाण दिया है, जिन्हें आवश्यक उत्तर–दक्षिण गठबंधनों के परिप्रेक्ष्य में और अधिक खोजा जाना चाहिए।

सुमाक कावसाय और डीग्रोथ दोनों ही असीमित प्रगति और विस्तार के आधुनिक विचार को अस्वीकार करते हैं और एक अच्छे जीवन के बारे में मात्रात्मक कारकों के बजाय गुणात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों ही आधुनिक पूंजीवाद द्वारा प्रेरित असीमित आवश्यकताओं की धारणा को भी अस्वीकार करते हैं और सीमाओं की वकालत करते हैं: कट्टरपंथी लोकतंत्र के सामूहिक, जानबूझकर किए गए अभ्यास में डीग्रोथ ''सीमाओं को हम पर बाहरी रूप से थोपी गई चीज के रूप में नहीं, बल्कि आत्म–सीमा के एक सचेत विकल्प के रूप में देखता है''; पूंजीवादी संचय के लिए सुमाक कावसाय निष्क्रिय है क्योंकि यह उभरती असमानताओं को फिर से संतुलित करने का प्रयास करता है और उन्हें सामुदायिक जीवन के लिए खतरा मानता है। यह प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और पारस्परिकता को भी बढ़ावा देता है। दोनों इस विचार को अपनाते हैं कि स्वायत्तता, सामूहिक स्वशासन या स्वतंत्रता का अर्थ है मनमाने ढंग से या बाहरी रूप से थोपे गए नियमों का पालन करने के बजाय खुद को आचरण के नियम और इस तरह सीमाएँ देना।

हालांकि, लैटिन अमेरिका के विकास–विरोधी और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के बीच समृद्ध वैचारिक संवाद को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन वैश्विक संवादों के परिप्रेक्ष्य से यह समस्याजनक है कि विकास–विरोधी समर्थक आधुनिक–औपनिवेशिक वैश्वीकृत विश्व में गहरी उलझनों और अंतर–निर्भरताओं के साथ विश्लेषणात्मक रूप से जुड़े बिना अपने नीतिगत प्रस्तावों को मुख्य रूप से केवल 'वैश्विक उत्तर से और उसके लिए' तैयार करते हैं ।

> उत्तर में डीग्रोथ पर्याप्त नहीं है

जैसा कि शुरू में बताया गया था, डीग्रोथ साहित्य में एक आवर्ती थीसिस यह है कि वैश्विक उत्तर के उच्च आय वाले देशों में डीग्रोथ वैश्विक दक्षिण के लिए 'वैचारिक स्थान' या 'पारिस्थितिक स्थान' को मुक्त करेगा। जेसन हिकेल जैसे कुछ लेखक यहां तक दावा करते हैं कि डीग्रोथ एक गैर–औपनिवेशिक रणनीति है। मैं जेसन हिकेल से दृढ़ता से सहमत हूं कि दक्षिणी देशों को उत्तरी विकास की सेवा करने के बजाय स्व–परिभाषित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों और श्रम को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। हालांकि यह तभी होगा जब वैश्विक पूंजीवादी विश्व व्यवस्था की संरचनाओं, संस्थानों और नियमों को बदल दिया जाएगा और दक्षिण के देशों के लिए पैंतरेबाजी के लिए वास्तविक जगह बनाई जाएगी। और इसके लिए क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों गठबंधनों की आवश्यकता है।

फिर से, आइए हाल के लैटिन अमेरिकी अनुभव पर नजर डालें। यहां तक कि जब कमोबेश वामपंथी सरकारों (2000–2015) ने नवउदारवाद को पीछे छोड़ने और शोषणवाद पर काबू पाने का दावा किया, तो क्षेत्र में एक असाधारण भू–राजनीतिक समूह का निर्माण हुआ, संबंधित देश स्थायी क्षेत्रीय एकीकरण की एक स्व–निर्धारित, अंतर्जात प्रक्रिया को प्राप्त नहीं कर सके। इसके बजाय, उन्होंने कच्चे माल के निर्यात में एक–दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिससे चीन और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि हुई। इस संदर्भ में लैटिन अमेरिकी सरकारों को सभी देनदारियों से मुक्त करना और अंतर–क्षेत्रीय शक्ति असंतुलन को अनदेखा करना अदूरदर्शिता होगी।

लेकिन वे वैश्विक व्यापार और बौद्धिक संपदा नियमों, वित्त और ऋण गतिशीलता, देश जोखिम रैंकिंग, विवाद निपटान आदि के एक तंग जाल में भी फंस गए थे, जिसने उनकी संभावनाओं को काफी कम कर दिया था। वैश्विक न्याय के दृष्टिकोण से, नियमों का एक जाल एक विषम तरीके से संचालित होता है। एक बार फिर वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में असमान विनिमय और शक्ति असंतुलन संचालित होता है जब लैटिन अमेरिकी देशों को मूलभूत वस्तुओं के निर्यात के लिए जो कीमतें मिलती हैं, वे उनके द्वारा आयात किए जाने वाले प्रसंस्कृत माल के लिए भुगतान की जाने वाली राशि से काफी कम हैं। आज, साम्राज्यवादी विनियोग में न केवल सस्ते अप्रसंस्कृत कच्चे माल शामिल हैं, बल्कि दक्षिण के कुछ क्षेत्र, जो 80 के दशक में दुनिया की फैक्ट्रियां बन गए, से सस्ते श्रम और प्रसंस्कृत सामान भी शामिल हैं: वैश्विक वस्तु श्रृंखलाएं, जहां उत्तरी कंपनियां दक्षिणी आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों को कम करने के लिए एकाधिकार शक्ति का उपयोग करती हैं, जबकि अंतिम कीमतें यथासंभव ऊंची तय करते हुए, फिर भी वैश्विक उत्तर को इस औद्योगिक श्रम को सस्ते में हड़पने की अनुमति देती हैं।

परिणामस्वरूप, दक्षिण को समृद्ध बनाने के लिए वैश्विक उत्तर में सामग्री और ऊर्जा प्रवाह को कम करना एक आवश्यक, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। यदि विषम वैश्विक आर्थिक संरचनाएं अछूती रहती हैं तो दक्षिण में अंतर्जात और संप्रभु सुधारों के लिए वास्तविक 'स्पेसमेकिंग' कच्चे माल की मांग में साधारण कमी के माध्यम से नहीं होगी । इससे कुछ दक्षिणी देशों में भयावह मंदी भी आ सकती है, जिससे बचने की कसम डीग्रोथ समर्थक खाते हैं।

> हरित विकास के विरुद्ध गैर–औपनिवेशिक वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता

टिकाऊ और वैश्विक रूप से न्यायोचित पारिस्थितिक सामाजिक बदलावों के लिए मार्ग खोलने के बजाय, हरित विकास पर केंद्रित जलवायु परिवर्तन के लिए प्राधान्य जवाब वैश्विक दक्षिण के क्षेत्रों पर निष्कर्षणवादी दबाव को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएँ हैं: क) नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक नई औद्योगिक क्रांति के लिए 'रणनीतिक खनिजों' की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनाय ख) 'ऊर्जा सुरक्षा' और ग) वैश्विक उत्तर के लिए अच्छा डीकार्बोनाइजेशन रिकॉर्ड।

वास्तविक ऊर्जा संक्रमण के बजाय, यह समग्र ऊर्जा विस्तार – आर्थिक विकास के लिए एक नया चालक, में परिवर्तित हो जाता है। यूक्रेन युद्ध की भू–राजनीति ने जीवाश्म ईंधन सहित इस विस्तार को और बढ़ा दिया है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के शोध से पता चलता है कि हरित विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह तकनीक–आधारित और कॉर्पोरेट–नेतृत्व वाली प्रक्रिया किस प्रकार कई गुना नए पर्यावरणीय अन्याय और हरित उपनिवेशवाद के रूपों में तब्दील हो जाती है।

हरित वृद्धि की प्राधान्य नीतियाँ वैश्विक दक्षिण के क्षेत्रों को चार प्रकार की भूमिकाएँ प्रदान करती हैं, जिनमें से प्रत्येक में साम्राज्यवादी विनियोग का एक मजबूत आयाम शामिल है: (1) कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण भंडार, जिसे प्रमुख विश्व शक्तियों के डीकार्बोनाइजेशन के लिए उपलब्ध माना जाता है। (2) एक संभावित स्थान जहाँ उत्तर (चीन सहित) में होने वाले CO2 उत्सर्जन को कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं के माध्यम से 'बेअसर' किया जा सकता है, ताकि 'शून्य शुद्ध उत्सर्जन' के लक्ष्य तक पहुँचा जा सके– जिसे यूरोप, अमेरिका या चीन में शून्य वास्तविक उत्सर्जन के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। (3) उत्तर से अपशिष्ट निर्यात के लिए एक प्राप्तकर्ता, जिसमें नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण से निकले

>>

इलेक्ट्रॉनिक और विषाक्त अपशिष्ट शामिल हैं। और अंत में, (4) नई प्रौद्योगिकियों के लिए एक संभावित बाजार जिसे पर्यावरण–आधुनिकीकृत उत्तरी अर्थव्यवस्थाएँ उत्पादित करेंगी और उच्च कीमतों पर बेचेंगी।

वैश्विक पर्यावरण शासन और एक न्यायोचित पारिस्थितिक सामाजिक परिवर्तन के बारे में बहस में डीग्रोथ का एक मुख्य योगदान खुले तौर पर हरित विकास को समस्याग्रस्त बनाना है, जो डीग्रोथ को परिधि के कर्त्ताओं के लिए एक संभावित सहयोगी बनाता है। लेकिन यह केवल तभी ऐसा सहयोगी होगा जब, उसी समय, डीग्रोथ विद्वान और आंदोलन वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक पदानुक्रमों को खत्म करने की रणनीतियों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

मेरा तर्क यह नहीं है कि वैश्विक दक्षिण को सभी गतिविधियों को संकुचित करने के अर्थ में सामान्य रूप से विकास में कमी लानी चाहिए। उत्तर के ऐतिहासिक उत्तरदायित्व और औपनिवेशिक के साथ साथ पर्यावरणीय ऋण को देखते हुए पारिस्थितिक विध्वंस के सामने वैश्विक उत्तर को सामग्री और ऊर्जा प्रवाह में निरपेक्ष कमी में प्रमुख योगदान देना चाहिए। लेकिन आर्थिक विकास को केंद्र से हटाकर, और इसके बजाय ग्रहीय सीमाओं के भीतर जीवन को प्राथमिकता देने से, वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों में हानिकारक उत्पादक और पुनरुत्पादन गतिविधियों की चुनिंदा गिरावट आ सकती है।

उदाहरण के लिए, वैश्विक दक्षिण में इसका अर्थ होगा, निष्कर्षण को कम करना, जिसने विकास के नाम पर न केवल कई सामाजिक समूहों को गरीब बना दिया है, बल्कि स्व–निर्धारित आर्थिक नीतियों की ओर जाने वाले मार्ग पर एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा भी बन गया है। दूसरी ओर, वैश्विक उत्तर में कुछ आवाजों में से एक होने के नाते जो हरित विकास के तर्क पर सवाल उठाती है और संरचनात्मक परिवर्तनों का दावा करती है, डीग्रोथ ऐसे उद्देश्यों के लिए अनुसंधान और राजनीतिक गठबंधन दोनों का हिस्सा बनने के लिए पूर्वनिर्धारित है – लेकिन केवल तभी जब यह वैश्विक दक्षिण में आंदोलनों के साथ वास्तविक संवाद के लिए खुलता है जो वैचारिक अभिसरण से परे जाता है और मौजूदा विषम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए रणनीतियों में संलग्न होता है। ■

सभी पत्राचार मिरियम लैंग को <miriam.lang@uasb.edu.ec> पर प्रेषित करें।

*यह लेख इस पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण है:
लैंग, एम. (2024) "डीग्रोथ, ग्लोबल असीमेट्रीस एंड इकोसोशल जस्टिस: डीकोलोनियल पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका। रिव्यु ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज https://doi.org/10.1017/S0260210524000147.

> नारीवादी डीग्रोथ और पारिस्थितिक–सामाजिक संक्रमण

बेंगी अकबुलुत, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, कनाडा द्वारा

यह लेख डीग्रोथ को एक आधिपत्यवादी–विरोधी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करता है जो परिवर्तन काल की प्रमुख समझ को अस्थिर करता है और उससे आगे निकल जाता है। अर्थव्यवस्था को पुनः केंद्रित करने और पुनः उन्मुख करने (केवल जैवभौतिकी डाउनस्केलिंग के मामले के बजाय) के रूप में डीग्रोथ को समझने पर जोर देते हुए, मैं इस क्षमता के लिए बुनियादी तीन अक्षों को रेखांकित करती हूं जो हैं: (अ) काम का गठन करने वाली एक व्यापक अवधारणा को सामने लानाय (ब) न्याय, विशेष रूप से वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और चल रहे अन्याय के संबंध मेंय और (स) एक डीग्रोथ अर्थव्यवस्था के आयोजन सिद्ध ांतों के रूप में स्वायत्तता और लोकतंत्र।

> 'कार्य' की हमारी अवधारणा को व्यापक बनाना

पहली धुरी वस्तु–उत्पादक मजदूरी श्रम से परे 'कार्य' की व्यापक अवधारणा है, जिसमें कार्य काम के ऐसे प्रकार शामिल हैं जो (मानव और गैर–मानव) जीवन को बनाए रखने के लिए बुनियादी हैं। लंबे समय से नारीवादी विचारकों ने श्रम के इस क्षेत्र को सिद्धांतबद्ध किया है जो वस्तु उत्पादन से बाहर है, फिर भी इसका आधार है, यानी सामाजिक पुनरुत्पादन। सबसे पहले सामाजिक पुनरुत्पादन श्रमिकों के पुनरुत्पादन और उन्हें बनाए रखने का कार्य हैय लेकिन यह जीवन को बनाए रखने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और जीवन और (वस्तु) उत्पादन की सामाजिक और पारिस्थितिक स्थितियों के पुनरुद्धार को भी शामिल करता है। इस प्रकार सामाजिक पुनरुत्पादन में श्रम के न केवल वे रूप शामिल हैं जो सीधे मानवीय उत्पादन क्षमता का उत्पादन और रखरखाव करते हैं, बल्कि वे भी शामिल हैं जो जीवन को आधार देने वाली जैवभौतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं, मध्यस्थता करते हैं और बदलते हैं।

जो बात विशेष रूप से सामाजिक पुनरुत्पादन को विशिष्ट बनाती है, वह है कि यह एक ओर स्पष्ट रूप से लैंगिक (और नस्ल आधारित) है, और दूसरी ओर अत्यधिक अदृश्य और अवमूल्यित है, यानी इसे 'गैर–काम' के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। यह आकस्मिक होने से बहुत दूर है: पूंजीवाद के तहत वस्तु उत्पादन न केवल कार्य और उत्पादन के इस क्षेत्र को छुपाता है, बल्कि बुनियादी तौर पर इसके अवमूल्यन पर निर्भर करता है: मजदूरों का सस्ता उत्पादन, यदि पूरी तरह से मुफ्त नहीं, उनका भरण–पोषण और उत्पादन की व्यापक पारिस्थितिक–सामाजिक स्थितियां पूंजीवाद के विकास और पुनरुत्पादन के लिए सहायक रही हैं। नारीवादी विद्वता ने उपनिवेशीकरण, प्रकृति पर वर्चस्व और महिलाओं की अधीनता के बीच समानताएं खींचते हुए अवमूल्यित और अदृश्य मूल्य प्रवाह के वैश्विक पैमाने की ओर इशारा किया है। इस प्रकार सामाजिक पुनरुत्पादन वैश्विक है और इसमें उपनिवेशों, स्वदेशी लोगों और निर्वाह उत्पादकों का काम शामिल है जो वैश्विक श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन और प्राकृतिक चयापचयी चक्र की सुरक्षाध नया जीवन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक पुनरुत्पादित श्रम का वैश्विक विभाजन भी जुड़ा है, जहां नस्लीय सामाजिक पुनरुत्पादित श्रम (जैसे प्रवासी देखभाल श्रमिक), विशेष रूप से वैश्विक उत्तर के देशों में, पूंजी संचय को बनाए रखने और पुनरुत्पादित करने की लागत को सस्ता करने का काम करता है।

काम की व्यापक अवधारणा को सामने लाने के लिए, सबसे पहले, यह आवश्यक है कि श्रम और उत्पादन के इस अदृश्य क्षेत्र को मान्यता दी जाए, पुरस्कृत किया जाए और समर्थन दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए संभावित कार्यवाहियों में देखभाल आय को लागू करना, साथ ही आवश्यक श्रमिकों के अधिकारों और पात्रताओं का विस्तार और सामाजिक और पारिस्थितिक पुनरुत्पादन में सार्वजनिक निवेश करना शामिल है। ऐसी नीतियाँ न केवल सामाजिक पुनरुत्पादन के श्रमिकों के लिए सामग्री की सहायता प्रदान करेंगी, बल्कि जिसे कार्य के रूप में पहचाना जाता है और मूल्यवान माना जाता है उसके बारे में धारणाओं को बदलने में भी सहायक हो सकती हैं।

फिर भी इस तरह के अग्रभूमिकरण के लिए मान्यता और प्रमाण ीकरण पर्याप्त नहीं हैं। इसके संगठन, को समस्याग्रस्त किये बिना सामाजिक पुनरुत्पादन की केवल मान्यता और प्रमाणीकरण इसके लैंगिक (और नस्लीय) वितरण को बनाये रखने का जोखिम उठाते हैं। एक छोटा सामाजिक चयापचय और सामग्री और ऊर्जा उपयोग में कमी अपने साथ महत्वपूर्ण प्रश्न लाती है, जैसे कि किस तरह की गतिविधियाँ मानव श्रम पर अधिक निर्भर होंगी, और किसका श्रम ऊर्जा उपयोग में कमी का विकल्प होगा, उदाहरण के लिए, घरेलू उत्पादन, कृषि या परिवहन। जैसा कि नारीवादी डीग्रोथ विद्वानों ने इंगित किया है, श्रम विभाजन के गहन रूप से निहित लैंगिक प्रतिमानों को देखते हुए, लैंगिक न्याय सुनिश्चित किए बिना इस तरह के संरचनात्मक बदलाव सामाजिक पुनरुत्पादन के पुनः –नारीकरण का जोखिम उठाते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, नारीवादी सोच और राजनीति न केवल सामाजिक पुनरुत्पादन के कार्य को मान्यता देने और पुरस्कृत करने में सहायक रही है। उन्होंने यह भी समस्याग्रस्त किया है कि यह पुनरुत्पादित कार्य कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यानी, यह कार्य कौन करेगा, कितना करेगा, किन परिस्थितियों में और किसके नियंत्रण में, यदि और कैसे इसका पारिश्रमिक दिया जाएगा और इसके वितरण पर कैसे निर्णय लिया जाएगा। वास्तव में, नारीवादी राजनीति के लिए, सामाजिक पुनरुत्पादन को दृश्यमान बनाना और इसे कार्य के रूप में प्रकट करना अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसके (लिंग आधारित और नस्लीय) वितरण और जिन परिस्थितियों में इसे किया जाता है, उन्हें बदलने के संघर्ष का साधन है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है, क्योंकि यह सामाजिक पुनरुत्पादन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस प्रश्न पर काम की व्यापक अवधारणा को आगे बढ़ाती है। हालाँकि शायद ही इसका कोई नक्शा हो, नारीवादी विद्वत्ता और व्यवहार इस प्रश्न से निपटने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, जो प्रावधान के सहकारी और

>>

''पूंजीवाद के तहत वस्तु उत्पादन न केवल कार्य और उत्पादन के इस क्षेत्र को छुपाता है, बल्कि बुनियादी तौर पर इसके अवमूल्यन पर निर्भर करता है।''

समतावादी रूपों की ओर इशारा करते हैं जहाँ श्रम सामूहिक होता है और लिंग न्याय के साथ संगठित होता है।

संक्षेप में कहें तो, डीग्रोथ द्वारा काम की व्यापक अवधारणा की अग्रप्रस्तुति सामाजिक पुनरुत्पादन के श्रम को दोनों मान्यता देना और पुरस्कृत करना है जो (मानव और गैर–मानव) जीवन को बनाए रखने के लिए बुनियादी है, और इसके सामूहिक, समतावादी और लोकतांत्रिक संगठन के लिए एक दृष्टि है। इस तरह की अग्रप्रस्तुति संक्रमण न्याय के बारे में सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, क्योंकि यह न केवल संक्रमण की धारणा को बल्कि श्रम और उत्पादन के विविध और विशाल क्षेत्र के साथ न्याय को भी प्रभावित करती है जो वस्तु उत्पादन और पूंजी संचय को रेखांकित करते हैं। दूसरे शब्दों में, संक्रमण न्याय के लिए सामाजिक पुनरुत्पादन के (मानव और गैर–मानव) श्रमिकों के लिए न्याय की आवश्यकता होती है।

> न्याय के रूप मेंध्न्याय के माध्यम से डीग्रोथ

दूसरी मूलभूत धुरी न्याय है। डीग्रोथ दो परस्पर संबंधित तरीकों से न्याय की परियोजना है। सबसे पहले, न्याय के लिए सीमाएँ निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि विकास की सामाजिक और पारिस्थितिक लागत हमेशा समाजों और भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर और बीच में असमान रूप से साझा की जाती है। ऊर्जा और संसाधनों के उपयोग में कमी न्याय की परियोजना है। यह विशेष रूप से वैश्विक उत्तर–वैश्विक दक्षिण संबंधों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि उत्तर में आर्थिक विकास दक्षिण पर गंभीर सामाजिक–पारिस्थितिक प्रभावों को प्रेरित कर रहा है और आगे भी कर रहा है। इसलिए विकास में कमी लाना उत्तर की जिम्मेदारी है, ताकि दूसरों के रहने के लिए अधिक जगह हो।

दूसरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास वैश्विक अन्याय द्वारा संचालित और समर्थित है। वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच असमान संबंध, जो ऐतिहासिक रूप से बनते हैं और लगातार पुरुत्पादित होते हैं, वैश्विक पूंजीवाद का आधार हैं। यह उत्तर और दक्षिण के देशों को अलग–अलग तरीके से रखता है, जहां पूर्व की समृद्धि और विकास बुनियादी रूप से दक्षिण से प्राप्त सस्ते प्रकृति और सस्ते श्रम के प्रवाह पर निर्भर रही है। वैश्विक पूंजीवाद की ऐतिहासिक गतिशीलता जिसने वैश्विक उत्तर को समृद्ध बनाया है, उसने वैश्विक दक्षिण के देशों को भी ऐसे रास्तों पर डाल दिया है, जिन्होंने उन्हें निरंतर विकास की अनिवार्यता में बांध दिया है, उदाहरण के लिए, शोषण, ऋण सेवा या संरचनात्मक समायोजन पर संरचनात्मक निर्भरता के माध्यम से।

इस प्रकार ऐतिहासिक और चल रहे अन्याय को सुधारना डीग्रोथ के लिए मौलिक है और इसे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयाम प्रदान करता है। जहाँ डीग्रोथ मुख्य रूप से वैश्विक उत्तर के मुख्य औद्योगिक देशों में और उनके लिए विकसित एक प्रस्ताव है, जिसकी संबंधित नीतियों और कार्रवाइयों को अक्सर इन अर्थव्यवस्थाओं के भीतर हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, 'डीग्रोथ की जिम्मेदारी' के निहितार्थ किसी भी तरह से वैश्विक उत्तर की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। न्याय के रूप में डीग्रोथ अनिवार्य रूप से एक ओर आर्थिक विकास के ऐतिहासिक और समकालीन प्रभावों को संबोधित करने की एक परियोजना है, और दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक प्रणाली की विकास–पुनरुत्पादक संरचनाओं को संबोधित करने की एक परियोजना है।

डीग्रोथ और न्याय के मध्य संबंध का ऐसा पुनर्निर्धारण वास्तव में हालिया डीग्रोथ सोच और सक्रियता में केंद्रीय है, जो विशेष रूप से पारिस्थितिक ऋण की धारणाओं के इर्द–गिर्द सघन हुआ है, अर्थात, पारिस्थितिक संसाधनों और सिंक का ऐतिहासिक और समकालीन विनियोग और/या असंगत उपयोग, और पारिस्थितिक रूप से असमान विनिमय, अर्थात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार किए गए सामानों के माध्यम से सन्निहित प्रकृति का असमान प्रवाह। फिर भी इसे सामाजिक पुरुत्पादन पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ पूरक करने की आवश्यकता है, जो न्याय की इस धारणा को वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच मनुष्यों और प्रकृति के जीवन–निर्वाह श्रम के असमान प्रवाह को शामिल करने के लिए विस्तारित करता है। इस तरह से देखा जाए तो यह केवल (निहित) प्रकृति का प्रवाह नहीं है, चाहे वह प्रत्यक्ष उपयोग और विनियोग के माध्यम से हो या वैश्विक व्यापार में असमान विनिमय के माध्यम से, बल्कि अधिक व्यापक रूप से सामाजिक पुरुत्पादन श्रम का प्रवाह है जो पूंजीवादी विकास को बनाए रखता है और उसका पुनरुत्पादन करता है। इसलिए वैश्विक अन्याय को सुधारने की दिशा में की जाने वाली कार्रवाइयों में 'सामाजिक पुरुत्पादन ऋण' की व्यापक अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें वैश्विक दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला नस्लीय और सस्ता सामाजिक पुरुत्पादन श्रम, साथ ही औपनिवेशिक क्षतिपूर्ति और भूमि को उनके वास्तविक स्वदेशी संरक्षकों को वापस देना शामिल है।

न्याय के रूप मेंध्के माध्यम से डीग्रोथ की इस समझ से जो ठोस कार्य और हस्तक्षेप सामने आते हैं उन्हें मोटे तौर पर तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि द फ्यूचर इज डीग्रोथः ए गाइड टू ए वर्ल्ड बियॉन्ड कैपिटलिज्म पुस्तक के ऋण पर अध्याय में किए गए प्रस्तावों के व्यापक रूप से अनुरूप हैं। पहला ऐतिहासिक और समकालीन अन्याय को ठीक करने से संबंधित है और इसमें पारिस्थितिक और अधिक व्यापक रूप से सामाजिक पुरुत्पादन ऋण, जलवायु और औपनिवेशिक सुधार, और वैश्विक वित्तीय और व्यापार प्रणाली में हस्तक्षेप जैसे उपाय शामिल हैं जो वैश्विक उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच असमान विनिमय की गतिशीलता को उलटध्कम करते हैं। इस अर्थ में डीग्रोथ न सिर्फ उन समकालीन आंदलनों जैसे लैंड बैक मूवमेंट में सम्मिलित होता है जो सुधार और स्वदेशी सम्प्रभुता का आह्वान करते हैं बल्कि उनमें भी जो सदर्न पीपुल्स इकोलॉजिकल डेब्ट क्रेडिटर्स अलायन्स, जिसने तीसरी दुनिया के तथाकथित ऋण संकट को वैश्विक उत्तर द्वारा बकाया ऋण के रूप में पुनः प्रस्तुत किया था, की परिवर्तनकारी क्षमता को पुनर्जीवित करते हैं।

दूसरे चरण की कार्यवाहियाँध्हस्तक्षेप संभावित रूप से दुर्बल करने वाले प्रभावों से संबंधित हैं, जो डीग्रोथ के अनुरूप औद्योगिक देशों में उत्पादन और उपभोग गतिविधियों के संकुचन से वैश्विक दक्षिण पर

> >

पड़ सकते हैं, खासकर उन देशों पर जो संरचनात्मक रूप से निर्यात या विदेशी निवेश पर निर्भर हैं। जैसे वैश्विक उत्तर और दक्षिण के मध्य विषम संबंध और श्रम के असमान प्रवाह और प्रकृति ने भी ऐतिहासिक रूप से दक्षिण में कई अर्थव्यवस्थाओं को संरचनात्मक रूप से निर्यात क्षेत्रों पर निर्भर रहने के लिए आकारित किया है, उत्तर में संकुचन के मामले में दक्षिण को नुकसान होगा, जो एक बाध्यकारी अलगाव के बराबर है। यद्यपि ऊपर वर्णित न्याय–उन्मुख उपाय कुछ राहत प्रदान करेंगे, लेकिन आर्थिक पुनर्गठन के लिए संसाधनों के हस्तांतरण जैसे प्रत्यक्ष उपायों की भी आवश्यकता है।

और प्रस्तावों का तीसरा और अंतिम समूह वैश्विक दक्षिण, अगर वह ऐसा करना चाहता है, के लिए गैर–विकास मार्गों को अपनाने के लिए जगह खोलने और मजबूत करने के बारे में है । एक ओर इसका तात्पर्य वैश्विक दक्षिण से उत्पन्न विकास से परे विभिन्न आंदोलनों, प्रस्तावों और विश्वदृष्टि की वैधता को पहचानना है (जैसे पोस्ट–एक्स्ट्रेक्टिविज्म, उबंटू, ब्यून विविर) और दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण में विकास की अंतर्निहित अनिवार्यता को कम करने के उपाय, उदाहरण के लिए, विकास से अलग प्रावधान की सहकारीध सार्वजनिक प्रणालियों को वित्तपोषित करना या असमान विनिमय संबंधों पर निर्भरता से दूर जाने का समर्थन करना।

> स्वायत्तता/लोकतंत्र के रूप में डीग्रोथ

तीसरी और अंतिम धुरी स्वायत्तता और लोकतंत्र है। यह विकास की अनिवार्यता से प्रभावित सामाजिक कल्पना से बाहर निकलने और आर्थिक प्रक्रियाओं को आकार देने में लोकतांत्रिक निर्णय लेने को आगे बढ़ाने के लिए डीग्रोथ के आह्वान से संबंधित है। इस आह्वान का एक प्रतिरूप स्वायत्तता पर डीग्रोथ का जोर रहा है। डीग्रोथ स्वायत्तता (और, संबंधित, लोकतंत्र) की अवधारणाओं से काफी प्रेरित है, जिसे इवान इलिच, आंद्रे गोरज और कॉर्नेलियस कैस्टोरियाडिस जैसे विचारकों ने विकसित किया है। अपने मतभेदों के बावजूद, इन विचारकों द्वारा साझा किया गया सामान्य आधार यह समझ है कि आर्थिक गतिविधि का बढ़ता हुआ पैमाना कैसे स्व–शासन की क्षमता को कमजोर करता है, चाहे वह आर्थिक निर्णय लेने के केंद्रीकरण और नौकरशाही के माध्यम से हो या बाजार अर्थव्यवस्था के उदय के साथ जरूरतों को स्वयं परिभाषित करने की क्षमता के क्षरण के माध्यम से हो। अंतहीन आर्थिक विकास वांछनीय नहीं है, भले ही यह जैवभौतिक रूप से संभव हो, क्योंकि यह सामूहिक रूप से स्व–शासन की क्षमता को विस्थापित करता है।

स्वशासन के विस्तार की दिशा में आर्थिक निर्णय–निर्माण का लोकतंत्रीकरण, अर्थात, सभी को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम बनाना, डीग्रोथ में निहित है। यह सबसे पहले, डीग्रोथ के सामूहिक और लोकतांत्रिक निर्धारण पर जोर देने से प्रेरित है, अर्थात, कौन सी गतिविधियों को समाप्त करना है, कौन सी सीमित करनी है, और डीग्रोथ भविष्य में किन गतिविधियों का समर्थन और विस्तार करना है। लेकिन यह डीग्रोथ के 'अलग, न केवल कम' पर जोर देने के साथ भी प्रतिध्वनित होता है, अर्थात, एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था के निर्माण का आह्वान जो शोषण, संचय और विकास पर आधारित अर्थव्यवस्था से अलग कार्य करती है, जो जरूरतों, प्रावधान, समानता और एकजुटता पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट शक्ति पर अंकुश लगाना, धन और वित्त पर लोकतांत्रिक निगरानी स्थापित करना, भागीदारीपूर्ण सार्वजनिक बजट, उत्पादक क्षमताओं का लोकतांत्रिक शासन और साथ ही उत्पादन, वितरण/वनिमय और उपभोग के वैकल्पिक (गैर–पूंजीवादी) रूपों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण इस प्रकार डीग्रोथ के मूलभूत पहलू हैं।

इस तरह के हस्तक्षेपों और प्रथाओं के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेने के लोकतंत्रीकरण में ठोस जरूरतों को सामने लाने, संचय, लाभ अधिकतमकरण और विकास पर मूल्यों और गैर–मौद्रिक धन का उपयोग करने और टिकाऊ और न्यायसंगत आजीविका या पर्यावरणीय गुणवत्ता का पुनर्जनन, नवीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करने जैसे सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की क्षमता है। कर्त्ताओं के एक बड़े आधार की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को खोलने से निर्णयों को सूचित करने के लिए मांग और मूल्यों की एक व्यापक श्रंखला के सम्मिलित करने की क्षमता बढ़ेगी जैसे कि क्या, कितना और किसके लिए और किन परिस्थितियों में उत्पादन,कीमतों का या मजदूरी का निर्धारण कैसे हो एवं अधिशेष का निवेश कहाँ हो। यह आर्थिक अनिवार्यताओं जैसे कि विकास या दक्षता पर पुनर्विचार करने, वैकल्पिक लक्ष्यों के संचालन को सक्षम करने और आर्थिक तर्कसंगतता को सामाजिक विचार–विमर्श और नियंत्रण के अधीन करके अर्थव्यवस्था का (पुनः) राजनीतिकरण करने के लिए जगह बनाएगा।

आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र और स्वायत्तता न केवल अपने आप में अनुसरण करने योग्य सिद्धांत हैं, बल्कि वे पूंजीवादी विकास अर्थव्यवस्थाओं की सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी गतिशीलता को रोकने और बदलने के लिए एक शक्ति के रूप में भी कार्य करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र और स्वायत्तता पर डीग्रोथ का जोर विशेष रूप से पारिस्थितिकी–सामाजिक संक्रमण पर मुख्यधारा की बहस की पृष्ठभूमि के सामने महत्वपूर्ण है। उस मोर्चे के भीतर के प्रस्ताव ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के संरचनात्मक पुनर्संरचना पर केंद्रित हैं, जैसे कि अक्सर पारिस्थितिकी–कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ, जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों से दूर जाना। वे रूपांतरण के प्रश्न को निवेश की 'सही' दिशा से बदल देते हैं, अर्थात, पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी गतिविधियों से दूर होना और उत्पादन क्षमताओं के गलत आवंटन को दुरुस्त करना।

यद्यपि इन बहसों में से, आर्थिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार शासित करना चाहिए और किस प्रकार की आर्थिक संस्थाओं की आवश्यकता है के बारे में सोच गायब है। यहीं पर स्वायत्तता/लोकतंत्र पर डीग्रोथ का जोर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह संक्रमण पर बहस को उनके परिणामों के अलावा आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की समस्या से लैस करता है।■

सभी पत्राचार बेंगी अकबुलुत को <bengi.akbulut@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> एक न्यायोचित एवं लोकप्रिय ऊर्जा परिवर्तन को कैसे निर्मित किया जाए?

तातियाना रोआ एवेन्डानो, पर्यावरण नियोजन उप–मंत्री, कोलंबिया, और **पाब्लो बर्टिनाट**, टैलर इकोलॉजिस्टा, अर्जेंटीना द्वारा

श्रेय : एंजी वैनेसिटा (angievanessita.wordpress.com).

सामाजिक–पर्यावरणीय न्याय के दृष्टिकोण से और लोकप्रिय पर्यावरणवाद के जगत के भीतर, हम एक न्यायपूर्ण और लोकप्रिय ऊर्जा परिवर्तन का बचाव करते हैं जो पूंजीवाद–विरोधी और सामाजिक–पारिस्थितिक आख्यान पर आधारित है। हालाँकि, इसे प्राप्त करने के लिए, हमें पहले वर्तमान स्थिति का निदान करना होगा और वांछित भविष्य की ओर मार्ग स्थापित करना होगा। इस संबंध में, ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की जटिलता को समझना महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, बल्कि क्षेत्रों में सामाजिक असमानताओं और सामाजिक–पर्यावरणीय प्रभावों के साथ–साथ ऊर्जा से जुड़े संघर्षों और ऊर्जा शक्ति के कुछ व्यक्तियों में और बड़ी कंपनियों के साथ संकेंद्रण पर विचार करना है।

ऊर्जा प्रणाली को हम सामाजिक संबंधों के एक समूह के रूप में समझते हैं जो हमें एक समाज के रूप में और हमारे समाज में बांधते हैं– प्रकृति के संबंध, जो उत्पादन संबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं। न्यायोचित और लोकप्रिय ऊर्जा संक्रमण के लिए वि–वस्तुकरण, लोकतंत्रीकरण, वि–जीवाश्मीकरण, वि–संकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण और वि– पितृसत्तात्मकीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं?

>>

> वि–वस्तुकरण और लोकतंत्रीकरण का मार्ग

न्यायोचित और लोकप्रिय ऊर्जा परिवर्तन इस आधार वाक्य पर आधारित है कि सभी लोगों को ऊर्जा का अधिकार है, और यह इस विचार को चुनौती देता है कि ऊर्जा एक वस्तु है। यह सार्वजनिक, सहभागी और लोकतांत्रिक के विभिन्न रूपों को निजीकरण से मुक्त करने और उन्हें मजबूत करने के बारे में है। नारों में से एक नारा है वि–वस्तुकरण (डीकमोडिफाई) करना, जिसका अर्थ है ऊर्जा को आर्थिक लाभ के व्यावसायिक तर्क की प्रधानता से मुक्त करना और इसके बजाय सभी आयामों, भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों में जीवन को नियंत्रित करने और पुनः पेश करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना।

हम ऊर्जा को साझा संपत्ति का हिस्सा मानते हैं और इसलिए इसे प्रकृति के अधिकारों के अनुरूप सामूहिक अधिकार मानते हैं। पानी के अधिकार के लिए संघर्ष को उदाहरण के तौर पर लेते हुए ऊर्जा को अधिकार के रूप में देखना जरूरी है। यह अधिकार केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए है। हम इस परिभाषा में प्रकृति और उसकी सभी प्रजातियों को शामिल करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मानव जीवन के पूर्ण आनंद और पर्यावरण के बीच एक दूसरे पर निर्भरता है।

वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे के भीतर, बाजार ऐसे साधन हैं जो उन क्षेत्रों की सेवा करते हैं जिनका मूलाधार जीवन की भौतिक सीमाओं से परे असीमित पूंजी संचय पर आधारित है। वि–वस्तुकरण की अवधारणा कुछ जरूरतों को हल करने के लिए पूंजीवादी बाजारों की केंद्रीयता को चुनौती देती है। इस मार्ग के लिए जनता की बहाली आवश्यक है। इसका तात्पर्य निजी हाथों से इसे पुनः प्राप्त करके न केवल स्वामित्व के बारे में बहस करना है, बल्कि प्रबंधन के बारे में भी। हमारे दृष्टिकोण से, जनता की बहाली राज्य (राष्ट्रीय) के साथ इसके जुड़ाव तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह समुदाय, सामूहिक, नगरपालिका, सहयोगी और सहकारी क्षेत्रों से संबंधित ऐतिहासिक अनुभवों सहित स्वामित्व और प्रबंधन के संदर्भ में जनता के सभी रूपों को मजबूत करने और पुनः सृजित करने के बारे में प्रश्न है। ये मूल्यवान उपकरण हैं जिन्हें सेवाओं के प्रावधान में निजी कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली कथित बेहतर दक्षता के सामने मजबूत किया जाना चाहिए।

अन्य कार्यों के मध्य, ऊर्जा के अधिकार का वि–वस्तुकरण और सामाजिक रूप से निर्मित करने का तात्पर्य, एक व्यापक विधायी, विनियामक और मानक सुधार से है जो निजीकरण कानूनों और बाजारों के उदारीकरण को निरस्त करता है जिन्होंने निजी क्षेत्र को ऊर्जा प्रणाली के केंद्र में रखा है। यह गैर–निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कुंजी भी है जिसमें ऊर्जा कंपनियां ही नहीं बल्कि अन्य बुनियादी सेवाएं के साथ विकास के वे उपकरण भी सम्मिलित हैं जो सभी क्षेत्रों को मजबूत करते हैं (सहकारी, सामुदायिक, राज्य और राष्ट्रीय)। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों के आवश्यक संस्थागत ढांचे पर जोर देते हुए स्वामित्व और प्रबंधन के सन्दर्भ में सार्वजनिक के स्वरूपों को मजबूत करना आवश्यक है।

क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की दिशा में पहले कदम के रूप में उन सूचना तंत्रों को स्थापित करना आवश्यक है जो किसी भी समुदाय, चाहे ग्रामीण या शहरी, को निर्णय–लेने में संलग्न होने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म आधारित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी नीतियों की समीक्षा करना, उन्हें सही करना और यहां तक कि कुछ अवसरों पर उन्हें उलटना भी महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी बाजार के बाहर ऊर्जा के उत्पादन, वितरण, प्रबंधन और खपत में शामिल संस्थानों और कर्त्ताओं को मान्यता देना और उनका समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर ऊर्जा के विभिन्न आयामों (उत्पादन, खपत, ऊर्जा गरीबी, आदि) पर निर्णय लेने की संभावना को मानना महत्वपूर्ण है। नगरपालिका ऊर्जा एजेंसियां और सार्वजनिक सेवाओं को पुनः प्राप्त करने के अनुभव ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मजबूत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को और अधिक गतिशील बनाने के लिए, पद्धतिगत रूप से आगे बढ़ना भी आवश्यक है: इन नीतियों के सामूहिक विनियोजन के स्वरुप में स्थानीय, सामुदायिक और नगरपालकीय ऊर्जा के निर्माण हेतु उपकरण और प्रक्रियाओं को विकसित करना।

> यह सिर्फ कार्बन मुक्त करने के बारे में नहीं है

कार्बन सिंक, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अवशोषित करने वाले तंत्र हैं, और सामग्री और खनिजों की सीमित उपलब्धता, वर्तमान उत्पादन और खपत मैट्रिक्स के ढांचे के भीतर, जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की क्षमता पर एक सीमा निर्धारित करती है। इसका मतलब यह है कि मुख्य लक्ष्य के रूप में ऊर्जा के शुद्ध उपयोग में कटौती करना आवश्यक है, यद्यपि विद्यमान असमानताओं तथा विभिन्न देशों और सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस कटौती की योजना और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

यह भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में केवल प्रगति करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि, प्रत्येक विशिष्ट उद्यम की वहनीयता निर्धारित करने के लिए उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर विचार करना आवश्यक है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

- जोखिम–प्रवण क्षेत्रों, जैसे अपतटीय क्षेत्रों में अपरंपरागत और पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का दोहन न करने, या अल्पावधि में जीवाश्म ईंधन को त्यागने की योजना के ढांचे के भीतर उनके उपयोग को कम करने पर सहमत होना;
- जलवायु प्रतिबद्धताओं से परे ऊर्जा उपयोग में शुद्ध कमी की निगरानी करना;
- परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव हों, जो लैटिन अमेरिका में मुख्य ऊर्जा उपभोक्ता है और इसे अपने आप में एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए;
- ऐसे उपकरण विकसित करना जो ऊर्जा दक्षता के सामाजिक–आर्थिक लाभों की कल्पना करें और ऐसे नियामक परिवर्तन स्थापित करें जो वाणिज्यिक तर्क के विरुद्ध हों;
- बड़े वाणिज्यिक/अंतर्राष्ट्रीय प्रदाताओं के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया को एकमात्र विकल्प के रूप में अपनाना बंद करें तथा इसके बजाय इन स्रोतों के विकेन्द्रित और विघटित विकास को प्राथमिकता दें।

> उत्पादन मॉडल और उपभोग पर

न्यायोचित और लोकप्रिय ऊर्जा परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए,

> >

एक ऐसा उत्पादन मॉडल बनाना आवश्यक है जो जीवन की स्थिरता और इसे संभव बनाने वाले पारिस्थितिक तंत्र और चक्रों की देखभाल के अनुकूल हो। जैसा कि नारीवादी प्रस्तावित करते हैं, इस मॉडल के केंद्र में जीवन को रखना आवश्यक है।

हम जिस ऊर्जा संक्रमण का प्रस्ताव करते हैं, उसके लिए प्राकृतिक और मानवीय भौतिक सीमाओं को पहचानना, साथ ही जीवन के अस्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं के रूप में संबंधों और संबंधों की महत्ता और महत्व को पहचानना भी आवश्यक है। ये अवधारणाएँ समाज में जीवन को व्यवस्थित करने के नए तरीकों, उत्पादन के नए रूपों, समाज में उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्यों द्वारा लिए गए स्थान के पुनर्मूल्यांकन और उपभोग के नए रूपों से जुड़ी हैं, जो समाज–प्रकृति चयापचय में बदलाव से जुड़ी हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता से जुड़ी पहलों के बावजूद, क्षेत्रीय उत्पादन और परिवहन मैट्रिक्स पर सवाल उठाने और टिकाऊ और निष्पक्ष विकल्पों की तलाश करने के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण में आगे बढ़ना आवश्यक है। इस क्षेत्र में ठोस प्रस्तावों में निम्न शामिल हैं:

- वस्तुओं के संचलन के लिए अधिकतम सर्किट स्थापित करना तथा स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने वाली लघु उत्पादन श्रृंखलाएं विकसित करना;
- भौतिक उत्पादन के उन क्षेत्रों का विश्लेषण करना जिनमें विकास कम करने की आवश्यकता है और यह निर्धारित करना कि किसका उत्पादन बंद किया जाएय भौतिक वस्तुओं की तुलना में सेवाओं को कैसे बढ़ाया जाए का विश्लेषण करना। इसके साथ ही इस डीग्रोथ के लिए समयसीमा निर्धारित करना भी आवश्यक है;
- उत्पादन के नए क्षेत्रों और कम ऊर्जा–गहन सेवाओं का विकास करना;
- व्यक्तिगत आंतरिक दहन वाहनों का उपयोग बंद करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना;
- माल परिवहन में मॉडल परिवर्तन की प्रक्रिया को लागू करना;

बुनियादी ढांचे की भूमिका और डिजाइन पर पुनर्विचार करना, क्योंकि इसका वित्तपोषण सार्वजनिक धन से होता है और यह भविष्य के व्यवहार और उपभोग को निर्धारित करता है।

इसी प्रकार, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो हमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के अन्य रूपों के सामाजिक निर्माण में आगे बढ़ने की अनुमति दे। यह एक गहन और व्यापक प्रक्रिया है, लेकिन इसे विभिन्न उपकरणों के उपयोग के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, टिकाऊ उपभोग के लिए शहरी नेटवर्क को मजबूत करनाय नियोजित अप्रचलन को प्रतिबंधित करने वाले नियम विकसित करनाय उत्पादों का सामूहिक जीवन चक्र का विश्लेषण करना; उत्पादों की विशेष शाखाओं पर विज्ञापन को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करनाय ऊर्जा गरीबी को खत्म करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम स्थापित करनाय आवास नीतियों के साथ ऊर्जा नीतियों को जोड़ना; और ऊर्जा के विलासितापूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित करना। ■

सभी पत्राचार टाटियाना रोआ को <troaa@censat.org> पर और
पाब्लो बर्टिनाट को <pablobertinat@gmail.com>
ट्विटर: @tatianaroaa और @PactoSur पर प्रेषित करें।

> (अखिल) अफ्रीकी पर्यावरण–नारीवादी आंदोलन

जो रैंड्रियामारो, विकास विकल्पों के लिए अनुसंधान और सहायता केंद्र– हिंद महासागर, मेडागास्कर द्वारा

फ्रिपिक : अर्बु द्वारा लिया गया

अफ्रीकी पारिस्थितिकी–नारीवादी आंदोलन तीन अलग–अलग आंदोलनों के संगम पर स्थित है जो उन्हीं साम्राज्यवादी विचारधाराओं और संस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने स्वदेशी संस्कृतियों और संस्थाओं को बाधित और कमजोर किया है: नवउदारवाद विरोधी आंदोलन, जिसका मुख्य रूप से जलवायु न्याय कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थन किया जाता है, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जिसे उपनिवेशवाद–विरोधी लोगों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और पितृसत्तात्मक–विरोधी आंदोलन जिसका नेतृत्व नारीवादियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, अफ्रीकी–पारिस्थितिकी–नारीवादी उन सत्ता संरचनाओं और पदानुक्रमों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं जो महिलाओं और प्रकृति दोनों का दमन और शोषण करते हैं।

> जलवायु न्याय के लिए एक अखिल– अफ्रीकी नारीवादी आंदोलन

बड़े पैमाने की कृषि–औद्योगिक और निष्कर्षण परियोजनाओं और कॉर्पोरेट और राज्य शक्तियों के साथ उनके संबंधों के परिणामस्वरूप अफ्रीकी महाद्वीप में सामुदायिक स्तर पर, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। पारिस्थितिकी–नारीवाद जमीनी स्तर पर ठोस संघर्षों और पहलों से अविभाज्य है, जो भौतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रहने योग्य स्थानों और सामाजिक बंधनों को संरक्षित, विकसित या मरम्मत करने के लिए है, जो समाज को अन्य समाजों या जीवित प्रजातियों को नष्ट किए बिना खुद को पुनः उत्पन्न करने की अनुमति देता है।

इस दृष्टिकोण से, प्रभावित लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता के आधार पर कि प्रमुख नवउदारवादी विकास मॉडल अस्थिर है जलवायु न्याय आंदोलनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जो नारीवादी दृष्टिकोण से पारिस्थितिक संकट और उसके मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह के पारिस्थितिकी–नारीवादी आंदोलन अफ्रीका में जलवायु और पारिस्थितिक संकटों पर, उनके शोषणकारी विकास और उनके लैंगिक प्रभावों पर केंद्रित हैं, और मांग करते हैं कि 'पृथ्वी की देखभाल करने और लोगों और प्रकृति के अधिकारों के ऐतिहासिक उल्लंघनों के लिए निवारण प्रदान करने

> >

के लिए अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए', जैसा कि मार्गरेट मापोंडेरा, त्रुशा रेड्डी और सामंथा हग्रीव्ज सुझाव देते हैं।

अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के कारण, जलवायु न्याय आंदोलन और अफ्रीका के लिए उपनिवेशवाद–विरोधी परियोजना दोनों को टुकड़ों में सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इनके लिए एक अखिल–अफ्रीकी कार्रवाई की आवश्यकता है। महाद्वीप के विखंडन और वैचारिक विभाजन ने अफ्रीका में उपनिवेशवाद के विभिन्न रूपों को कायम रखने में बहुत योगदान दिया है, जिसका अर्थ है कि अखिल अफ्रीकीवाद अफ्रीकी–पारिस्थितिकी–नारीवादियों द्वारा अपनाई गई उपनिवेशवाद–विरोधी परियोजना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

> अफ्रीकी पारिस्थितिकी–नारीवाद और उपनिवेशवाद–विरोध

वंगारी मथाई ने पुष्टि की कि ''औद्योगीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण प्रकृति के क्षरण की शुरुआत उपनिवेशवाद से हुई थी [...] जंगलों की कटाई, आयातित पेड़ों के रोपण जिसने पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया, वन्यजीवों का शिकार और वाणिज्यिक कृषि वे औपनिवेशिक गतिविधियाँ थीं जिन्होंने अफ्रीका में पर्यावरण को नष्ट कर दिया''। इस प्रकार, प्रारम्भ से ही, अफ्रीका में व्यवस्थागत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी–पारिस्थितिकी नारीवाद गैर–औपनिवेशिक नारीवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है।

इस संबंध में, पितृसत्तात्मक सत्ता और नवउपनिवेशवाद को चुनौती देने के लिए अफ्रीकी–पारिस्थितिकी–नारीवादी भी अपनी समृद्ध पारंपरिक विरासत और स्वदेशी संस्कृति पर भरोसा करते रहे हैं। जबकि फेनोस मंगेना जैसे कुछ अफ्रीकी नारीवादियों ने तर्क दिया है कि अफ्रीकी सांस्कृतिक परंपरा और सामुदायिक दर्शन नारीवाद के साथ संगत नहीं हैं क्योंकि वे गहन रूप से पितृसत्तात्मक हैं, सिल्विया तामाले और मुनामातो चेमहुरू जैसे अन्य पारिस्थितिकी–नारीवादी पुष्टि करते हैं कि अफ्रीकी पारंपरिक दर्शन और उबुंटू जैसे उपकरणों का उपयोग लैंगिक न्याय के साथ–साथ अफ्रीकी–नारीवाद के अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

जैसा कि युगांडा की शिक्षाविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता सिल्विया तामाले तर्क देती हैं, ''पारिस्थितिकी नारीवाद की अंतर्निहित विशेषताएँ बहुत हद तक गैर–पश्चिमी स्वदेशी संस्कृतियों में पारंपरिक रूप से प्रचलित विशेषताओं से मिलती–जुलती हैं''। विशेष रूप से, पारिस्थितिकी–नारीवादी प्रथाओं में ''स्वदेशी लोगों और प्रकृति के बीच ज्ञानात्मक संबंध से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ख्जो, उनकी आध्यात्मिकता, कबीले के टोटम, निषेधों, पैतृक मिथकों, अनुष्ठानों, दंतकथाओं और इसी तरह की अन्य बातों के माध्यम से प्रकट होता है ख्.., उल्लेखनीय रूप से, निषेध का उल्लंघन करने के परिणाम व्यक्तिगत नहीं थे और उनका अनुपालन करने की जिम्मेदारी सामुदायिक थी। यदि आप सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करते हैं, तो आपके रिश्तेदारों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे'' (पृष्ठ 87–89)।

इस ज्ञानात्मक संबंध का एक विशिष्ट उदाहरण नीचे दिया गया कथन है, जो उन महिलाओं द्वारा व्यक्त किया गया है जो मेडागास्कर के उत्तर–पश्चिमी भाग में साकाटिया द्वीप के स्वदेशी समूह के स्थानीय पवित्र स्थलों और जैव–सांस्कृतिक विरासत (*मपिजोरो टैनी*) की संरक्षक हैं:

> *''मपिजोरो टैनी' के रूप में हमारी भूमिका हमारे गांव के प्रति हमारा कर्तव्य है, जिसकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने की है। अंकाटाफेबे नामक एक पवित्र स्थान है, और एम्पिजोरोआ और अंकोफियामेना में भी एक और है। पूर्व में, कोई चर्च नहीं था, लेकिन ये वे स्थान थे जहाँ हम भगवान से प्रार्थना करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम चर्च में करते हैं। ये वार्षिक 'फिजोरोआना' (अनुष्ठान प्रार्थना समारोह) के स्थान हैं जहाँ प्रार्थना की जाती है और आशीर्वाद मांगा जाता है [...] हमारे पूर्वजों ने 'फैडिन–तानी' (भूमि निषेध) का सख्ती से पालन किया, और सकातिया में अधिकांश लोग अभी भी उनका पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 'फैडी' (निषेध) तोड़ता है, तो उसे अपने द्वारा किए गए गलत काम के प्रायश्चित के रूप में एक जेबू को मारना होगा।" (जस्टिन हंबा, अनुष्ठान प्रार्थना नेता, 2021)।*

सकातिया द्वीप पर पवित्र स्थलों के अन्य संरक्षक ने पारंपरिक अनुष्ठानों और रीति–रिवाजों के पीछे के तर्क को इस प्रकार समझाया, तथा सामान्य भलाई के लिए उनका पालन करने और समुदाय में एकता, सहयोग, प्रेम और विश्वास सुनिश्चित करने के साथ–साथ जीवित और मृत लोगों के बीच सम्मान स्थापित करने के लिए उनका महत्वपूर्ण महत्व बताया:

> *''कोडरी' (मछली) को खाने वाले लोगों के लिए उसे संरक्षित करने का एक तरीका है। आप केवल उतनी ही मात्रा लेते हैं जितनी आपको आवश्यकता है; किसी भी अधिशेष को समुदाय में वितरित किया जाना चाहिए; इसे फेंका या बेचा नहीं जा सकता। यह समुदाय और प्रेम की भावना है। जो लोग भोजन चुनते हैं, जरूरी नहीं कि वे इसे खाने वाले भी हों; इसे समुदाय के साथ साझा किया जाना चाहिए। इसे बेचा नहीं जा सकता और इसे बड़ी मात्रा में काटा नहीं जा सकता; अन्यथा यह विलुप्त हो जाएगी और ऐसा करने से लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं [...] गांव के छोटे जानवरों को बिना किसी कारण के मारा नहीं जा सकता है, उदाहरण के लिए, 'अंजवा' एक छोटा जानवर, जो छायादार और ठंडी जगहों पर रहता है। जिन हरे जंगलों में वह छिपता है उन्हें नहीं काटा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को मारता है, तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। अभिशाप तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि वह सजा (मनला फडी) को नहीं काट लेता और गांव के पारम्परिक प्रार्थना नेताओं से क्षमा नहीं मांग लेता [...] वह व्यक्ति जो निषेधों को तोड़ता है बेअदबी करता है; ये इस भूमि के खजाने हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने संजोया है और इन जानवरों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें गांव में ही रहना चाहिए [...] जंगल, जो हमें जीने के लिए बारिश और ताजी हवा प्रदान करते हैं, को नष्ट करना मना है। इसलिए सकातिया एक हरा–भरा द्वीप है, क्योंकि हम पहाड़ियों पर जंगलों को नहीं काटते हैं, और हम पेड़ भी लगाते हैं। और हम मछलियों सहित समुद्री जीवन की भी रक्षा करते हैं, हम मछुआरों को गैर–मानक जाल का उपयोग करने से रोकते हैं। हम समुद्री कछुओं और 'होरोको' और 'कोड्री' जैसी स्थानिक मछली प्रजातियों की रक्षा करते हैं [...] हमारे गांव में एक दीना (प्रतिबंधों की प्रणाली के साथ पारंपरिक सामाजिक सम्मेलन) है: उदाहरण के लिए, यदि आप गाली देते हैं या अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो 'दीना' में एक तदनुरूप दंड है। आपको अनुष्ठान प्रार्थना नेताओं के पास जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा गांव में हर कोई शाप के अधीन होगा।" (सेलेस्टीन, अनुष्ठान प्रार्थना नेता, 2021)*

जैसा कि उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है, सकातिया में मालागासी समुदाय भी उप–सहारा अफ्रीका के अनेक स्वदेशी समूहों की तरह ही 'प्रकृति–संबंधी नैतिकता' का पालन कर रहे हैं। ये स्वदेशी

>>

समूह प्रकृति पर मानव–केंद्रित हस्तक्षेपों के प्रति सजग हैं, जो स्वस्थ जीवन–तन्त्र को इस तरह से कमजोर करते हैं कि पृथ्वी के अस्तित्व को ही जोखिम में डालते हैं। जैसा कि सिल्विया तामले ने अपनी पुस्तक *डीकोलोनाइजेशन एंड एफ्रो–फेमिनिज्म* में सही ढंग से रेखांकित किया है, ''वैश्विक दक्षिण में महिलाओं ने स्वयं को 'पारिस्थितिक नारीवादी' के रूप में नहीं पहचाना है, लेकिन उनके पास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति पारिस्थितिक चेतना और नैतिक दायित्व का एक लंबा इतिहास है''।

> विकास के लिए अफ्रीकी पर्यावरण–नारीवादी विकल्प

उपनिवेशवाद–विरोधी, पर्यावरण–नारीवादी दृष्टिकोण से, सूक्ष्म और मध्यम स्तर पर पहले से ही कई समृद्ध विकल्प मौजूद हैं। इनमें से कई विकल्प अफ्रीका से लिए गए हैं, जैसे कि एकजुटता अर्थव्यवस्था और श्रम और संसाधनों जैसे बीज और धन के लिए सामूहिक समाधान और इन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और इन पर काम किया जाना चाहिए। जैसा कि लैटिन अमेरिका में अन्य प्रस्तावों, जिनमें स्वदेशी लोगों के कुछ पक्षों और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोणों को अपनाया गया, जिसमें प्रकृति के अधिकार और 'ब्यून विविर' (एक स्पेनिश वाक्यांश जो सामाजिक और पारिस्थितिक विस्तारित दृष्टि पर आधारित अच्छे जीवन को संदर्भित करता है) का विश्वदृष्टिकोण शामिल है, के साथ हुआ, निश्चित रूप से अंतर्जात विचारों, प्रथाओं और राजनीतिक अवधारणाओं का एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी संग्रह है जो परंपरा में निहित है, साथ ही उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्षों और उपनिवेशवाद–उत्तर परिवर्तनों में भी है, जिनसे हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन लेना चाहिए। इनमें स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ, सामुदायिक नियम/स्वदेशी भूमि अधिकार और सामाजिक श्रम सहयोग शामिल हैं।

इनमें से प्रमुख अफ्रीकी विश्वदृष्टि और दर्शन पर आधारित महत्वपूर्ण विकल्प हैं जिन्हें दक्षिणी अफ्रीका में उबुंटू के नाम से जाना जाता है, जिसका बड़े पैमाने पर उप–सहारा अफ्रीका में अभ्यास किया जाता है और यह ''अस्तित्व के पारंपरिक पितृसत्तात्मक, द्वैतवादी और मानव–केंद्रित विचारों को कम करने का यथासंभव प्रयास करता है''। उबुंटू के कारण, अफ्रीकियों ने सदियों से उन मूल्यों का जश्न मनाया है जो अतीत और वर्तमान के साथ–साथ मनुष्यों और प्रकृति को जोड़ती हैं।

एक अफ्रीकी नैतिक प्रतिमान के रूप में, उबुंटू पूंजीवादी संबंधों, निजी संपत्ति और व्यापक असमानता के साथ संगत नहीं है। इसके बजाय, यह विश्वास सतगर द्वारा 'साम्राज्यवादी पारिस्थितिकी विनाश' कहे जाने वाले के सामने एकजुटता और उपनिवेशवाद के उन्मूलन की सक्रियता की मांग करता है। उबुंटू की पारिस्थितिक नैतिकता ने ''पोस्ट–एक्स्ट्रेक्टिविज्म की कट्टरपंथी धारणा को जन्म दिया है, यानी, विनाशकारी पूंजीवादी संचय और उसके संकटों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते वाले जीवाश्म ईंधन और खनिजों को भावी पीढ़ियों के लिए पीछे छोड़ना''।

एक अफ्रीकी पर्यावरण–नारीवादी परिप्रेक्ष्य से:

> *''उबुंटू पर्यावरण नैतिकता प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर देती है जिन्हें पारंपरिक रूप से नैतिक रूप से महत्वहीन माना जाता है – जैसे कि गैर–मानव सजीव प्राणी – देखभाल, श्रद्धा, दयालुता के साथ और उन्हें नैतिक विचार प्रदान करते हैं। साथ ही, उबुंटू में यह पारिस्थितिकी नारीवादी आयाम यह दर्शाता है कि उबुंटू के गुणों से उत्पन्न होने वाले समान मूल्य – जैसे कि देखभाल, अच्छाई और श्रद्धा – प्रकृति के गैर–जीवित पहलुओं जैसे कि भौतिक प्रकृति, पौधों और जल निकायों को भी दिए जा सकते हैं या उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं जिनमें जरूरी नहीं कि चेतना हो।*

अफ्रीकी ग्रामीण और स्वदेशी महिलाओं द्वारा अपने क्षेत्रों, अपनी स्वायत्तता, अपने उत्पादन के तरीकों, अपने सामुदायिक संबंधों और प्रकृति के साथ अपने अन्योन्याश्रित संबंधों की रक्षा के लिए पहले से ही जीवन के विकल्प प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिसके बिना वे अत्यधिक विनाशकारी निष्कर्षणवादी मॉडल के खिलाफ जीवित नहीं रह सकतीं। ऐसे जीवन विकल्पों की पहचान उन तरीकों से की जा सकती है जिनसे वे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, आदान–प्रदान, देखभाल और पुनर्जनन करते हैंय हमारे परिवारों और समुदायों का पोषण करती हैंय हमारे समुदायों में सहयोग करती हैं, आदि। जैसा कि वूमिन ने कहा है, ''अफ्रीका की अधिकांश महिलाएँ, जो जलवायु और पारिस्थितिक संकट का बोझ उठाती हैं और जिन्होंने इस समस्या में सबसे कम योगदान दिया है, निष्कर्षणवादी पितृसत्ता के प्रति अपने गहन पारिस्थितिकी नारीवादी प्रतिरोध में, एक विकास विकल्प का अभ्यास और प्रस्ताव कर रही हैं जिसका सभी मानवता को सम्मान करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए यदि हमें और पृथ्वी को जीवित रहना है''।

ठोस शब्दों में, एक अलग भविष्य के लिए न्यायसंगत और संधारणीय विकल्प, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के वास्तव में संधारणीय तरीकों के साथ, उबंटू के दर्शन पर आधारित लोगों के बीच सामूहिक एकजुटता और साझाकरण पर केंद्रित होंगे, में अफ्रीकी पारिस्थितिकी–नारीवादियों द्वारा प्रस्तावित तत्वों की एक श्रृंखला शामिल होगी। सबसे पहले, वे कृषि के कृषि–पारिस्थितिक कम–इनपुट मॉडल के माध्यम से खाद्य संप्रभुता को लागू करेंगे। वे वैश्विक दक्षिण में महिलाओं के लिए सहमति की अवधारणा के माध्यम से, कल्याण की ओर अपने स्वयं के मार्ग पर लोगों की संप्रभुता की गारंटी देंगे, जो स्थानीय स्तर पर जीवित विकास विकल्पों को विश्वसनीयता और स्थान देता है। साथ ही, उन विकल्पों को समुदायों और विशेष रूप से महिलाओं के नियंत्रण में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के संधारणीय और विकेन्द्रित सामूहिक रूपों के माध्यम से ऊर्जा संप्रभुता का लक्ष्य रखना होगा, और सभी जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और जलाने को समाप्त करना होगा। वे अभी भी स्वामित्व के सामूहिक रूपों के तहत और स्थानीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अधीन छोटे पैमाने पर, कम प्रभाव वाले निष्कर्षण की अनुमति देंगे। अपने शासन मॉडल के संदर्भ में, उन्हें निर्णय लेने के सभी स्तरों पर सहभागी, समावेशी लोकतंत्र को आगे बढ़ाना होगा, जो समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और प्रभावित समुदायों और विशेष रूप से महिलाओं की पूर्ण और निरंतर सहमति की आवश्यकता को मान्यता देता हो।

वे विकल्प निजी संपत्ति की प्रधानता को भी चुनौती देंगे, उन प्रणालियों का सम्मान और समर्थन करेंगे जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सामूहिक और समूहों द्वारा किया जाता है, और निजीकरण और वित्तीयकरण के खिलाफ लड़ाई के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में आम संपत्तियों का सक्रिय विस्तार किया जाता है। और वे पारंपरिक वैश्विक उत्तर और दक्षिण में अमीर और मध्यम वर्गों की ओर से विकास में कमी और कम उपभोग वाली जीवनशैली में तेजी से बदलाव को बढ़ावा देंगे और लागू करेंगे। ■

सभी पत्राचार जो रैंड्रियामारो को <randriamarozo@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> ग्वाटेमाला में लोकतंत्र के लिए 106 महत्वपूर्ण दिनों का वृतांत

एना सिल्विया मोनजोन, लैटिन अमेरिकी सामाजिक विज्ञान संकाय (FLACSO) ग्वाटेमाला द्वारा

'ग्वाटेमाला एक नए वसंत का हकदार है।' क्रेडिट : कार्लोस चोक।

तीन दशकों के सैन्य शासन और एक सशस्त्र संघर्ष के बाद जिसमें जिंदगियाँ गंवाने, लापता होने और हिरासत में लिए जाने के मामले में भारी नुकसान हुआ, 1985 में ग्वाटेमाला ने नागरिक शासन में वापसी के बाद से, 2023 में, सबसे जटिल चुनावी प्रक्रियाओं में से एक का अनुभव किया। बाईस उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए लिए नामांकित किये गए थे, जिसमें रूढ़िवादी नेशनल यूनिटी ऑफ होप (UNE) और प्रगतिशील सेमिला पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को दूसरे दौर में आगे बढ़ाया। हाल ही में इसकी स्थापना और इस तथ्य को देखते हुए कि यह चुनावों में शीर्ष पदों में से नहीं थी, सेमिला पार्टी की सफलता आश्चर्यजनक थी। 25 जून को पहले दौर के बाद, और 20 अगस्त को दूसरे दौर के आयोजन की घोषणा के साथ, दक्षिणपंथी क्षेत्रों से एक ठोस प्रतिक्रिया शुरू हुई, जो अभिजात वर्ग के हितों और राष्ट्रीय सेना के सबसे विद्रोही क्षेत्रों के हितों का जवाब देती है।

> >

सेमिला पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बर्नार्डो एरेवालो और करिन हेरेरा पर हमला करने के लिए अपनाई गई रणनीति एक कानूनी योजना थी, जो दिखाती है कि न्याय संस्थाओं को किस हद तक सहयोजित किया गया था। एक निराधार शिकायत, एक अपूर्ण जांच और एक न्यायाधीश की पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों, जिसने चुनावी कानून के बजाय आपराधिक कानून के मानदंडों को लागू किया, के आधार पर मीडिया ने चुनावी धोखाधड़ी की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। सेमिला पार्टी को निलंबित करने के लिए अनुरोध किए गए। इस क्रूर हमले के बावजूद, सेमिला ने दूसरे दौर में 58: वोट के साथ निर्विरोध जीत हासिल की: यह नागरिकों के बीच बदलाव की इच्छा का संकेत है, जो भ्रष्टाचार और सहयोजितता से थक चुके हैं जिसने कानून के शासन का उल्लंघन किया है, राष्ट्रीय खजाने को खाली कर दिया है और लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है।

> ''नए वसंत'' के सामने तख्तापलट के प्रयास

नागरिकों का उत्साह सड़कों पर एक नारे के साथ व्यक्त किया गया, जिसमें ''नए वसंत'' की संभावना को दर्शाया गया, जो 1944 की क्रांति का संकेत था, जो लगभग एक सदी के तानाशाही शासन के बाद देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके अलावा, उस लोकतांत्रिक वसंत का नेतृत्व डॉ. जुआन जोस एरेवलो बरमेजो ने किया था, जो वर्तमान राष्ट्रपति के पिता और सेमिला पार्टी के नेता हैं, और जो संयोग से एक समाजशास्त्री हैं। इस संयोग को कई लोगों ने संस्थागत क्षय और असहमति के दमन के अधीन एक देश में आवश्यक तत्काल परिवर्तनों के लिए एक अच्छे शगुन के रूप में देखा, खासकर पिछले दशक में।

संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने सेमिला पार्टी के खिलाफ न्यायिक साजिश में शामिल होकर, सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल पर दबाव बढ़ा दिया जब उसने विजयी राष्ट्रपति टिकट को वैध बताने वाले आधिकारिक चुनाव परिणाम घोषित किए। न्यायिक उत्पीड़न के हिस्से के रूप में, सितंबर 2023 में, ट्रिब्यूनल के मुख्यालय पर विशेष अभियोजक के दण्ड से छूट के खिलाफ छापा मारा गया, एक अप्रत्याशित कार्य जिसे लोकप्रिय वोट का उल्लंघन बताया गया, क्योंकि लोक अभियोजक के कार्यालय के कर्मियों ने – बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के – नागरिकों द्वारा डाले गए मतपत्रों वाले कई बक्से हटा दिए।

इस परिदृश्य के कारण नागरिकों ने अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उन्होंने सरकार का विरोध और आलोचना करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वालों के खिलाफ इस और अन्य आपराधिक उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई की है। इन अधिकारों का प्रयोग करने के कारण लगभग सौ पत्रकार, न्यायाधीश, अभियोजक और कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा के लिए निर्वासन में चले गए हैं। अन्य, जैसे कि वकील और पूर्व भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक वर्जीनिया लापरा और पत्रकार जोस रूबेन जमोरा को उनके मामलों की गंभीरता से पुष्टि किए बिना एक साल से अधिक समय तक प्री–ट्रायल हिरासत में रखा गया है और इसलिए उन्हें राजनीतिक कैदी माना जाता है।

इसके अलावा, 16 नवंबर, 2023 को, लोक अभियोजक कार्यालय ने ''ऑक्यूपेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सैन कार्लोस डी ग्वाटेमाला'' (*टोमा डे ला यूएसएसी*) के नाम से जाने जाने वाले मामले में विश्वविद्यालय के पांच छात्रों और एक युवा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाए। यह कब्जा 2022–26 की अवधि के लिए नए रेक्टर के चुनाव के खिलाफ एक विरोध था, जो एकमात्र सार्वजनिक राज्य विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग कर रहा था। इस अधिकार को उन लोगों द्वारा हड़प लिया गया था जो विश्वविद्यालय के रेक्टरशिप का प्रयोग करने के लिए कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करते थे और जिन्होंने 2022 में अवैधताओं, धमकियों और बल के प्रयोग का सहारा लेकर खुद को थोपा था। इस मामले में, लोक अभियोजक के कार्यालय ने वर्तमान उपाध्यक्ष, करिन हेरेरा, जो चुनाव अभियान की शुरुआत तक, रसायन विज्ञान संकाय में प्रोफेसर थे, को विश्वविद्यालय के हड़पने वालों के साथ जोड़ने की कोशिश की। जैसा कि देखा जा सकता है, ''तख्तापलट समझौते'' ने सेमिला की चुनावी जीत को अवैध ठहराने और रद्द करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

> जनता द्वारा लोकतंत्र की रक्षा की गई

2 अक्टूबर 2023 को, ग्वाटेमाला के 48 कैंटोन (सांप्रदायिक प्राधिकारियों की एक प्रणाली, जिसकी उत्पत्ति टोटोनीकापान के किचे लोगों के इतिहास में हुई है) के प्राधिकारियों ने, जो आमतौर पर राष्ट्रीय राजनीति से अनुपस्थित रहते हैं, सार्वजनिक रूप से अटॉर्नी जनरल, दो जांच अभियोजकों और उस न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग की, जिन्होंने सेमिला पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और जिन्होंने नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों के उल्लंघन का समर्थन किया था।

अनुपालन करने से इनकार करने का सामना करते हुए, 48 कैंटन के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मार्च शुरू किया जिसने राजधानी में लोक अभियोजक के कार्यालय तक 200 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें अन्य शहरों और कस्बों से सामाजिक आंदोलनों और अधिकारियों से उनके साथ शामिल होने का आह्वान किया गया। तर्क तीन गुना था: लोक अभियोजक द्वारा समर्थित न्यायिककरण चुनावी कानून, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, की अवहेलना करके लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा थाय लोगों की इच्छा की अवहेलना की जा रही थीय और संघर्ष केवल सेमिला पार्टी से कहीं अधिक था।

यह हाल के दशकों में ग्वाटेमाला में सामाजिक लामबंदी में एक गुणात्मक प्रगति थी। देश के सबसे हालिया महत्वपूर्ण नागरिक आंदोलन में, जो 2015 में उच्च स्तरीय सरकारी प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, लामबन्दियाँ राजधानी तक ही सीमित थीं। 2015 में उच्च–स्तरीय सरकारी उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लामबंदी राजधानी तक ही सीमित थी। अब, नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी अधिकारियों से आ रहा था, जिसमें 48 कैंटन अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जिसमें राजधानी शहर के कुछ क्षेत्रों के अलावा सोलोला, इक्सिल्स, काकचिक्वेल्स, क्यू'एक्ची, चोर्टिएस और जिनकास के अधिकारी शामिल थे।

अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह से, स्वदेशी अधिकारियों के समर्थन में हजारों लोग देश की मुख्य सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इन सड़कों को 80 अलग–अलग बिंदुओं पर अवरुद्ध कर दिया। संगठन का स्तर प्रभावशाली था। लोक अभियोजक के कार्यालय के बाहर लगातार उपस्थिति बनाए रखने के लिए शिफ्टों को अपनाया गया, जिससे प्रतिदिन 300 से 400 लोगों के लिए भोजन और आवश्यक परिस्थितियों की गारंटी मिली। यह कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने राजधानी में लोगों के 100 से अधिक दिनों तक ''एकजुटता रसोई'' चलाई।

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी आबादी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई अमेरिकी शहरों में ग्वाटेमाला वाणिज्य दूतावासों के सामने हर हफ्ते दान और राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से खुद को व्यक्त किया, जैसा कि कनाडा और यूरोप में भी हुआ। सामाजिक नेटवर्क की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।

>>

शहर में नाकेबंदी कई गुना बढ़ गई, जिसका नेतृत्व पड़ोस के समूहों, धार्मिक समूहों, छात्रों, अनौपचारिक फेरीवालों और नियमित श्रमिकों ने किया, जिन्होंने सड़कों पर नृत्य और योग कक्षाएं, लॉटरी खेल, स्वतःस्फूर्त संगीत कार्यक्रम और सड़क वार्ता जैसी मौलिक गतिविधियों का आयोजन किया। राजनीतिक विरोध के अलावा, इसका उद्देश्य परिवहन, सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा की कमी से जूझ रहे शहर में सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त करना था।

लोक अभियोजक के कार्यालय के सामने की सड़क निंदा, विश्लेषण, माया समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, खेल, गायन, नृत्य और सभी स्वदेशी भाषाओं में भाषणों के लिए एक लोकतांत्रिक स्थान बन गई। इस तात्कालिक शिविर में, विचार और प्रस्ताव उबल पड़े, और महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने खुद को व्यक्त किया, जो तथाकथित ''तख्तापलट करने वालों के समझौते'' के हर कदम पर ध्यान से नजर रखते थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल का कार्यालय, मिलीभगत करने वाले न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और अपने मंत्रिमंडल के साथ खुद राष्ट्रपति शामिल थे।

पुलिस की प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए घुसपैठियों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद विरोध शांतिपूर्ण रहा। 106 दिनों के विरोध प्रदर्शन में, देश के दक्षिण में सैन मार्कोस राजमार्ग पर सशस्त्र लोगों द्वारा केवल एक बार आक्रमण किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए।

इस अवधि के दौरान अन्य महत्वपूर्ण कर्त्ता अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS), अमेरिकी सरकार और यूरोपीय संघ थे। इन सभी ने विशिष्ट मिशनों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया का अनुगमन किया, जिसने दो मतपत्रों की पारदर्शिता और परिणामस्वरूप, दो निर्वाचित उम्मीदवारों की वैधता पर रिपोर्ट की। OAS ने सेमिला पार्टी के– अक्सर समझ से परे और सभी अनुपातों से बाहर– उत्पीड़न, अनगिनत न्यायिक कार्यवाहियों और मतदाताओं के अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बयान जारी किए।

ग्वाटेमाला की स्थिति कई असाधारण बैठकों का विषय रही और 20 अगस्त के मतदान और 15 जनवरी, 2024 को बर्नार्डो एरेवलो के शपथ ग्रहण के बीच की लंबी अवधि के दौरान ओएएस महासचिव के मध्यस्थता मिशन की निरंतर उपस्थिति रही। एक पहलू जिस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह है इस मिशन के तत्वावधान में एक संवाद की स्थापना, जिसने स्वदेशी अधिकारियों और गणराज्य की सरकार को समान स्तर पर रखा। हालाँकि इस संवाद से स्वदेशी लोगों के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन इसने उनके नेतृत्व और नागरिकों की मांगों को एक महत्वपूर्ण समर्थन दिया।

ग्वाटेमाला में लोकतंत्र के लिए ये 106 महत्वपूर्ण दिन अनिश्चितता, बदलाव की इच्छा और संस्थाओं की कमजोरी के बीच बीते। स्थापित शक्तियों के हमले ने नए राष्ट्रपति जोड़े के शपथ ग्रहण के क्षण तक नागरिकों के बीच चिंता का माहौल बनाए रखा। नए वसंत को रोकने के प्रयासों के बावजूद, हम जीवित रहे...

एक सौ छह दिन
यादों को समेटने के लिए
ऊतकों का पुनर्निर्माण
सभी भाषाओं में
मंजिल ले
गरिमा की पुनः पुष्टि
खुशी को अधिकार के रूप में पुनः प्राप्त करना
नागरिक जागृति
चालबाजी का रूपांतरण,
सड़कों पर लाशों का विस्फोट
जो इतिहास के अर्थ पर विवाद करते हैं
एक सौ छह दिन
जिसने पीछे नहीं हटने वाली अंतरात्मा
पर अपनी छाप छोड़ी है। ■

सभी पत्राचार एना सिल्विया मोनजोन को <amonzon@flacso.edu.gt>
ट्विटरः @AnaSilviaMonzo1 पर प्रेषित करें।

> चिली में संवैधानिक प्रक्रिया की विफलता के बाद सामाजिक आंदोलन

कारमेन गेमिटा ओयारज़ो विडाल, यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा डे चिली, चिली द्वारा

'नवउदारवादी मॉडल चिली में जन्म लेता है और यहीं खत्म होता है।'
फोटो : मोइसेस पामरो।

अक्टूबर 2019 में, चिली ने अपने समकालीन इतिहास की सबसे बड़ी लामबंदी की शुरुआत का अनुभव किया। विरोध के इस चक्र के चिली के समाजशास्त्रियों द्वारा कई आकलन किए गए थे, लेकिन तीन मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। पहला, जो काफी व्यापक है, यह सुझाव देता है कि 2019 का विद्रोह सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए आह्वान करने वाली लामबंदी के पिछले चरण के चरम (और समापन) को चिह्नित करता है। उस चक्र की शुरुआत 2011 में छात्र आंदोलन के साथ हुई थी, जिसकी सामाजिक माँगों को एक नए लोकतांत्रिक आदेश के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। दूसरी व्याख्या विरोध के स्वायत्तता को संदर्भित करती है और संस्थागत राजनीतिक कर्त्ताओं, जैसे यूनियनों और राजनीतिक दलों से सामाजिक लामबंदी की दूरी का वर्णन करती है। चिली के मामले में, संस्थागत राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के बीच दरार की अधिकतम अभिव्यक्ति 2021 के संवैधानिक सम्मेलन में हुई थी। तीसरा, यह थीसिस है कि 2019 और 2021 के बीच चिली के समाज द्वारा अनुभव की गई राजनीतिकरण की प्रक्रिया एक विरोधाभासी और जटिल घटना थी जो नवउदारवाद के रोजमर्रा के अनुभव के विरोधाभासों से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति, एक ओर, व्यक्तियों और उनकी कार्रवाई की क्षमताओं की एक मजबूत छवि और दूसरी ओर, अन्याय और असमानता की धारणा पैदा करती है। व्यक्तिपरक असुविधा के राजनीतिकरण की थीसिस चिली के समाज की नवउदारवाद के लिए एक वैकल्पिक सामूहिक परियोजना की कल्पना करने में कठिनाई को समझाएगी।

> 2021 का संवैधानिक अनुभव और 2022 में हार

2019 के अंत में चिली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद, देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने एक नई संविधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए नागरिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। अक्टूबर 2020 में, एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था जिसमें 78% से अधिक मतदाताओं ने एक संविधान प्रक्रिया की शुरुआत को मंजूरी दी थी, जिसे मई 2021 में चुने गए ''संवैधानिक सम्मेलन'' द्वारा संचालित किया जाएगा। यह पहली बार था कि ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत सामाजिक समूहों (महिलाएं, स्वदेशी लोग और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के सदस्य) के प्रतिनिधियों ने खुद को एक संस्थागत स्थान में पाया, जिसमें उनके पास निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक प्रभाव था। यह भी

> >

पहली बार था कि चिली का संविधान सभी चरणों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संविधान प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया।

निर्वाचित संवैधानिक सम्मेलन की संरचना में स्वतंत्र उम्मीदवारों की प्रमुखता थी, जिन्होंने 155 सीटों में से 48 सीटें प्राप्त कीं, और प्रगतिशील बलों के विखंडन के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के प्रयास किये गए। संवैधानिक प्रक्रिया में बहुत अधिक भरोसा था, जिसे वामपंथियों ने 2019 के विरोध प्रदर्शनों के प्राथमिक राजनीतिक परिणाम और देश को फिर से स्थापित करने और ऑगस्टो पिनोशे (1973–89) की तानाशाही के दौरान स्वीकृत 1980 के संविधान को उखाड़ फेंकने के एक वास्तविक अवसर के रूप में देखा।

संवैधानिक बहस ने राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर तनाव पैदा किया, जिन्हें पिछली अवधि में हल्के में लिया गया था –जैसे कि चिली के समाज का समरूप चरित्र, क्षेत्र की एकता और राष्ट्र की अवधारणा। इसने एकजुटता पर आधारित सामाजिक अधिकारों की धारणा भी पेश की।

संवैधानिक सम्मेलन के काम के परिणामस्वरूप, जुलाई 2022 में, चिली के लिए एक नए संविधान के प्रस्ताव की प्रस्तुति हुई, जिसे दो महीने बाद जनता द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। मूल लेख ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को मान्यता दी और उन्हें शामिल किया तथा इसका एक पारिस्थितिक और बहुराष्ट्रीय दृष्टिकोण था। यद्यपि, 4 सितंबर 2022 को संविधान को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए आयोजित जनमत संग्रह में, जिसमें 85% से अधिक आबादी ने भाग लिया (यह चिली के इतिहास में सबसे अधिक भागीदारी वाली चुनावी प्रक्रिया थी), प्रस्तावित पाठ को 38% पक्ष में मतों की तुलना में 62% मतों से अस्वीकृत कर दिया गया।

> हार की भावनाएँ और कारण

चुनाव के नतीजों ने कार्यकर्ताओं और सामाजिक आंदोलनों को हैरान कर दिया। जब वे उस पल के प्रभाव को याद करते हैं, तो वे बताते हैं कि कन्वेंशन के महीनों के काम इतने तीव्र थे कि सदस्य समय रहते यह समझने में विफल रहे कि संवैधानिक प्रस्ताव की सामग्री नागरिकों के एक बड़े वर्ग को समझ में नहीं आ रही थी। संवैधानिक चर्चाओं की तीव्रता के बाद, कन्वेंशन के काम के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के केंद्र ने चुनावी अभियान के दौरान ही आम लोगों की नाराजगी को महसूस करना शुरू किया, तब जब प्रक्रिया को बदलने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। सबसे दर्दनाक यह एहसास था कि ''लोग'' उनके साथ नहीं थे। हालाँकि, उन्होंने उस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया; उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि बदलाव की इच्छा प्रबल थी। भावनाएँ और हार के कारण

चुनाव के नतीजों ने कार्यकर्ताओं और सामाजिक आंदोलनों को हैरान कर दिया। जब वे उस पल के प्रभाव को याद करते हैं, तो वे बताते हैं कि कन्वेंशन के महीनों के काम इतने गहन थे कि समय रहते सदस्य यह समझने में विफल रहे कि संवैधानिक प्रस्ताव की सामग्री नागरिकों के एक बड़े वर्ग को समझ में नहीं आ रही थी। संवैधानिक चर्चाओं की तीव्रता के बाद, कन्वेंशन के काम के लिए समर्पित मुख्य कार्यकर्ताओं ने चुनावी अभियान के दौरान ही आम लोगों की नाराजगी को महसूस करना शुरू किया, लेकिन तब तक प्रक्रिया को बदलने के लिए पहले से ही काफी देर हो चुकी थी। यह एहसास सबसे कष्टदायक था कि ''लोग'' उनके साथ नहीं थे। हालाँकि, उन्होंने उस वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दियाय उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि बदलाव की इच्छा प्रबल थी।

जब नतीजे आये तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगे श्रम में शामिल कई कार्यकर्ताओं को लगा कि उन्होंने समय और ऊर्जा बर्बाद की है। अपने शोध में, मैंने कई कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया, जिन्होंने हार को शोक की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया। संविधान प्रक्रिया की चुनावी विफलता ने सामाजिक परिवर्तन की आशा की मृत्यु को चिह्नित किया, जिसके लिए कुछ लोग दशकों से लड़ रहे थे। 2019 की तीव्र लामबंदी के बाद, पिनोशे के संविधान और उसमें निहित सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के मॉडल को समाप्त करने के लिए अंततः सामाजिक और राजनीतिक ताकत मिलने की जबरदस्त उम्मीद थी।

दूसरी ओर, इस प्रक्रिया में शामिल कई कार्यकर्ताओं को लगा कि उन्होंने समय और ऊर्जा बर्बाद की है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के दैनिक जीवन और उनके अनुसार, ''सम्मेलन के बाहर'' क्या हो रहा था, के बीच अंतर एक दिलचस्प पहलू है। बैलेंस शीट के लिए विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के आख्यानों में एक बलिदानी स्वर की जरुरत हैः थकाऊ काम के घंटों की स्मृति, निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के कारण नींद की कमी, और परिवार या अवकाश के समय को स्थगित करना, उन्हें यह महसूस कराता है कि आम जनता ने इस प्रक्रिया में उनके द्वारा लगाई गई सारी ऊर्जा का प्रतिदान नहीं किया।

हार के दर्द के बाद उन मतदाताओं की कृतघ्नता पर गुस्सा आया, जिन्हें नए संविधान द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले सामाजिक परिवर्तन का लाभ मिलना था। मतदाताओं के व्यवहार का आकलन करना और यह जानना कि बहुमत ने प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया, इसने कार्यकर्ताओं के बीच तनाव पैदा कर दिया। नतीजों के तुरंत बाद, सबसे अधिक संदेह करने वाले लोग चुनावी आपदा पर विश्वास नहीं कर पाए। वहीं, सबसे अधिक निराश लोगों ने सोचा कि अज्ञानता और दक्षिणपंथियों द्वारा चलाए गए दुष्प्रचार अभियान ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है । दूसरों ने, लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त प्रयास न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। लेकिन परिणाम स्पष्ट थाः चिली का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां नए संविधान के लिए ''हां'' ने जीत हासिल की हो।

चुनावी पराजय के लगभग दो साल बाद, कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और लोगों की सामान्य समझ के बीच की दूरी पर अधिक गहराई से विचार किया है। जब वे उस जुनून और कड़वाहट को याद करते हैं जिसके साथ कुछ लोगों ने लोकप्रिय वोट को खारिज कर दिया था, तो उनका मानना है कि मतदाताओं के कारणों की अनदेखी करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे बढ़कर, मेरे द्वारा आयोजित समूह साक्षात्कारों के दौरान, प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यदि लोकप्रिय मांगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले लोग उनकी अनदेखी करते हैं, तो राजनीतिक बहुमत का निर्माण असंभव है।

हालाँकि कार्यकर्ता अभी भी प्रक्रिया की विफलता पर अपना दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन अब वे लोगों को आदर्श नहीं बनाने या उनके उद्देश्यों को तुच्छ समझने के महत्व को पहचानते हैं। उनका यह भी मानना है कि राजनैतिक विमर्श के कुछ प्रकार क्यों उन लोगों के लिए अर्थहीन हैं या वे इस प्रकार के परिवर्तन को आगे बढ़ाने में क्यों इच्छुक नहीं हैं को समझने के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की भौतिक चिंताओं के साथ जुड़ना आवश्यक है। इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि एकजुटता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना इतना अवहनीय क्यों है।

>>

जब कार्यकर्ता हार के अन्य कारणों पर चर्चा करते हैं, तो वे अपने नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों के साथ समझौता करने में अपनी कठिनाइयों की भी पहचान करते हैं। सामाजिक लामबंदी के सबसे प्रबल क्षणों के दौरान, उन्हें विश्वास हो गया कि कुछ भी संभव है और यह कि उनके पास पारंपरिक राजनीतिक अभिनेताओं को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त ताकत है। 2021 की अप्रत्याशित चुनावी जीत से प्रबलित होकर, उन्होंने सोचा कि स्थापित पार्टियों के साथ बातचीत करना भी अनावश्यक है।

संवैधानिक प्रस्ताव की कुछ सामग्री की कट्टरपंथी प्रकृति और इसे संयमित करने की आवश्यकता के बारे में, आंदोलनों द्वारा किया गया आकलन यह है कि देश के लिए आवश्यक परिवर्तनों को बढ़ाने के लिए संविधान प्रक्रिया एक ऐतिहासिक क्षण था। यह सब कुछ मांगने और सब कुछ व्यवस्थित और सीलबंद छोड़ने का समय था क्योंकि संसद भविष्य में उन्हें धोखा दे सकती थी। हालांकि, साक्षात्कारकर्ताओं ने माना कि उनके संगठनों की ओर से भी अहंकार और अड़ियलपन था, जिसने अपनी जीत और अपने बहुमत को मूर्त रूप देने की इच्छा से प्रेरित होकर, दूसरों के तर्कों पर बातचीत करने या सुनने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा, एक नए संविधान के लिए राजनीतिक समर्थन के लिए पाठ में विशिष्ट मुद्दों पर सहमति देने से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। 2022 के संवैधानिक प्रस्ताव द्वारा मांगे गए गहरे सामाजिक और संस्थागत परिवर्तनों के लिए पहले से सामाजिक और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता थी। चिली में वह सहमति मौजूद नहीं थी, भले ही आंदोलनों में संविधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ताकत थी।

> क्या सब कुछ खत्म हो गया है? अप्रकट तनाव और क्षेत्रीय बदलाव

हालाँकि सम्मेलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं के समूहों ने पहले ही वैकल्पिक राजनीतिक दल बना लिए हैं (जैसा कि सोलिडारिडाड पैरा चिली के मामले में है) लेकिन सब कुछ यह संकेत देता है कि प्रतिनिधित्व के स्थानों पर विजय और लोकप्रिय आधारों का निर्माण सामाजिक आंदोलनों के लिए एक लंबी और चुनौतीपूर्ण मार्ग होगा। अब तक, राजनीतिक विखंडन को दूर करने का कोई व्यवहार्य तरीका नहीं है जो पूर्व संवैधानिक सम्मेलन की विशेषता थी। शासक दलों के प्रति आंदोलनों का अविश्वास बताता है कि भविष्य में गठबंधन बनाना बहुत मुश्किल होगा।

अपने आंदोलन की पहचान को संरक्षित रखने की उत्सुकता में प्रादेशिक शर्त सबसे मजबूत दिखती है। क्षेत्र के अनेक अर्थ हार के बाद आंदोलनों की प्राथमिकताओं और अन्य कर्त्ताओं (जिसमें वाम–पंथ दल भी सम्मिलित हैं) के साथ सहयोग और संघर्ष के संबंधों को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। चिली के वर्तमान आंदोलनों में हम कम से कम तीन प्रासंगिक अर्थों को पहचान सकते हैं। पहला, भौगोलिक और सामाजिक–पारिस्थितिक स्थान के रूप में परिभाषित क्षेत्र एक व्यापक पर्यावरणीय जागरूकता दिखाता है जो कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी व्यापक है और न केवल उन लोगों के बीच जो वर्तमान में पर्यावरण संगठनों के साथ काम करते हैं या सहयोग करते हैं। इसके अलावा, यह चिली में क्षेत्रीय विविधता के महत्व को उजागर करता है। देश के उत्तर, मध्य या दक्षिण में रहना अलग है। छोटे समुदायों को बड़े, स्थानिक और सामाजिक रूप से अलग–थलग शहरों की तुलना में एक ही पहचान वाले सामूहिक के रूप में खुद को सोचने में कम कठिनाई होती है।

क्षेत्र एक राजनीतिक स्थान और एक संबंधित समूह के रूप में भी उभरता है। सामाजिक आंदोलन अपने समर्थन के सामाजिक आधारों की पहचान करते हैं और और यह भी कि ''क्षेत्रीय कार्य'' के लक्ष्य कौन होंगे। सामाजिक–राजनीतिक स्थानों के रूप में, क्षेत्र विविध लोगों और दैनिक सह–अस्तित्व के रूपों को समाहित करते हैं जिसमें संगठित समूह खुद को पहचानते हैं। इस दृष्टिकोण से, क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं को परिभाषित करने वाली सार्थक अंतःक्रियाओं का एक स्थान है जो दूसरों द्वारा उन्हें वैध वार्ताकार के रूप में पहचाने जाने की अनुमति देता है।

अंत में, मापुचे समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ काम करने से क्षेत्र का तीसरा अर्थ सामने आया। मापुचे समुदायों के लिए, क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ उनकी पूरी जीवन शैलीः भौतिक जीवन (भूमि और पानी तक पहुँच), राजनीतिक जीवन (सह–अस्तित्व के नियमों का एक समूह), और आध्यात्मिक जीवन, दांव पर लगी होती है। भूमि और नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और समुदायों को उनके पूर्वजों की स्मृति से जोड़ती हैं। इसलिए, यह समझते हुए कि मापुचे उनका क्षेत्र है, राजनीतिक सह–अस्तित्व का स्थान समुदायों का है। समुदाय उन परिवारों के लिए संगठन का प्राथमिक साधन है जो एक क्षेत्र साझा करते हैं। वे ऐसे छोटे समुदाय हैं जिनमें सह–अस्तित्व एक राजनीतिक प्राधिकरण (लोंको) और एक आध्यात्मिक प्राधिकरण (माची) द्वारा प्रशासित होता है।

चिली में संवैधानिक प्रक्रिया की हार के बाद सामाजिक आंदोलनों की राजनीतिक कार्रवाई को समझने के लिए क्षेत्र के ये अलग–अलग अर्थ महत्वपूर्ण हैं। राजनैतिक संलग्नता तभी आती है जब आंदोलनों के प्रतिनिधियों को ''जमीनीं'' अथवा ''लोगों '' को प्रतिस्थापित करते हुए राजनीतिक जुड़ाव होता है। हालाँकि, यह एक छोटा राजनीतिक स्थान है जिसमें उप–सांस्कृतिक या सामुदायिक संबंध प्रबल होते हैं। सामाजिक आंदोलन ऐसे प्रमाण बन सकते हैं जिनमें सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावित करने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन, राजनीति में, दो साल का समय बहुत लंबा होता है। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संबंधों और आगामी निगमीय और संसदीय चुनावों में नए मध्यस्थों के निर्माण में ये आंदोलन कितने सफल होते हैं को देखने के लिए इंतजार करना और देखना आवश्यक है।यह इंतजार करना और देखना आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों और नई मध्यस्थता के निर्माण में आंदोलन कैसे आगे बढ़ते हैं जो आगामी नगरपालिका और संसदीय चुनावों और प्रतिनिधित्व के विभिन्न स्थानों में प्रतिध्वनित हो सकते हैं। ■

सभी पत्राचार कारमेन गेमिटा ओयार्जो विडाल को
<carmen.oyarzo@uautonoma.cl> पर प्रेषित करें।

> माइली की सरकार के प्रतिरोध की शुरुआत

जूलियन रेबन, ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय और कश्वनिसेट, अर्जेंटीना द्वारा

श्रेय : एमरजेन्टेस, CC BY-NC 4.0.

वर्ष 2023 के अंत में, जेवियर माइली ने अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया, तथा खुद को इतिहास में पहले स्वतंत्रतावादी राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत किया। अपने उद्घाटन सम्बोधन में, उन्होंने कांग्रेस और उपस्थित संसद सदस्यों की ओर पीठ करके अपने एकत्रित समर्थकों से बात की। उन्होंने राज्य और ''जाति'': एक अस्पष्ट शब्द जो पारंपरिक राजनेताओं से लेकर ट्रेड यूनियनवादियों और सार्वजनिक कर्मचारियों तक के कथित रूप से विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक हस्तियों को संदर्भित करता है, में समायोजन शुरू करके अर्जेंटीना के पतन को समाप्त करने का वादा किया। उपस्थित लोगों ने चौक से ''नो हे प्लाटा'' (कोई पैसा नहीं है) के उल्लासपूर्ण नारों के साथ उनका जवाब दिया।

माइली की सरकार के पहले 100 दिनों को सभी रूढ़िवादी चीजों का उन्मादी समायोजन चिह्नित करता है। हालाँकि, समायोजन का भार ''जाति'' के बजाय एक व्यापक और विविध सामाजिक स्पेक्ट्रम पर पड़ा। जैसा कि माइली कहते हैं, राजकोषीय अधिशेष बनाने के उद्देश्य से उनके ''चेनसॉ'' की कार्रवाई ने हजारों लोगों की छंटनी, विभिन्न एजेंसियों के बंद होने, सार्वजनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने और सब्सिडी को समाप्त करने का काम किया है। माइली ने शॉक थेरेपी भी लागू की जिसे उन्होंने ''ब्लेंडर'' कहा है, जिसमें एक दिन में अर्जेंटीना की मुद्रा का 50% से अधिक अवमूल्यन हुआ, जिससे मुद्रास्फीति दोगुनी से अधिक हो गई। इससे सेवानिवृत्त और श्रमिकों (लगभग 30%) की क्रय शक्ति में भारी कमी आई, साथ ही पेसो में बचत खत्म हो गई, जो नकारात्मक ब्याज दरों के कारण और सार्वजनिक बजट भी नष्ट होने से अधिक संयोजित हो गया।

> माइली कौन है?

जेवियर माइली एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक व्यवस्था से बाहर के व्यक्ति हैं। अपनी हंगामेकारी शैली के लिए प्रसिद्ध टेलीविजन टिप्पणीकार के रूप में, उन्होंने बार–बार मंदी से चिह्नित देश में बढ़ती मुद्रास्फीति के उपाय के रूप में डॉलरीकरण का प्रस्ताव रखा। संस्थागत राजनीति में प्रवेश करने के कुछ वर्ष पश्चात, जब उनके पास कोई राजनीतिक दल नहीं था, उन्होंने दो गठबंधनों को हराया जो सरकार में बारी–बारी से आ रहे थे और देश को ध्रुवीकृत कर रहे थे: राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बाईं ओर, *यूनियन पोर ला पैट्रिया–पेरोनिस्मो*, और दाईं ओर, *जुंटोस पोर एल कैम्बियो*।

अपनी अल्प संस्थागत शक्ति के बावजूद– संसद में यह केवल एक लघु अल्पसंख्यक हैं और यह किसी भी प्रांत पर शासन नहीं करता है– राजनीतिक गठबंधन लिबर्टाड अवांजा (''फ्रीडम एडवांसेज'') साहसपूर्वक आर्थिक क्षेत्र में चरम नवउदारवाद और राजनीतिक परिदृश्य पर अधिनायकवाद के पुनः–आधारभूत एजेंडे का प्रस्ताव देता है। एक आक्रामक शैली के साथ, जो मुख्य रूप से सामाजिक नेटवर्क और मीडिया के माध्यम से लागू होती है, माइली का राजनैतिक आख्यान ''जाति'' को उसके शत्रु के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, वह मुख्य रूप से लोकलुभावनवाद–पेरोनिज्म, वामपंथ, नारीवाद, ट्रेड यूनियनवाद और सामाजिक आंदोलनों पर हमला करते हैं। इस बीच, उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों के ऐतिहासिक राजनेताओं को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया है और बड़े आर्थिक समूहों के बीच समर्थन जुटाया है।

> माइली विरोधी प्रदर्शनों का उदय

माइली द्वारा लागू किए गए समायोजनों को, विरोध–प्रदर्शनों पर सरकार की प्रतिबंधात्मक और दमनकारी नीति के बावजूद सड़कों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही, सुरक्षा बलों को सार्वजनिक सड़कों पर प्रदर्शनों को सीमित करने की अनुमति देते हुए एक प्रतिरोध–विरोधी प्रोटोकॉल पेश किया गया। देश के नागरिक कार्रवाई के प्रदर्शनों की सूची में विरोध का एक पारम्परिक रूप ''सड़कों को अवरुद्ध करने'' पर प्रतिबंध, साथ ही सामाजिक संगठनों से सुरक्षा संचालन की लागत वसूलना और लोगों को प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए मजबूर करने के लिए समूहों द्वारा कथित जबरदस्ती की गुमनाम रूप से निंदा करने के लिए समर्पित चौनलों का निर्माण, कुछ अनुशासनात्मक

>>

उपाय हैं जिन्हें स्थापित किया गया। माइली के पदभार ग्रहण करने के कुछ दिनों के भीतर, सरकार ने अर्थव्यवस्था को विनियमित करने, दर्जनों कानूनों को समाप्त करने और श्रम से लेकर आवास और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए डिक्री ऑफ नेसेसिटी एंड अर्जेन्सी (DNU) पर हस्ताक्षर किए थे। घोषणा के बाद, देश के मुख्य शहरों की सड़कों पर स्वतःस्फूर्त विरोध और प्रदर्शनों ने नव–पारित प्रतिरोध–विरोधी प्रोटोकॉल को लागू करने की कठिनाई का सबूत दिया।

इसके बाद, सरकार ने संसद में एक बहुउद्देश्यीय ''ओमनीबस'' विधेयक प्रस्तुत करने की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रपति के लिए असाधारण शक्तियों, निजीकरण और विरोध के अधिकार पर सीमाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर 600 से अधिक लेख शामिल हैं। जैसा कि इस तरह के नवउदारवादी सुधारों के लिए विशिष्ट है, इसके कारण होने वाले व्यापक सामाजिक उथल–पुथल से उत्पन्न प्रतिरोध के विभिन्न स्तर थे। ट्रेड यूनियनों और सामाजिक आंदोलनों ने इस प्रक्रिया में अगुवाई की। उन्होंने जनवरी के मध्य में एक आम हड़ताल की जिसने पूरे देश में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटाई। आम हड़ताल से पहले और बाद में सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए। इनमें बर्खास्तगी के खिलाफ क्षेत्रीय हड़तालें और वेतन वृद्धि की मांग, सामाजिक नीति पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सामाजिक आंदोलनों द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन, और संस्थानों और संगठनों की एक श्रृंखला में कटौती के खतरे और उनके कार्यान्वयन के खिलाफ सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन शामिल थे। 8 मार्च को लाखों महिलाओं ने माइली की आर्थिक योजना और लैंगिक नीति को खत्म करने के खिलाफ मार्च किया।

सड़कों पर प्रतिरोध सरकार के सामाजिक विरोध में एक नई प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका सामना राजनीतिक विरोध की कमजोरी से होता है, मुख्य रूप से पेरोनिज्म, जिसे पिछले चुनाव में पराजित किया गया था और समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब तक, इस प्रतिरोध ने सामान्य पुनर्गठन को नहीं रोका है, हालांकि इसके मार्ग में बाधाएं खड़ी की गई हैं। न्यायपालिका ने आंशिक रूप से DNU को रोक दिया, विशेष रूप से इसके श्रम अध्याय को; ओमनीबस एक्ट का पहला संस्करण कांग्रेस में विफल रहा, मुख्य रूप से राष्ट्रपति की अक्षमता या वार्ता समर्थक विपक्ष के साथ संशोधनों पर बातचीत करने से इनकार करने के कारण। हालाँकि, क्रय शक्ति का नुकसान जारी है। सरकार पहल को बरकरार रखे है, और हर हफ्ते अधिग्रहित अधिकारों के उन्मूलन के साथ नई कटौती की घोषणा की जाती है।

माइली की सरकार की शुरुआत के तुरंत बाद सामाजिक प्रतिरोध पैदा हुआ, जिसमें विरोध प्रदर्शनों ने सार्वजनिक स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके विपरीत, सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से सड़कों पर समर्थन नहीं जुटाया है। यह वह चरम दक्षिणपंथी नहीं है जो सामाजिक आंदोलन के रूपों को आकर्षित करता है। हालांकि, अर्जेंटीना में विरोध के ऐतिहासिक मापदंडों को देखते हुए और सबसे बढ़कर, शिकायतों की सीमा और प्रभावित होने वाले लोगों की विविध प्रकृति को देखते हुए, पैमाने के संदर्भ में यह, कम से कम अभी के लिए, विरोध के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक नहीं है; न ही प्रतिरोध के विभिन्न रूप एकजुट मोर्चे में साथ हुए हैं।

> हाल के विरोध प्रदर्शन: विशेषताएँ, चुनौतियाँ और रुझान

विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाली शिकायतों की तीव्रता के बावजूद, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से ऐसा लगता है कि वे विकसित नहीं होंगे। विशेष रूप से, प्रतिक्रियावादी सरकार अपने पसंदीदा शत्रुओं के रूप में विशिष्ट कर्त्ताओं को चुनती है। यह इनसे बातचीत करने से इनकार करती है और इनकी संगठनात्मक शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करती है – उदाहरण के लिए, ट्रेड यूनियनों की खुद का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता को बदलकर – और संघर्ष के वे रूप जिनमें वे शामिल हो सकते हैं, राज्य द्वारा सहन किए जाने वाले और अनुमत लोगों को सीमित करके तथा सक्रिय रूप से दमन को बढ़ावा देकर। साथ ही, सरकार इन समूहों पर अपने विचार–विमर्श और संचार तंत्र को केंद्रित करती है, उन्हें गंभीर स्थिति और सामाजिक अशांति के लिए जिम्मेदार के रूप में चित्रित करने का प्रयास करती है। पेरोनिज्म, जो अधिकांश आयोजकों के लिए संदर्भ का विशिष्ट बिंदु है, की हार को देखते हुए अब विरोध प्रदर्शनों के लिए एक राजनीतिक संदर्भ बिंदु स्थापित करने में भी स्पष्ट कठिनाई है। पिछली प्रगतिशील सरकार की विफलता और सुधारों की गति एक साथ होने से पीड़ितों के बीच संदेह बढ़ गया है। अंत में, सरकार अभी भी अपने कार्यकाल के प्रारंभिक महीनों में है, इसलिए इसके कुछ उपायों के प्रभाव अभी तक पूरी तरह से नहीं देखे गए हैं, जबकि यह लगभग आधी आबादी की उम्मीदों और समर्थन को बनाए रखना जारी रखे है। यह एक सांस्कृतिक माहौल में असंतोष फैलने की संभावना को सीमित करता है जो अभी भी माइली की कई सरकारी नीतियों के अनुकूल है।

विरोध प्रदर्शनों की गतिशीलता अनिश्चित है, और भविष्य चुनौतियों से भरा है। एक ओर, सरकार का भाग्य मुद्रास्फीति को कम करके आर्थिक स्थिति को स्थिर करने और एक राजनीतिक और सामाजिक बहुमत बनाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है जो उसे शासन करने और इसे अधिक स्थिर वैधता प्रदान करने की अनुमति देगा। हालाँकि, मुद्रास्फीति में मात्र कमी – जो अपने आप में एक कठिन परिणाम है – सामाजिक प्रतिगमन और श्रमिकों के प्रतिकूल शक्तियों के परिणामी पुनर्गठन को स्वचालित रूप से मान्य नहीं करेगा जब तक कि विरोध में प्रमुख कर्त्ता पराजित या गंभीर रूप से कमजोर न हो जाएँ। यदि ऐसा होता है, तो हम परिवर्तन की दिशा पर चर्चा करने की स्पष्ट क्षमता के बिना अधिक असंतत, खंडित और अकार्बनिक संघर्षों के चरण में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर, सड़कों पर और संस्थानों में पीड़ित लोगों की क्षमता है कि वे सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल करें, जो उस कार्रवाई से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनावों पर सवार हो। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अर्जेंटीना के इतिहास में अन्य अवसरों की तरह, विरोध प्रदर्शन राजनीतिक अवसरों की संरचना को बदल देते हैं, जिससे नए परिदृश्य खुलते हैं। ■

सभी पत्राचार जूलियन रेबॉन को <jrebon@sociales.uba.ar> पर प्रेषित करें।

> अयोतजिनापा : दस साल की दण्डहीनता

कार्लोस डी जेसुस गोमेज–अबार्का, यूनिवर्सिडाड डी सिएन्सियास वाई आर्टेस डी चियापास, मेक्सिको, द्वारा

''अलाइव यू टुक दैम! अलाइव वी वॉन्ट दैम बैक नॉउ!'' श्रेय : जेसुस गोमेज–अबार्का, 2014

मार्च 6, 2024 को, मेक्सिको सिटी के मध्य में, मानवाधिकार कार्यकर्ता और 2014 में अयोतजिनापा से गायब हुए छात्रों के माता–पिता हिंसक तरीके से नेशनल पैलेस में घुस गए। उन्नीसवीं सदी के ऐतिहासिक दरवाजे को एक वैन द्वारा गिराने की चौंकाने वाली तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित हुईं। प्रदर्शनकारी आगंतुक पंजीकरण काउंटर तक पहुँच गए, जहाँ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेना ने आंसू गैस से जवाब दिया। यह सब तब हुआ जब राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर सुबह का सामान्य सम्मेलन कर रहे थे। महल की खिड़की पर एक साइनबोर्ड लगा था जिस पर लिखा था: ''हम सिर्फ संवाद चाहते हैं''। इसके आलोक में, हम यह आश्चर्य करते हैं कि: दुखद ''इगुआला की रात'' के दस साल बाद क्या बदल गया है?

> तथ्य और जांच

26 सितंबर की रात और 27 सितंबर, 2014 की भोर में, एक कार्यवाही ने गुएरेरो राज्य के अयोटजिनपा में ग्रामीण सामान्य विद्यालय ''इसिड्रो बर्गोस'' के छात्रों के एक समूह को निशाना बनाया। इस घटना में, छह लोग मारे गए और 43 अन्य छात्रों का अपहरण कर लिया गया। इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ असामान्य नहीं हैं, जहाँ लोकप्रिय संघर्षों और राज्य दमन का एक लंबा इतिहास रहा है। युवा छात्रों के खिलाफ आक्रामकता ग्रामीण स्कूलों के लिए नकारात्मक प्रभावों वाली सरकारी नीतियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनका संबंध किसान और छात्र विद्रोहों की ऐतिहासिक प्रतिध्वनियों के साथ–साथ मेक्सिको के समाजवादी किसान छात्रों के संघ (FECSM) की प्रतिध्वनियां है। ये घटनाएँ ऐसे क्षेत्र में हुईं जहाँ कई आर्थिक और राजनीतिक हित, कानूनी और अवैध दोनों, दांव पर लगे थे।

एनरिक पेना नीटो के प्रशासन (2012–18) के दौरान, 43 अयोटजिनपा छात्रों के ''गायब होने'' की जांच मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल (पीजीआर), जेसुस मुरिलो करम द्वारा की गई थी। 7 नवंबर, 2014 को, मुरिलो ने तथ्यों के बारे में ''ऐतिहासिक सच्चाई'' की घोषणा की। घटनाओं के उस संस्करण के अनुसार, बंदियों के एक समूह ने छात्रों की हत्या करने की बात कबूल की। छात्र नगरपालिका अध्यक्ष की पत्नी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को बाधित करने जा रहे थे, और उन्हें इगुआला, गुएरेरो से पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत ''ऐतिहासिक सच्चाई'' ने सुझाव दिया कि छात्रों को स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत करके आपराधिक समूह ''गुएरेरोस यूनिडोस'' द्वारा कोकुला लैंडफिल में जला दिया गया था।

2014 से, माता–पिता, प्रदर्शनकारियों, विश्लेषकों और मीडिया ने गवाही और सबूत, जो दर्शाते हैं कि सैन्य नेताओं को इन आपराधिक कृत्यों के बारे में जानकारी थी और उन्हें इसमें शामिल किया गया था, पेश कर इस संस्करण पर सवाल उठाए हैं।

2018 में मेक्सिको के राष्ट्रपति पद को संभालने के बाद, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर (AMLO) ने अयोतजिनपा मामले में कमीशन फॉर ट्रूथ एंड एक्सेस टू जस्टिस इन द आयोतजिनपा केस (COVAJ) बनाकर जाँच को पुनर्जीवित किया। आयोग ने तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए एक नई जाँच शुरू की, जिसमें सत्य, न्याय और इन गंभीर अपराधों की पुनरावृत्ति न होने के अधिकार की गारंटी दी गई। COVAJ की दूसरी रिपोर्ट में, ''ऐतिहासिक सत्य'' को खारिज कर दिया गया, घटनाओं की नई परिकल्पनाएँ स्थापित की गईं, और यह माना गया कि अयोतजिनपा में जो हुआ वह एक ''राज्य अपराध''

> >

था जिसमें मैक्सिकन सेना और नौसेना के विभिन्न अधिकारी और तत्व शामिल थे।

अनुमान है कि इस त्रासदी में कम से कम 434 लोग शामिल थे। तीन छात्रों के अवशेषों की पहचान कर ली गई है और अभियोजक ने 132 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लापता छात्र जीवित हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में सेना, गुरेरोस यूनिडोस, पुलिस के सदस्य और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। पिछले साल, कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिनमें पूर्व अटॉर्नी जनरल जेसुस मुरिलो करम जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, जो "ऐतिहासिक सत्य" के आविष्कार के पीछे के लोगों में से एक हैं।

> न्याय के लिए संघर्ष

2014 में, 2 अक्टूबर, 1968 को मैक्सिको सिटी में छात्रों की हत्या की स्मृति में आयोजित मार्च के दौरान, 43 अयोटजिनपा छात्रों के ठिकाने के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हालाँकि, यह स्मरणोत्सव एक सर्वसम्मत नारे में बदल गया जिसमें उन लोगों की वापसी की मांग की गई जो जीवित ''गायब'' हो गए थे। इसके चलते मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक केंद्र की सड़कें जाम हो गईं क्योंकि छात्रों, नागरिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों ने प्लाजा डे लास ट्रेस कल्चरस से जोकलो तक मार्च किया, साथ ही देश में बढ़ती हिंसा पर अपना दुख, अविश्वास और आक्रोश व्यक्त किया।

आने वाले महीनों में, मैक्सिको और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर मार्च और सभाएँ हुईं। 43 छात्रों के माता–पिता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और नागरिक न्याय की मांग करते हुए पुलिस के साथ बढ़ते दमन और टकराव के बीच तथा ''यह राज्य था!'' के नारों द्वारा निंदा करते हुए मेगा–मार्च की श्रृंखला में शामिल हुए। आधिकारिक जानकारी कम थी, लेकिन लोगों ने अपने निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए, और चल रहे दमन और सरकार के कथन को अस्वीकार करते हुए ''न तो 43 और न ही 68'' जैसे नारों के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त किया।

1 दिसंबर, 2014 के बाद मार्च में उपस्थिति में कमी के बावजूद, माता–पिता का संघर्ष कम नहीं हुआ है। उन्होंने छात्रों, नागरिक संगठनों और अन्य सामाजिक आंदोलनों से समर्थन मांगना और प्रयासों का समन्वय करना जारी रखा है। मार्च 2024 में नेशनल पैलेस में हाल ही में 43 छात्रों के माता–पिता के नेतृत्व में घुसपैठ का उद्देश्य राष्ट्रपति के साथ बातचीत को फिर से खोलना और जांच को आगे बढ़ाना था।

यह कार्रवाई ऐसे संदर्भ में हुई, जहां माता–पिता और ।डस्व् की सरकार के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, और COVAJ के शुरुआती वर्षों के दौरान स्पष्टीकरण के लिए प्रयास करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोग अब इस कार्य का हिस्सा नहीं हैं। एक ओर, 43 छात्रों के माता–पिता मामले को स्पष्ट करने के लिए सरकार की इच्छा की कमी की ओर इशारा करते हुए, इसमें शामिल सैन्य कर्मियों की सुरक्षा की निंदा करते हैं, और सैन्य जासूसी दस्तावेजों को जारी करने की मांग करते हैं जो जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दूसरी ओर, AMLO के कार्यकाल के अंतिम चरण में, सरकार सवाल उठाने वाले लोगों को ''रूढ़िवादी'' करार करते हुए उन लोगों की मांगों को बदनाम करना जारी रखे है। साथ ही छात्रों के माता–पिता को उनके वकीलों की गैर–मौजूदगी में बैठक की पेशकश की जाती है।

सेंट्रो प्रो के निदेशक सैंटियागो एगुइरे के लिए, यह मामला इस नई सरकार के साथ मेक्सिको में न्याय वितरण में बदलाव का एक उदाहरण हो सकता था। हालाँकि, यह इस प्रशासन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक बन गया है, जो अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की कमियों के सामने नई सैन्य शक्ति और निष्क्रियता को उजागर करता है। इस बीच, 43 छात्रों के लिए न्याय एक ऐसा कर्ज लगता है जो लंबित रहेगा और संभवतः अगले प्रशासन को विरासत में मिलेगा। केवल "अर्ध–सत्य" के साथ, 43 छात्रों के माता–पिता सत्य और न्याय तक पहुँचने के लिए अपने अथक प्रयास जारी रखे हैं। ■

सभी पत्राचार कार्लोस डी जेसुस गोमेज–अबार्का को
<jesus.gomezabarca@gmail.com> पर प्रेषित करें।

> अधिशेष और विस्थापन
शरणार्थी और प्रवासी

नादिया बौ अली और **रे ब्रासियर,** BICAR (बेरूत इंस्टीट्यूट फॉर क्रिटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च) और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत, लेबनान द्वारा

एआई की मदद से अर्बु द्वारा बनाई कलाकृति

यह लेख बेरोजगार जनसँख्या की विशेषता के रूप में ''अतिरिक्त आबादी'' की धारणा पर विस्तार से चर्चा करने हेतु लिखा गया है। इसमें औपचारिक वेतन संबंध से बाहर रखे गए अनिश्चित श्रम में लगे लोग और पूंजीवादी गरीबी के कारण केवल सामान्य श्रेणियों (शरणार्थी, प्रवासी) के अंतर्गत दिखाई देने वाले लोग शामिल हैं। शरणार्थियों और प्रवासियों की सामान्य श्रेणियां अमूर्त वर्णनात्मक श्रेणियां हैं जिनके लिए वैश्विक पूंजीवाद की विभेदक गतिशीलता के भीतर ''अतिरिक्त आबादी'' के ठोस विश्लेषणात्मक विवरण की आवश्यकता होती है।

पूंजीवाद अपने अपने गठन के मूल रूप में असमान हैय आदिम संचय उद्गम है जब तक वह अधिशेष मूल्य के उत्पादन के साथ लगातार पुनरुत्पादित होता है। यह कहने के साथ, औपनिवेशिक आवेग पूंजीवाद के लिए बुनियादी है, जो सामाजिक संबंध और पारिस्थितिक संबंध दोनों है। एक ओर, ''पूंजीवादी युग'' की विशेषता मानव जीवन और प्रकृति की व्ययशीलता है। दूसरी ओर, ''जनसांख्यिकीय बेदखली'' की श्रेणी बताती है कि यह असमानता किस तरह से विशेष रूप और सार्वभौमिक रूप से, उन लोगों के समूह द्वारा अनुभव की जाती है, जिनका औपचारिक वेतन संबंध से बहिष्कार अधिशेष मूल्य के उत्पादन के लिए बुनियादी है।

> सर्वहाराकरण के रूप में अधिशेष जनसंख्या

एक बड़ी गलतफहमी को शुरू से ही संबोधित करने की जरूरत है। पारिभाषिक तौर पर अधिशेष जनसंख्या विस्थापित नहीं होतीः उन्हें किसी दिए गए देश या राष्ट्र राज्य की सीमाओं के बाहर से आने वाली आबादी होने की जरूरत नहीं है। वे केवल असमान विकास का परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे प्रभाव हैं, जो पूंजीवादी संचय की प्रक्रिया में एक कारण बन जाते हैं। मार्क्स ने अपरिष्कृत माल्थुसियन तर्क की तीखी आलोचना की है जो अति जनसंख्या को प्रकृति के नियम के रूप में देखता है और इस तरह दूसरों के अस्तित्व के लिए कुछ आबादी के खात्मे को उचित ठहराता है। आज, हम उन लोगों के तर्क में माल्थुसियनवाद के विस्फोटों को सुनते हैं जो अधिशेष आबादी के प्रवाह के खिलाफ राष्ट्रीय सीमाओं को प्रतिरक्षित करना चाहते हैं और जो बलिदान योग्य आबादी को नष्ट करना या स्थानांतरित करना चाहते हैं। चल रहे पर्यावरणीय पतन ने अधिशेष मानवता के प्रश्न में जटिलताओं की परतें जोड़ दी हैं और इसे पूंजीवादी पारिस्थितिकी से निपटने वाले बाद के खंड में संबोधित किया जाएगा। मार्क्स के विश्लेषण में, यह आपूर्ति और मांग का माल्थुसियन तर्क नहीं है जो अधिशेष आबादी उत्पन्न करता है, बल्कि मूल्य निर्धारण का तर्क है, या अधिशेष मूल्य को अधिकतम करने का तर्क हैः

>>

''यह पूंजीवादी संचय ही है जो लगातार उत्पादन करता है, और वास्तव में अपनी स्वयं की ऊर्जा और सीमा के साथ सीधे संबंध में, एक अपेक्षाकृत अनावश्यक कार्यशील आबादी का उत्पादन करता है, यानी एक ऐसी आबादी जो पूंजी की अपनी स्वयं की मूल्य निर्धारण के लिए औसत आवश्यकताओं के लिए अनावश्यक है, और इसलिए एक अधिशेष आबादी है [...] यह उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली के लिए विशिष्ट जनसंख्या का एक नियम हैय और वास्तव में प्रत्येक ऐतिहासिक उत्पादन के तरीके में जनसंख्या के अपने विशेष नियम हैं, जो उस विशेष क्षेत्र के भीतर ऐतिहासिक रूप से मान्य हैं।'' (कैपिटल)

पूंजीवाद के लिए एक विशिष्ट जनसंख्या का नियम हैः उत्पादक शक्तियों के विकास के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से सापेक्ष अधिशेष आबादी विकसित होती है । ''श्रम की आपूर्ति और मांग का नियम'' सामान्य मजदूरी (श्रमिक वर्ग, यानी श्रम शक्ति) के कुल सामाजिक पूंजी के अनुपात को नियंत्रित करता हैः ''श्रम की उत्पादकता जितनी अधिक होगी, रोजगार के साधनों पर श्रमिकों का दबाव उतना ही अधिक होगा, इसलिए उनके स्वयं के अस्तित्व के लिए स्थिति उतनी ही अनिश्चित होगी'' (*पूर्वोक्त,* जोर दिया गया)। इसी तरह, ''मशीनरी एक अधिशेष कार्यशील आबादी का उत्पादन करती है'' (*पूर्वोक्त*)। इस संदर्भ में, यह मजदूरी संबंध ही है जो श्रमिक वर्ग के विपन्नता और सर्वहाराकरण को पैदा करता है।

इसका तात्पर्य यह होगा कि सापेक्ष अधिशेष आबादी मजदूरी संबंध के माध्यम से पूंजीवाद की प्रवृत्ति के रूप में उत्पादक शक्तियों के विकास का एक साथ कारण और प्रभाव बन जाती है। यद्यपि पूंजीवाद उत्पादन की शक्तियों (मशीनीकरण, स्वचालन, इत्यादि) को विकसित करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह श्रम शक्ति को भी विकसित करता हैय बल्कि, इसका उल्टा प्रतीत होता हैः जैसे–जैसे उत्पादक शक्तियाँ विकसित होती हैं, श्रम–शक्ति के पुनरुत्पादन की लागत कम होती जाती है और मजदूरी घटती जाती है। उत्पादक शक्तियों के विकास को प्रेरित करने वाली चीज शोषण की दर (श्रम शक्ति से अधिशेष मूल्य के निष्कर्षण की दर) को बढ़ाने की मजबूरी है और इस तरह से अधिशेष और आवश्यक श्रम के अनुपात को बढ़ाना है, न केवल श्रम प्रक्रिया के भीतर बल्कि मजदूरी मजदूरों की पूरी आबादी में। जैसे–जैसे कम से कम श्रम से अधिक से अधिक अधिशेष मूल्य निकाला जाता है, मजदूरों की बढ़ती संख्या मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए अनावश्यक हो जाती है।

पूंजी बेरोजगारी पैदा करती है, जो श्रम प्रक्रिया में इसके वास्तविक अधीनता की एक शर्त है (यानी शोषण की दर को अधिकतम करने के लिए इसके पुनर्गठन की)। इस प्रकार, बेरोजगार, अतिरिक्त और अधिशेष, शोषण की वर्तमान प्रणाली के लिए बुनियादी हैं। जहाँ जबकि पूंजी श्रम शक्ति के शोषण के माध्यम से खुद को पुनरुत्पादित करती है, और श्रम शक्ति खुद को पूंजी द्वारा शोषित होने की अनुमति देकर स्वयं को पुनरुत्पादित करती है, पूंजी के रूप में मूल्य का विस्तार श्रम शक्ति के मूल्य के विस्तार को शामिल नहीं करता हैय इसके विपरीत, पूंजी का विस्तारशील आत्म–मूल्यांकन श्रम के मूल्यह्रास को शामिल करता है, जिसका अर्थ है, अधिशेष से आवश्यक श्रम का, बेरोजगार से नियोजित का लगातार बढ़ता अनुपात। इसका मतलब यह है कि पहले उत्पादन के साधनों से श्रम को अलग करने के बाद, पूंजी फिर उत्पादन प्रक्रिया से श्रमिकों के लगातार बढ़ते हिस्से को अलग करने के लिए आगे बढ़ती है जिसके माध्यम से उन्हें खुद को पुनरुत्पादित करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह द्वितीयक सहायक पृथक्करण (बेरोजगार से नियोजित का) प्रारंभिक प्राथमिक पृथक्करण (उत्पादकों से उत्पादन के साधनों का) का अनुसरण करता है। फिर मुद्दा यह है कि अधिशेष को आवश्यक श्रम से, या बेरोजगार को नियोजित से कैसे जोड़ा जाएः

''[...] सर्वहारा वर्ग को पुनरुत्पादन के साधनों से उसके अलगाव और पूंजी का पुनरुत्पादन करके खुद को पुनरुत्पादित करने की उसकी मजबूरी से परिभाषित किया जाता है। सर्वहारा वर्ग (उसकी श्रम–शक्ति का मूल्य) का पुनरुत्पादन, मूल्य के नियम के 'सामान्य' कामकाज के माध्यम से पूंजी के पुनरुत्पादन के अनुरूप रखा जाता हैः यदि मजदूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो पूंजी कम श्रमिकों को काम पर रखेगी, इस प्रकार एक आरक्षित सेना का निर्माण होगा जो मजदूरी पर नीचे की ओर दबाव डालेगी। यहाँ मुद्दा यह है कि जब तक नियोजित और बेरोजगार एक साथ नहीं आते, तब तक मजदूरी हमेशा पूंजी संचय की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। (बी.आर. हैनसेन)

इस प्रकार, ''बेरोजगारों की आरक्षित सेना'' और बेरोजगार ''लुम्पेन सर्वहारा वर्ग'' के रूप में अधिशेष आबादी, एक साथ पूंजीवादी केंद्र के लिए आंतरिक हैं, यानी दुनिया के उन क्षेत्रों के लिए आंतरिक हैं जो पूरी तरह से पूंजी द्वारा एकीकृत या समाहित हो चुके हैं, और इस केंद्र के परिधीय हैं, यानी उन क्षेत्रों में मौजूद हैं जो अभी तक आंशिक रूप से या औपचारिक रूप से पूंजी द्वारा समाहित हैं (तीसरी दुनिया या वैश्विक दक्षिण)। इसका मतलब यह है कि पूंजी के पुनरुत्पादन में और उसके माध्यम से उत्पन्न अधिशेष मानवता केंद्र और परिधि दोनों पर कब्जा करती हैः यह केंद्र और हाशिये दोनों पर मौजूद है।

> दृश्यमान जनसमूह और अदृश्य श्रम

अतिरिक्त आबादी लोकप्रिय जनसमूह के रूप में दिखाई देती है। पेरिस से लेकर दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया तक, हाल के दशकों में हमने झुग्गी–झोपड़ियों और शिविरों में रहने वालों द्वारा अचानक बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों को देखा है, और जिसे शायद शरणार्थी विद्रोह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह आमतौर पर अदृश्य संरचनात्मक गतिशीलता की दृश्यमान अभिव्यक्ति हैं। लेकिन वे इसे वस्तुनिष्ठ संरचना की व्यक्तिपरक अभिव्यक्तियों के रूप में प्रकट करते हैंः वे अदृश्य के दृश्यमान होने के व्यक्तिपरक क्षण हैं।

संरचनात्मक विश्लेषण को अदृश्य, वस्तुनिष्ठ संरचना की इस दृश्यमान, व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति के लिए स्थितियों को उजागर करना चाहिए। इस तरह के विश्लेषण में पहला कदम विस्थापित और अधिशेष आबादी के बीच अंतर करना है। यद्यपि लोगों की भीड़ राष्ट्रीय सीमाओं पर शरणार्थियों और प्रवासियों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वे अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें अधिशेष आबादी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस आम गलत धारणा के कारण वैचारिक हो सकते हैंः निस्संदेह अधिशेष आबादी को मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से संबोधित करना आसान है जो विकसित देशों में विदेशियों और प्रवासियों को शरण के अधिकार प्रदान करने और एकीकृत करने का प्रयास करता है। हालांकि, मैं तर्क दूंगी कि यह दृष्टिकोण वैचारिक या व्यावहारिक रूप से प्रश्न को संतोषजनक ढंग से संबोधित करने में विफल रहता है।

जरूरी नहीं है कि अतिरिक्त आबादी विस्थापित या प्रवासी आबादी हो। जैसा कि आरोन बेननव बताते हैं, 1950 के दशक से, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LIC) में शहरी बेरोजगारों में से अधिकांश वास्तव में शहर में जन्मे हैंः ''1950 के दशक की शुरुआत में, LIC में शहरी जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा पहले से ही शहरी क्षेत्रों में पैदा हुए लोगों के कारण था, न कि उनके लिए पलायन करने के कारण।'' बेननव का तर्क है कि ''1980 के बाद नगरीकरण की धीमी दर के बावजूद, शहरी श्रम शक्ति कम आय वाले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है।'' शहरी श्रमिक बस कहीं

> >

से नहीं आते हैं या कहीं और से नहीं आ आते हैंय वे सर्वहाराकरण की प्रक्रियाओं के लक्षण के रूप में उभरते हैं जो देर से पूंजीवाद के विकास के मद्देनजर विकसित हुए हैं। जबकि नगरीकरण की दरों में मंदी है, शहरी गरीबों की जनसांख्यिकीय वृद्धि हुई है जिन्होंने अब बच्चों की पीढ़ियों को जन्म दिया है, जो अपने माता–पिता की तरह अनौपचारिक श्रम के सर्किट में रहते हैं। सर्वहाराकरण को सरलता से ''जीवित रहने के लिए अपने श्रम को बेचने पर निर्भर रहने वाली आबादी के हिस्से में वृद्धि'' के रूप में समझा जा सकता है। सर्वहाराकरण में यह वृद्धि ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण नहीं है, जो कि विकास अध्ययनों द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली एक गलत धारणा है। इसके बजाय, LICs दो मुख्य कारकों के कारण श्रम की कम मांग प्रदर्शित करते हैं: 1) आर्थिक असमानताओं का उच्च स्तर जो अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक आबादी द्वारा मांगे जाने वाले श्रम–गहन वस्तुओं के बजाय मुख्य रूप से अभिजात वर्ग द्वारा मांगे जाने वाले पूंजी–गहन वस्तुओं के उत्पादन की ओर ले जाता है; और 2) औद्योगिक देशों से आयातित तकनीकी प्रगति और स्वचालन। इस प्रकार, LICs में अर्थव्यवस्थाएँ श्रम–गहन की तुलना में अधिक पूंजी–गहन हैं।

पिछले दशक में अर्थशास्त्रियों (विशेष रूप से यू.एस.–आधारित) द्वारा रोजगार वृद्धि और 1990 के दशक के बाद वैश्विक श्रम बाजार में बदलाव को समायोजित करने की आवश्यकता के बारे में किए गए दावों के बावजूद, LICs और अन्य देशों से श्रम बलों को समायोजित करने के लिए बहुत कम काम किया गया है। एक अग्रणी विश्व शक्ति के रूप में, अमेरिका अपने भीतर और दुनिया के अन्य हिस्सों में उभर रही बढ़ती अलगाववादी नीतियों को रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकता था। 1990 के दशक में NAFTA की बहसों में और साथ ही इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में अवैध अप्रवासियों से निपटने के तरीके पर बहस में वैश्विक उत्तर की विश्व अर्थव्यवस्था के लाभों को पुनर्वितरित करने में विफलता की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। आज हालात और भी बदतर हैं क्योंकि हम सीमाओं और शिविरों में अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिए जाने, सीमा की दीवारों का निर्माण आदि देख रहे हैं।

> प्रवासी श्रमिक सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का सामना करते हुए अशांति और निर्वासन के चक्र में फंसे हुए हैं।

विशेष रूप से MENA क्षेत्र में कहानी काफी हद तक शरणार्थियों और प्रवासी आबादी के प्रवाह से निर्धारित होती है। उन्नीसवीं सदी के अंत में ओटोमन साम्राज्य के पतन और उसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के यूरोपीय उपनिवेशीकरण के बाद से, जो ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य विभाजित हो गया, उपनिवेशीकरण के मद्देनजर राष्ट्र–राज्यों का उदय काफी हद तक औपनिवेशिक हितों के अनुसार क्षेत्र के क्षेत्रीय विभाजन द्वारा चिह्नित किया गया है। 1948 में यूरोप से यहूदी प्रवासियों की आमद के परिणामस्वरूप फिलिस्तीन पर ऐतिहासिक कब्जे ने पड़ोसी देशों में 750,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शरणार्थी बना दिया। लेबनान में, 260,000 और 280,000 के बीच फिलिस्तीनी शरणार्थी 12 शिविरों और 42 सभाओं में वितरित किए गए हैं। UNRWA के अनुसार, लेबनान की वर्तमान जनसंख्या 6.8 मिलियन है और लगभग 250,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। वे लेबनानी कार्यबल का लगभग 5.6% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से 50% गैर–लेबनानी हैं। लेबनान में फिलिस्तीनियों को औपचारिक श्रम बाजार से बाहर रखा गया है और उन्हें औपचारिक वेतन, संपत्ति के स्वामित्व और अन्य बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है। अन्य शरणार्थियों की तरह, लेबनानी रोजगार प्रतिबंध फिलिस्तीनियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कानून जैसे उदार व्यवसायों तक पहुँचने से रोकते हैं, जिससे फिलिस्तीनियों को अल्पकालिक, कम वेतन वाली नौकरियों की विशेषता वाले एक अनिश्चित अनौपचारिक श्रम बाजार में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लगभग आधे नियोजित फिलिस्तीनी निर्माण और वाणिज्य या संबंधित गतिविधियों (थोक और खुदरा व्यापार, मोटर वाहनों की मरम्मत, घरेलू सामानों की मरम्मत, आदि) में काम करते हैं, जहाँ अनौपचारिकता का स्तर औसत कार्य घंटों से बहुत अधिक है, और अधिकांश लेबनानी न्यूनतम मजदूरी से कम कमाते हैं।

फिलिस्तीनियों के अलावा, 1950 के दशक से सीरियाई लोगों ने लेबनान में प्रवासी श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा बनाया है। 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद से यह हिस्सा नाटकीय रूप से बढ़ गया है। वर्तमान में लेबनान में 1.5 मिलियन सीरियाई शरणार्थी हैं। फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर, वे लेबनान की पूरी आबादी का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं। *द इनविजिबल केज* में, जॉन चाल्क्राफ्ट दिखाते हैं कि कैसे जबरन प्रवास और जबरन श्रम आपस में जुड़े हुए हैं। वे जबरन श्रम पर आधारित श्रम बाजार की गतिशीलता और लंबे समय तक अशांति और निर्वासन के निरंतर चक्र में मौजूद प्रवासी मजदूरों के अंतहीन रोटेशन का परिणाम हैं।

2024 में, यह अदृश्य श्रम पिंजरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है: 2019 के लेबनानी वित्तीय पतन और संसाधनों और श्रम अवसरों दोनों की बढ़ती कमी के साथ, सीरियाई मजदूरों को पूर्वाग्रह, जेनोफोबिया और उत्पीड़नकारी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सीरियाई मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि ने देश के बिगड़ते आर्थिक संकट के मद्देनजर लेबनानी श्रमिक वर्ग की दुर्दशा के साथ–साथ सीरियाई विरोधी भावना को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, लेबनान की श्रम शक्ति भागीदारी दर 43.4% है, जो दर्शाता है कि कामकाजी उम्र की आधी से भी कम आबादी या तो वेतन या लाभ के लिए काम कर रही है, या रोजगार की तलाश कर रही है।

राष्ट्रीयता और नस्ल के विभाजनों के पार श्रम को संगठन की ओर ले जाने के बजाय, सर्वहाराकरण में गरीबी और अनिश्चितता शामिल है, जो बदले में श्रमिक वर्ग के विखंडन की ओर ले जाती है। लेबनान में, श्रमिक वर्ग लेबनानी, सीरियाई, अफ्रीकी और एशियाई मजदूरों से बना है जो देश में घरेलू और देखभाल के काम से लेकर अन्य प्रकार के अनिश्चित श्रम तक अधिकांश पुनरुत्पादन श्रम करते हैं। लेबनान में लगभग 90% सीरियाई शरणार्थी अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं। इनमें से, 2020 के कोविड–19 महामारी की शुरुआत के बाद से गरीबी दर में 56% की वृद्धि हुई है। अनौपचारिक अकुशल श्रम बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शरणार्थियों को लंबे समय तक काम करने, कम वेतन और कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा या भुगतान किए गए अस्वास्थ्य अवकाश की कमी जैसी अपर्याप्त कार्य स्थितियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही है। महिला सीरियाई श्रमिकों को अपर्याप्त परिवहन, बाल देखभाल सहायता की कमी और सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को भी सहना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ शरणार्थियों को गिरफ्तारी, जबरन प्रत्यावर्तन और निर्वासन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं।

इस बीच, सीरियाई शरणार्थी जो औपचारिक रूप से काम करना चुनते हैं, उन्हें लेबनानी नियोक्ता द्वारा प्रायोजन या पट्टे के समझौते के तहत प्रवासियों के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। फिलिस्तीनियों की तरह, सीरियाई लोगों के लिए भी औपचारिक रोजगार आम तौर पर तीन क्षेत्रों तक सीमित है: पर्यावरण, कृषि और निर्माण, जिसके लिए प्रति वर्ष 200 डॉलर की लागत वाले निवास परमिट की आवश्यकता होती है। शरणार्थी कुछ अन्य सीमित क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार की तलाश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कई वित्तीय और नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है, खासकर उनके निवास परमिट को नवीनीकृत करने में: 2020 में,

>>

लेबनान में पंजीकृत सीरियाई शरणार्थियों (विशेष रूप से 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के) में से लगभग 70% के पास परमिट नहीं थे, जिससे न केवल उनकी जीविका कमाने की क्षमता बल्कि उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता भी गंभीर रूप से सीमित हो गई थी ।

> अधिशेष आबादी का प्रबंधन पूंजी के पुनरुत्पादन का अभिन्न अंग है।

आर्थिक प्रवासियों को शरणार्थी श्रम शक्ति से अलग करना महत्वपूर्ण है। एलिजाबेथ लॉन्गनेस और पॉल टैबर के अनुसार, लेबनान के कार्यबल में लगभग 15% प्रवासी श्रमिक और 35% सीरियाई श्रमिक शामिल हैं। हमने ऊपर अधिशेष आबादी को विस्थापित या शरणार्थी आबादी से अलग करने की आवश्यकता पर बल दिया। फिर भी उनकी सभी दुर्दशाएँ लेबनान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित हैं, जहाँ सीरियाई और फिलिस्तीनी आबादी में प्रवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। ये वर्ग लेबनान की कामकाजी आबादी के भीतर दोहरे रूप से वंचित हैं: वे पूंजी द्वारा आवश्यक माने जाने वाले श्रम के मुकाबले अधिशेष का गठन करते हैं, जबकि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एकीकृत श्रम आबादी (लेबनानी और अन्य राष्ट्रीयताओं से बनी) के मुकाबले विस्थापित भी होते हैं। उनकी स्थिति एक ओर आवश्यक और अधिशेष श्रम के अधिरोपण को उजागर करती है, और दूसरी ओर मजदूरों की आबादी के भीतर एकीकृत और विस्थापित श्रम को उजागर करती है।

कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जो इस अंतर को ध्यान में रखने में विफल रहता है, वह दोहरा जोखिम उठाता है। एक ओर, यह हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि शरणार्थी एक ''अपूर्ण प्रवास'' का मामला बनाते हैं, एक समस्या जिसे या तो घर वापस आकर या नागरिकता की औपचारिक स्थिति तक पहुँचकर कम किया जा सकता है। बदले में, इस धारणा का अर्थ है कि समाधान अधिकारों और सामाजिक मान्यता के स्तर पर विचार किए जाते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ पहली समस्या, जाहिर है, यह है कि यह पूंजीवादी सामाजिक गतिशीलता के गहरे और व्यापक प्रभाव को अस्पष्ट करता है – जो विस्थापित और गैर–विस्थापित दोनों प्रकार के श्रमिक वर्ग की आबादी को समान रूप से प्रभावित करता है – और समाधान और प्रतिक्रियाओं को इस तरह से तैयार करता है कि श्रमिक वर्ग के क्षेत्रों को और दूर कर देता है, जो वास्तव में समान राजनीतिक परिस्थितियों को साझा करते हैं। दूसरी ओर, जब कोई प्रवासी और शरणार्थी श्रम शक्ति के बीच अंतर को ध्यान में नहीं रखता है, तो वह संकट परिदृश्य के प्रबंधन के लिए हाथ में मौजूद राजनीतिक चुनौतियों को कम करने का अतिरिक्त जोखिम भी उठाता है, जैसा कि कई गैर–सरकारी संगठन करते हैं जब वे सामाजिक और प्राकृतिक त्रासदियों के जवाब में सहायता प्रदान करना चाहते हैं।

इस अंतर को पहचानने में विफल होने से जो खो जाता है वह यह है कि अधिशेष आबादी का प्रबंधन एक बाहरी गतिविधि नहीं है जो आबादी की दुर्दशा के कारणों का मुकाबला कर रही है: यह वास्तव में एक ऐसी गतिविधि है जो पूंजी के पुनरुत्पादन का अभिन्न अंग है। यह प्रबंधन न केवल श्रम की आरक्षित सेना द्वारा कार्यबल पर लगाए गए प्रतिस्पर्धी बल के माध्यम से श्रम की लागत को कम करने की अनुमति देता है, बल्कि यह खुद को सामाजिक पुनरुत्पादन के टूटे हुए सर्किट में भी सम्मिलित करता है, जिससे पूंजीवादी पुनरुत्पादन के व्यापक सर्किट को बरकरार रहने की सहूलियत मिलती है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक वर्ग के क्षेत्रों के बीच विभाजन को बढ़ाने के अलावा, इस तरह का दृष्टिकोण अंततः शरणार्थियों को संकट प्रबंधन की प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिसका उपयोग बेरोजगारों, अल्प–रोजगार वाले और गरीब श्रमिक वर्ग को अधिक व्यापक रूप से प्रबंधित करने के लिए नई सामाजिक प्रौद्योगिकियों के आधार के रूप में किया जा सकता है।

शरणार्थी श्रम की विशेष गुणवत्ता को पहचानना – इसे एक ऐसे लक्षण के रूप में समझना जो सामाजिक विघटन और आर्थिक एकीकरण के बीच अंतर्निहित संबंध को प्रकट करता है, जो सामाजिक पुनरुत्पादन के चक्र को अवरुद्ध करने के बजाय, वास्तव में इसे संभव बनाता है – इस सवाल को नए सिरे से उठाने के लिए जगह खोलना है कि आपदा पर पलने वाली सामाजिक व्यवस्था के लिए संरचनात्मक प्रतिक्रिया क्या होगी। ■

सभी पत्राचार नादिया बौ अली को <nadiabouali@gmail.com> एवं रे ब्रासियर को <ray.brassier@gmail.com> पर प्रेषित करें।

यह लेख अल्मेडा संस्थान के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया गया है।

> विनियोजन या उपयोग?

श्रम संघर्षों का पारिस्थितिक आयाम

साइमन शॉप, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, स्विटजरलैंड द्वारा

श्रेय : रिकार्डो गोमेज ऐंजल, 2017.

वर्ष 2022 की शरद ऋतु में कई हजार स्विस निर्माण कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। क्षेत्रीय नियोक्ता संघ ने अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटों को बढ़ाकर 58 करने की मांग की थी, जिसका एक बहुत ही अजीबोगरीब कारण थाः जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में, प्रतिकूल मौसम के कारण वैश्विक स्तर पर 45 प्रतिशत निर्माण परियोजनाओं में देरी होती है; लेकिन जलवायु परिवर्तन से ऐसी देरी का कारण बनने वाली मौसम स्थितियों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान श्रम उत्पादकता में कमी से जुड़ा है। यह निर्माण क्षेत्र को हीट वेव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बनाता है। साथ ही, निर्माण, ग्रीनहाउस गैसों का एक प्रमुख प्रदूषक और उत्पादक हैः अकेले सीमेंट का उत्पादन वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का लगभग 8% उत्पादन करता है।

> उत्पादन में एक घटक के रूप में प्रकृति का वर्चस्व

मेरी हाल ही की पुस्तक (जर्मन में प्रकाशित), *मेटाबोलिक पॉलिटिक्स –लेबर, नेचर एंड द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट,* में मैंने इस की जांच की कि यह और अन्य श्रम संघर्ष हमें पूंजीवादी श्रम प्रक्रिया और पारिस्थितिक संकट के बीच संबंधों के बारे में क्या सिखा सकते हैं। मुख्यधारा के पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच एक आश्चर्यजनक सहमति है कि पर्यावरण >>

विनाश का मुख्य कारण एक ऐसा संबंध है जिसमें प्रकृति को बिना भुगतान के "विनियोजित" किया जाता है, जिससे इसके अति प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। यह निश्चित रूप से मामला है, फिर भी प्रकृति के विनियोग की अवधारणा का एक विश्लेषणात्मक दोष स्पष्ट है कि यह प्रकृति की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करता है जो कच्चे माल के एक विशाल भंडार के रूप में है जिसका माल केवल एकत्र करने के लिए है, या जिसकी "पारिस्थितिकतंत्र सेवाएं" अपने आप उत्पादन में प्रवाहित होती हैं। ऐसी छवि का वास्तविकता से कोई लेना–देना नहीं है। प्रकृति एक संसाधन के रूप में मौजूद नहीं है: "प्रकृति को उपयोग करने योग्य बनाने" के लिए काम का निवेश किया जाना चाहिए। विनियोग की अवधारणा केवल उस गतिविधि का वर्णन करती है जिसके माध्यम से प्रकृति के पहलू निजी संपत्ति बन जाते हैं: यह अपने आप में कुछ भी ठोस शुरू नहीं करता हैय यह एक अमूर्तता है। बल्कि, यह मानव श्रम है जो प्रकृति को उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बाध्य करता है। उदाहरण के लिए, नदी केवल जल, ऊर्जा और भोजन का स्रोत ही नहीं है, बल्कि हमेशा एक जोखिम के रूप में भी मौजूद रहती है: यह खेतों और बस्तियों में बाढ़ ला सकती है या यातायात मार्गों को अवरुद्ध कर सकती है। इस कारण से, प्रकृति के उपयोग के लिए हमेशा नियंत्रण के एक पहलू की आवश्यकता होती है: नदी को चौनल किया जाना चाहिए, जानवरों को पालतू बनाया जाना चाहिए, खरपतवार और कीटों को खत्म किया जाना चाहिए, इत्यादि। इसलिए उपयोग का मतलब अनिवार्य रूप से प्रकृति की स्वायत्तता पर प्रभुत्व है।

> प्रकृति पर नियंत्रण कभी भी पूर्ण नहीं होता

हालाँकि, नियंत्रण का कोई भी प्रयास इस स्वायत्तता को स्थायी रूप से दबा नहीं सकता। इसके बजाय, नदी समय के साथ चौनल को नष्ट कर देगी, जानवर बीमार पड़ेंगे, और खरपतवार बार–बार वापस उगेगी। नियंत्रण का काम कभी नहीं रुकता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग में हमेशा तर्कसंगतता का तत्व शामिल होना चाहिए: अधिक उपज देने वाले पौधे और पशु प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं, प्राकृतिक चयापचय को तेज करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, जीवों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। फिर भी, समय के साथ, इस तरह के उपयोग से विरोधाभासी परिणाम सामने आते हैं, क्योंकि यह उन पदार्थों को कमजोर करता है जिनकी उपयोगिता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। यह परिणाम तब आम तौर पर उपयोग करने के आगे के प्रयासों से मिलता है। डस्ट बाउल का मामला प्रतिमानात्मक है। बीसवीं सदी की शुरुआत में, यूरोपीय बसने वालों ने अमेरिकी मिडवेस्ट के मैदानों पर जुताई की थी, जिससे बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव और रेत के तूफान आए। उत्पादकता बनाए रखने के लिए, कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों और मशीनीकरण के साथ कृषि को तेज किया गयाय लेकिन इसके परिणामस्वरूप उपजाऊ भूमि का और अधिक नुकसान हुआ।

> मानव श्रम: एक और प्राकृतिक संसाधन

प्रकृति के उपयोग और श्रम के उपयोग के बीच स्पष्ट समानताएं हैं। प्रकृति के अन्य भागों की तरह, मनुष्य श्रमिक के रूप में पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें लगातार इस तरह से ढाला जाना चाहिए। लोगों को काम करने में सक्षम होने से पहले, उन्हें पहले वर्षों तक शिक्षित किया जाना चाहिए, यानी उन्हें सामाजिक परंपराओं का पालन करना चाहिए जो श्रम के विभाजन के लिए बुनियादी शर्तें हैं। इसके अलावा, श्रमिकों को रोजगार योग्य होने के लिए एक निश्चित मात्रा में सामान्य शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब वे थक जाते हैं, तो लोगों को देखभाल और स्नेह की आवश्यकता होती है, और जब वे बीमार पड़ते हैं, तो उनकी श्रम शक्ति को चिकित्सा देखभाल के माध्यम से बहाल किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर ही, मानव शरीर को युक्तिसंगत और नियंत्रण के माध्यम से उपयोगी बनाया जाता है।

प्रकृति के उपयोग और श्रम के उपयोग के बीच का संबंध सादृश्य तक सीमित नहीं है। बल्कि, दोनों अनिवार्य रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रकृति को उपयोगी बनाने से मानव श्रम का गहन उपयोग संभव होता है, जो बदले में प्रकृति के अधिक गहन उपयोग को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, दास प्रथा और बागान अर्थव्यवस्था परस्पर एक दूसरे के पूरक थे: संयोजन द्वारा उत्पादित कपास का अधिशेष, जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग के साथ, कारखाना व्यवस्था का भौतिक आधार बन गया। प्रकृति के अन्य खंडों के उपयोग का एक संयोजन हुआ, जिस पर नई श्रम क्षमता लागू की गई। फिर भी उपयोग की विरोधाभासी विनाशकारीता हमेशा मंडराती रही।

> सभी श्रम राजनीति अंततः पर्यावरण राजनीति है

निर्माण उद्योग इसका एक प्रमुख उदाहरण है। 1892 में फ्रांसिस हेनेबिक ने प्रबलित कंक्रीट का पेटेंट कराया, जिससे उन्हें दशकों तक पूरे यूरोप में कंक्रीट की इमारतों के निर्माण पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। प्रबलित कंक्रीट ने निर्माण कंपनियों को श्रम लागत में कटौती करने की छूट दी, क्योंकि इसने कुशल ईंट बनाने वाले के पारंपरिक शिल्प व्यवसाय को काफी हद तक मिटा दिया। दीवारें अब केवल सांचों में ढाली जाती थीं। इसके अलावा, अब महंगे पत्थर के बजाय रेत को मूल सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था – कंक्रीट का उत्पादन मुख्य कारण है कि आज रेत पृथ्वी पर सबसे व्यापक रूप से निकाले जाने वाला संसाधन हैं। चूंकि निर्माण के लिए केवल नदियों और झीलों से रेत का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसके स्रोत और निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र का भारी क्षरण होता है। इसके अलावा, निर्माण CO_2 उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो बदले में उद्योग की उत्पादकता को कमजोर करता है।

यदि श्रम, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया, हमेशा प्रकृति का परिवर्तन है, तो उत्पादन की सभी राजनीति भी पर्यावरणीय राजनीति है– या "मेटाबोलिक राजनीति"। इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिकी संकट की जड़ों और उससे बाहर निकलने के संभावित तरीकों को समझने के लिए, हमें काम के मुद्दों पर अधिक जोर देने की जरूरत हैय और विशेष रूप से इस सवाल पर कि पूंजीवादी श्रम प्रक्रिया में काम और प्रकृति दोनों के विनाशकारी उपयोग को कैसे दूर किया जाए। इस अर्थ में, काम की तीव्रता से होने वाली व्यापक पीड़ा का एक कम खोजा गया पारिस्थितिक आयाम है, जो परिवर्तनकारी मेटाबोलिक राजनीति के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। ■

सभी पत्राचार साइमन शॉप को <simon.schaupp@unibas.ch>
ट्विटर : @simschaupp पर प्रेषित करें।

> मध्य पूर्व का डिजिटल दोहरा बंधन

मोहम्मद जायनी, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, कतर, और **जो एफ. खलील,** नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय, कतर द्वारा

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द डिजिटल डबल बाइन्ड के कवर का एक हिस्सा।

अरब मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए नए रास्ते खोल रहा है। चाहे वह ई–गवर्नमेंट, टेलीहेल्थ या ई–कोर्ट को अपनाना हो, डिजिटल कायापलट एक विघटनकारी शक्ति रही है, जिसने लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं को बदल दिया है और उन क्षेत्रों को फिर से जीवंत कर दिया है जिन्हें बदलाव के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। राइड–हेलिंग ऐप कैरीम जैसे सफल क्षेत्रीय स्टार्टअप, नियोम जैसी महत्वाकांक्षी हाई–टेक शहरी विकास परियोजनाएँ और वन मिलियन अरब कोडर्स जैसी भव्य पहल डिजिटल चीजों का लाभ उठाने के क्षेत्र के प्रयासों का प्रमाण हैं। क्षेत्र के अधिक देश डिजिटल तत्परता प्राप्त करने, व्यापक डिजिटल योजनाएँ तैयार करने और विभिन्न पहल शुरू करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे (जैसे, उपग्रह, फाइबर ऑप्टिक्स, अगली पीढ़ी के नेटवर्क) में निवेश करके ज्ञान अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए काम कर रहे हैं।

> क्षेत्रीय असमानताएँ और अंतर्निहित तनाव

लेकिन मध्य पूर्व ने अभी तक इस डिजिटल का समान रूप से अनुभव नहीं किया है। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय असमानताएँ हैं, जहाँ कुछ देश डिजिटल परिवर्तन को पूरी तरह से अपना रहे हैं वहीं अन्य अभी भी पिछड़े हैं । प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच और डिजिटल साक्षरता के विभिन्न स्तर मौजूदा असमानताओं को बढ़ाते हैं, जिससे क्षेत्र के भीतर कई डिजिटल विभाजन पैदा होते हैं। ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि डिजिटल परिवर्तन केवल नई तकनीकों को अपनाने के बारे में नहीं है। इसमें तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के बीच जटिल अंतर्संबंध को नेविगेट करना शामिल है, जो मध्य पूर्व के परिवर्तन के बारे में सरल पूर्वानुमानों को खारिज करता है।

जबकि डिजिटल प्रगति अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है, वे अतिरिक्त चुनौतियाँ भी पेश करती हैं। मध्य–पूर्व की डिजिटल में

>>

मग्नता की चारित्रिक विशेषता परिवर्तन के लिए आतुरता और इसके प्रति प्रतिरोध के मध्य बढ़ता तनाव है। यह विसंगति क्षेत्र को एक दोहरे बंधन में फँसाती है, जिसमें डिजिटल तकनीकों को अपनाने से परिवर्तन बढ़ता है और साथ ही मौजूदा स्थिरता बनी रहती है। डिजिटलीकरण के वास्तविकता बनने की वही संभावनाएं कई आर्थिक खिलाड़ियों, सामाजिक कर्त्ताओं और राजनीतिक शासनों के लिए आशंका का स्रोत हैं क्योंकि वे डिजिटल दोहरे बंधन का सामना करते हैं, जो उन्हें डिजिटल क्षेत्र पर नियंत्रण करते हुए एक साथ तकनीकी क्षमताओं का दोहन करने के लिए मजबूर करता है।

इन जटिलताओं को समझने के लिए हमें बहस को इस बात से दूर ले जाना होगा कि लोग तकनीकों के साथ क्या करते हैं और राज्य, बाजार और सार्वजनिक डिजिटल मग्नता से उत्पन्न होने वाले मतभेदों और तनावों का पता लगाना होगा। डिजिटलिटी का विश्लेषण करने के बजाय, हमें सामाजिकता की जांच करनी चाहिए।

> आधुनिकीकरण और प्रतिरोध के मध्य

ऐतिहासिक रूप से, मध्य पूर्व का प्रौद्योगिकी के साथ संबंध आधुनिकीकरण (अल–असराना) और आधुनिकता से जूझने के प्रयासों (अल–हदाथा) के साथ जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक युग से लेकर आज तक, इस क्षेत्र ने तकनीकी परिवर्तन को अपनाया और उसका विरोध भी किया है। इस तरह की अस्पष्टता दर्शाती है कि तकनीकी अपनाने का संबंध जटिल सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता से कैसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब पर विचार करें। 1960 के दशक में टेलीविजन की शुरूआत के प्रति राज्य का प्रतिरोध और 1990 के दशक में इंटरनेट को अपनाने के प्रति उसकी आशंका, टेलीविजन उद्योगों के स्वामित्व में अग्रणी होने और ट्रांसनेशनल सैटेलाइट चौनलों और संपन्न गेमिंग स्टूडियो से लेकर वैश्विक डिजिटल निवेश और घरेलू स्टार्टअप तक एक मजबूत डिजिटल मीडिया क्षेत्र को बढ़ावा देने के उसके प्रयास से ही मेल खाती है।

हमेशा से ही, प्रौद्योगिकी को अपनाने से चुनौतियाँ भी आई हैं। नए स्वतंत्र राज्यों के लिए, तकनीकी निर्भरता पर चर्चाओं का आगमन पश्चिमी प्रभाव और शक्ति के खिलाफ एक रैली का नारा था, जो इस अहसास के साथ था कि पश्चिमी तकनीक तक पहुँच उनके आधुनिकीकरण प्रयासों और विकास योजनाओं में प्रमुखता से शामिल थी। उच्च औद्योगीकरण के वर्तमान युग में, आर्थिक दबाव, तेज बदलाव और तेज शहरीकरण ने, क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के हस्तांतरण को और अधिक दबावपूर्ण बना दिया है।

इस तरह के विकास पथ की अपील तब भी बनी हुई है जब तकनीक खुद विकसित हुई है। हाल के दशकों में, वैश्वीकरण की पूरी ताकत और डिजिटल पूंजीवाद के आगमन के साथ, आधुनिकीकरण की खोज ने पारंपरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। इस विकसित संदर्भ में, ज्ञान अर्थव्यवस्था को अपनाना आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने की पहचान बन गया है।

> साझा आकांक्षाएँ और असमान विकास

हालाँकि, व्यवहार में, ये प्रयास बेहतरीन रूप में भी असमान हैं। जबकि कुछ देश (जैसे, यमन, सूडान, सीरिया) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना और डिजिटल तत्परता के मामले में स्पष्ट रूप से कमजोर हैं, अन्य (जैसे, खाड़ी देशों) ने डिजिटल को पूरे दिल से अपनाया है, और अगली पीढ़ी के नेटवर्क में निवेश किया है साथ ही स्मार्ट शहरों का निर्माण किया है। जहाँ कुछ देश (जैसे, यूएई, कतर और सऊदी अरब) वैश्विक डिजिटल प्रदर्शन और तत्परता चार्ट पर प्रमुखता से दिखाई देते हैं और डिजिटल पावरहाउस के रूप में उभर रहे हैं, वहीं इंटरनेट के शुरुआती अपनाने वाले क्षेत्र (जैसे, ट्यूनीशिया) डिजिटल परिवर्तन के मामले में पिछड़ रहे हैं। इस बीच, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रतिभा (जैसे, जॉर्डन) में समृद्ध माने जाने वाले मध्य पूर्वी देश क्षेत्रीय डिजिटल/आईटी हब के रूप में विकसित नहीं हुए हैं।

हालांकि खराब अवसंरचना अक्सर कम आर्थिक सूचकांकों औरध्या प्रतिबंधात्मक राजनीतिक संस्कृतियों से जुड़ी होती है, परन्तु ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए, केवल बुनियादी ढांचे, आर्थिक या राजनीतिक चर के आधार पर डिजिटल की टाइपोलॉजी पर विचार करने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों सहित विभिन्न कारक किसी देश के डिजिटल परिदृश्य और तत्परता को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। इसलिए, व्यापक विश्लेषण और प्रभावी नीति निर्माण के लिए सूक्ष्म समझ आवश्यक है।

> डिजिटल का व्यापक रूप

यहाँ तक कि जहाँ कमियों को दूर किया जा रहा है, मध्य पूर्व की डिजिटल मग्नता, परिवर्तन के लिए बढ़ते आवेग और उसी परिवर्तन के प्रतिरोध के बीच तनाव में फँसी हुई है। यह डिजिटल दोहरी बाधा है जिसमें यह क्षेत्र फँसा हुआ है। जहाँ डिजिटल तकनीकों को अपनाना और स्वीकार करना राज्य, बाजार और जनता को डिजिटल मग्नता के क्षेत्र में ले जाता है, वहीं इस तरह का प्रयास विरोधाभासी रूप से क्षेत्र को पर्याप्त परिवर्तन के लिए गति प्राप्त करने से रोकता है, जिससे स्थिरता की स्थिति बनी रहती है।

प्रभावी रूप से, राज्य अपने नागरिकों से इंटरनेट को दूर रखते हुए डिजिटल को अपनाते हैं। वे ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं को तो विकसित करना चाहते हैं जो नवाचार और रचनात्मकता पर पनपती हैं, परन्तु विशेषाधिकार और अधिकार के आधार पर ग्राहकवादी आर्थिक प्रणालियों को त्यागने से इनकार करते हैं। वे एक पदानुक्रमित, जोखिम–विरोधी व्यवसाय संस्कृति को बनाए रखते हुए स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

फिर भी, इन जटिलताओं के बीच, यह पहचानना आवश्यक है कि परिवर्तन और स्थिरता परस्पर अनन्य नहीं हैं। मध्य पूर्व के विकास पथ की विशेषता निरंतरता और परिवर्तन दोनों है, जो तकनीकी प्रगति और स्थापित सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता के बीच जटिल अंतर्क्रिया को दर्शाता है। ■

सभी पत्राचार मोहम्मद जयानी को <mz92@georgetown.edu> एवं जो एफ. खलील को <jkhalil@northwestern.edu> / ट्विटर : @JoeKhalil पर प्रेषित करें।

> गाजा शिक्षाविदों द्वारा खुला पत्र

गाजा से शिक्षाविदों द्वारा*

अपने चौथे दिन, 21 अप्रैल, 2024 को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पुनः स्थापित गाजा सॉलिडेरिटी कैंप । फोटो : विकिमीडिया कॉमन्स।

हमें मिटाने के सभी मौजूदा प्रयासों के मद्देनजर फिलीस्तीनी शिक्षाविदों और गाजा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के रूप में हम अपने अस्तित्व, अपने सहकर्मियों और अपने छात्रों के अस्तित्व तथा अपने भविष्य पर जोर देने के लिए एक साथ आए हैं ।

इजरायली सेनाओं ने हमारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय जीवित हैं। हम अपनी भूमि पर बने रहने और गाजा में अपने स्वयं के फिलीस्तीनी विश्वविद्यालयों में जल्द से जल्द शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान फिर से शुरू करने के अपने सामूहिक दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं।

हम दुनिया भर में अपने दोस्तों और सहकर्मियों से आह्वान करते हैं कि वे कब्जे वाले फिलिस्तीन में चल रहे विद्वानों के संहार के अभियान का विरोध करें, हमारे ध्वस्त विश्वविद्यालयों के पुनर्निर्माण में हमारे साथ काम करें और हमारे शैक्षणिक संस्थानों की अखंडता को दरकिनार करने, मिटाने या कमजोर करने की सभी योजनाओं को अस्वीकार करें। गाजा में हमारे युवाओं का भविष्य हम पर और हमारे लोगों की आने वाली पीढ़ियों की सेवा जारी रखने के लिए अपनी भूमि पर बने रहने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।

हम यह आह्वान कब्जा किये गए गाजा में सेनाओं के बमों के नीचे से, रफाह के शरणार्थी शिविरों से, और मिस्र एवं अन्य मेजबान देशों में नए अस्थायी निर्वासन स्थलों से जारी कर रहे हैं। हम इसे ऐसे समय में प्रसारित कर रहे हैं जब इजरायली सरकार हमारे लोगों के खिलाफ प्रतिदिन नरसंहार अभियान चला रही है, तथा हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू को समाप्त करने का प्रयास कर रही है।

हमारे परिवारों, सहकर्मियों और छात्रों की हत्या की जा रही है। हम एक बार फिर बेघर हो गए हैं और 1947 और 1948 में जायोनी सशस्त्र बलों द्वारा नरसंहार और सामूहिक निष्कासन के दौरान अपने माता–पिता और दादा–दादी के अनुभवों को फिर से जी रहे हैं।

हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे – विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र – जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाये गए थे, इस जानबूझकर हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे – विश्वविद्यालय, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र – जो हमारे लोगों की पीढ़ियों द्वारा बनाए गए थे, इस जानबूझकर के निरंतर नकबा से खंडहर में पड़े हैं। हमारे शैक्षिक बुनियादी ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाना गाजा को निर्जन बनाने और हमारे समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने–बाने को नष्ट करने का एक जबरदस्त प्रयास है। हालाँकि, हम इस तरह के कृत्यों को हमारे भीतर जलती हुई ज्ञान और लचीलेपन की लौ को बुझाने की अनुमति नहीं देंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में इजरायल के कब्जे के सहयोगी कथित पुनर्निर्माण योजनाएं, जो गाजा में स्वतंत्र फिलिस्तीनी शैक्षिक जीवन की संभावना को खत्म करना चाहती हैं, को बढ़ावा देकर एक और शैक्षणिक हत्या का मोर्चा खोल रहे हैं। हम ऐसी सभी योजनाओं को अस्वीकार करते हैं और अपने सहयोगियों

> >

से उनमें किसी भी तरह की मिलीभगत से इनकार करने का आग्रह करते हैं। हम दुनिया भर के सभी विश्वविद्यालयों और सहयोगियों से भी आग्रह करते हैं कि वे हमारे विश्वविद्यालयों के साथ किसी भी शैक्षणिक सहायता प्रयासों का सीधे समन्वय करें।

हम उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रति हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं जो इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे साथ एकजुटता में खड़े रहे हैं, और समर्थन और सहायता प्रदान कर रहे हैं। हालाँकि, हम गाजा में फिलिस्तीनी विश्वविद्यालयों को प्रभावी ढंग से फिर से खोलने के लिए इन प्रयासों के समन्वय के महत्व पर जोर देते हैं।

न केवल वर्तमान छात्रों का समर्थन करने के लिए, बल्कि हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की दीर्घकालिक लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी, हम गाजा के शिक्षा संस्थानों को फिर से संचालित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने का एक साधन नहीं हैय यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और फिलिस्तीनी लोगों के लिए आशा की किरण है।

तदनुसार, बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और विश्वविद्यालयों की संपूर्ण सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना आवश्यक है। हालाँकि, ऐसे प्रयासों के लिए काफी समय और पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों को संचालित बनाए रखने की क्षमता पर जोखिम पैदा होता है, और संभावित रूप से कर्मचारियों, छात्रों और पुनः संचालन करने की क्षमता का नुकसान होता है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, भौतिक अवसंरचना के विनाश से होने वाले व्यवधान को कम करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण की ओर बदलाव करना अनिवार्य है। इस बदलाव के लिए अकादमिक कर्मचारियों के वेतन सहित परिचालन लागतों को कवर करने के लिए व्यापक समर्थन की आवश्यकता है।

नरसंहार की शुरुआत के बाद से विश्वविद्यालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत, छात्र शुल्क में भारी गिरावट आई है। आय की कमी ने कर्मचारियों को वेतन विहीन कर दिया है, जिससे उनमें से कई बाहरी अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की आजीविका पर प्रहार करने के अलावा, जानबूझकर चलाए जा रहे शैक्षणिक–हत्या अभियान के कारण उत्पन्न यह वित्तीय तनाव स्वयं विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए एक अस्तित्वगत खतरा बन गया है।

इस प्रकार, शैक्षणिक संस्थानों के सामने मौजूद वित्तीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए, ताकि उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। हम सभी संबंधित पक्षों से इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के समर्थन में अपने प्रयासों को तुरंत समन्वित करने का आह्वान करते हैं।

गाजा के शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्निर्माण केवल शिक्षा का मामला नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

गाजा में उच्च शिक्षा का भाग्य गाजा के विश्वविद्यालयों, उनके शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों तथा समग्र रूप से फिलिस्तीनी लोगों का है। हम इस चल रहे नरसंहार को समाप्त करने के लिए दुनिया भर के लोगों और नागरिकों के प्रयासों की सराहना करते हैं।

हम अपनी मातृभूमि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने सहयोगियों से आह्वान करते हैं कि वे हमारे लोगों के भविष्य और गाजा में हमारी फिलिस्तीनी भूमि पर बने रहने की हमारी क्षमता के लिए हमारे विश्वविद्यालयों की रक्षा और संरक्षण के हमारे दृढ़ प्रयासों का समर्थन करें। हमने इन विश्वविद्यालयों को टेंट से बनाया है। और अपने दोस्तों के समर्थन से, हम इन्हें टेंटों से एक बार फिर से बनाएंगे। ■

*इस पत्र पर गाजा के 185 शिक्षाविदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं की पूरी सूची यहाँ देखें: https://www.aljazeera.com/opinions/2024/5/29/open-letter-by-gaza-academics-and-university-administrators-to-the-world

ISA PUBLICATIONS

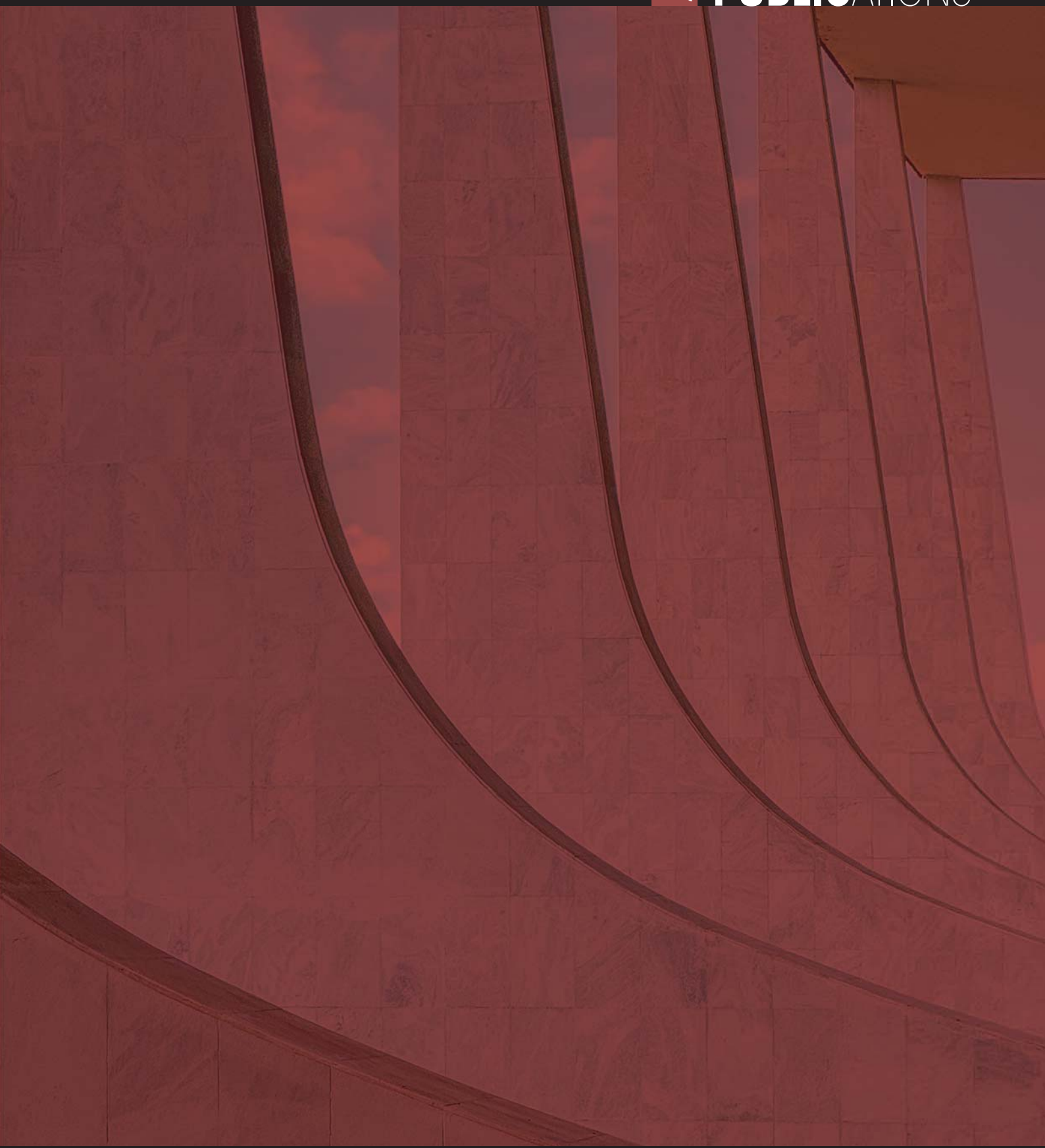

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org